असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा 27 मार्च, 2017 ई0

---------- सोमवार, तिथि----------

पंचम सत्र 06 चैत्र, 1939(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, बिजली दर में काफी बढ़ोत्तरी हो गयी है...

अध्यक्ष : बिजली के बारे में सरकार तो कह चुकी है कि वह सदन को सूचित करेगी । अभी आप क्या कहना चाहते हैं ? अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री नंद किशोर यादव । प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री नंद किशोर यादव जी ने प्रश्न पूछा है, गृह मंत्री जवाब दीजिए ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-24(श्री नंद किशोर यादव)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1-वस्तुस्थिति यह है कि जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक पटना जिला में लापता बच्चों की संख्या-656 है, जिसमें 443 बच्चों का पता लगाया जा चुका है । शेष 213 बच्चों की बरामदगी हेतु कांड अनुसंधानान्तर्गत है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अधिकतर लापता बच्चों, जिनकी वापसी/बरामदगी हो चुकी है, द्वारा अपनी मर्जी से घर वाले को बिना बताये स्वयं घर से चले जाने की बात बतायी गयी है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि लापता बच्चों की बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाकर, कांड दर्ज कर बच्चों की विवरणी फोटो सहित trackthemissingchild.gov.in वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है । तलाश और बच्चों की सुरक्षा के लिए जिलास्तरीय किशोर न्याय के नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में मानव-व्यापार निरोध इकाई कार्यरत है । इसके अतिरिक्त जिला के प्रत्येक थाना में थानाध्यक्ष/ वरीय पुलिस अवर निरीक्षक को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है । राज्यस्तर पर कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग , बिहार, पटना नोडल एजेंसी के रूप में नामित है तथा समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश, एस0ओ0पी0 निर्गत किया जाता है ।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खंड-2 का कोई उत्तर ही नहीं दिया ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि स्वयं बच्चे भागते हैं जो रिकोवरी हुई है, उसमें जो जांच प्रतिवेदन आया है, वह स्वयं बिना माता-पिता, घर को बताये विभिन्न जगहों पर चले जाते हैं, जिसकी रिकवरी के बारे में, मैंने यह बात बताया ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत भ्रामक है और तथ्य से परे है और सरकार का रेकर्ड इस बात का गवाह है कि बड़े पैमाने पर मानव तस्कर इस काम में लगे हैं और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ । महोदय, 25 दिसम्बर, 2016 को पटना सिटी के मालसलामी थाने से दो बच्चे लापता हो गये । उसमें से एक बच्ची 80 दिनों के बाद यू0पी0 के आगरा से बरामद हुई और उसने यह बात बतायी । तीन बार उस बच्ची को बेचा गया । जो दूसरी बच्ची है उसकी हत्या हो गयी एटा में तो महोदय ये जो कह रहे हैं कि केवल भाग जाते हैं बच्चे, यह सत्य से परे है महोदय । खुद बच्ची ने बताया है कि उसको नौकरी का झांसा देकर फिरोजाबाद ले गये और वहां उनको तीन बार बेचा गया तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस गंभीर विषय को इतने हल्के ढ़ंग से सरकार क्यों लेना चाहती है ? जबकि इसमें बड़े पैमाने पर मानव तस्कर शामिल हैं और आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि केवल पटना जिला के जो आंकड़े आपके सामने आये हैं, महोदय, माननीय मंत्री जी खुद भी स्वीकार किया है कि 656 लोग लापता हो गये और अभी-भी 213 बरामद नहीं हुए हैं । तो महोदय, सरकार यह मान लेगी कि बच्चे अपनी मर्जी से चले गये हैं तो इसका समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार बड़े पैमाने पर जो मानव तस्कर सक्रिय हैं पटना जिला के अन्दर और पूरे बिहार में, उन मानव तस्करों के खिलाफ कोई सघन कार्रवाई चलाकर उसके नेटवर्क को समाप्त करना चाहती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि झांसा देकर नौकरी के नाम पर ले गये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिना परिवार को बताये वह गायब होते हैं, जो रिकोवरी हुई है, उसमें यह बातें आयी है । जहां तक माननीय सदस्य ने इंगित किया है, वैसे भी तस्कर जब पकड़े जाते हैं तो उनपर कार्रवाई होती है । ऐसी बातें नहीं है, और भी ऐसे मामले आयेंगे तो इन बातों पर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा है कि एक अभियान चलाकर ऐसे मामलों में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है महोदय ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय,

अध्यक्ष : अब तो मान लिया ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, कैसे मान लिया ? महोदय, मूल विषय यह है और भी आंकड़े देखिए । आज एक समाचार-पत्र में, दैनिक समाचार पत्र में आंकड़े छपे हैं, जिसमें पूरे बिहार के, यह नेशनल क्राइम व्यूरो का आंकड़ा है, उसका रेकर्ड आंकड़ा है, उसके अनुसार 3,037 लड़कियां गायब हो गयी 2016 में और उसमें से 1587 लड़कियों के अलग तरह के कारण हैं, लव अफेयर, बाकी कारण हैं, जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा उसको मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन बाकी बच्चियों का क्या हुआ ? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी बच्चियां गरीब परिवार की है । महोदय, एक आंकड़ा और है जनवरी 2013 से जनवरी 2014 के बीच में 2674 गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए और उसमें से 633 लड़कियां अभी-भी नहीं मिली है महोदय । तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर मंत्री महोदय के मन में यह बात बैठी है और सरकार अगर यह सोचती है कि केवल लड़के और लड़कियां चले जाते हैं ऐसे तो यह धाारणा ही गलत है महोदय । 633 लड़कियां अभी तक बरामद नहीं हुई है तो इसका अर्थ साफ है कि लड़कियों को बेचा जा रहा है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है । हमारे बच्चे-बच्चियां, बेटे और बेटियां के साथ बिहार के अन्दर बड़े पैमाने पर लगातार घटनायें घट रही है । मैं वर्ष 2014 का आंकड़ा दे रहा हूँ और 2016 का आंकड़ा आपके सामने है।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, उसके बावजूद सरकार इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है ? महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकार कौन सा कदम उठाना चाहती है ?

अध्यक्ष : आपने जो कहा कि .....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ, पांच साल तक के बच्चे मिसिंग है 6, जिसमें ट्रेस किये गये 4 और अनट्रेस हैं 2 और लड़कियों में 3, जिसमें ट्रेस किये गये 1 और अनट्रेस है 2 । 6 से 14 साल, यह गौर करने का विषय है लड़के 90, ट्रेस किये गये 66, अनट्रेस है 24, लड़कियां 147, ट्रेस हो गये 102 और अनट्रेस है 45 । 15 से 18 वर्ष, लड़के में 85, ट्रेस हुए 55 और अनट्रेस है 30, लड़कियों में 325, ट्रेस हो गये 215 ...

अध्यक्ष : वह समेकित आंकड़ा तो उपलब्ध ही है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, गंभीर विषय यह है कि छोटे बच्चे नहीं, जो सम एक्सटेंट तक एडल्ट बच्चे-बच्चियां जो हैं, उसके गायब होने की जो रिपोर्टिंग है, वह होशियार लोग हैं, चिल्ला भी सकते हैं कि हमको फलानां ले जा रहा है, यह प्रोबलम है महोदय और मैंने जैसा जिक्र किया कि हरेक जिला में अपराध अनुसंधान विभाग नोडल एजेंसी के रूप में नामित है और सभी जिले में एक इन्सपेक्टर, एक दारोगा थाने में

इसके लिए नामित किये गये हैं और टाईम-टू-टाईम इन्स्ट्रक्सन भी दिया जा रहा है और अभियान भी चलाया जा रहा है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, तीन क्वेश्चन पूछने का आपने अधिकार दिया है ...

अध्यक्ष : हम अधिकार की बात नहीं कह रहे हैं । कह रहे हैं कि इसमें अब कोई बात बच नहीं गयी है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, बच गयी है, बहुत बात बची हुई है । कुछ हुआ ही नहीं महोदय ।

अध्यक्ष : हुआ तो यही कि आपने पूछा कि सरकार विशेष अभियान चलाना चाहती है तो सरकार ने कहा कि चलायेंगे । आपका पहला ही पूरक सरकार ने स्वीकार किया है, अब क्या होना है? आप जो चाहते हैं, सरकार ने उसको किया है ।

श्री नंद किशोर यादव : नहीं महोदय ।

अध्यक्ष : आपने जो कहा है उसको सरकार ने माना है ।

श्री नंद किशोर यादव : नहीं महोदय । सरकार लीपापोती करना चाहती है ।

अध्यक्ष : सरकार लीपापोती नहीं करना चाहती है । आप पूरक पूछिए ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाईड लाईन जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार जब बच्चे की गुमशुदगी होती है तो पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज किया जाता है । सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था सरकार को कि 24 घंटे के अन्दर इसको एफ0आई0आर0 में तब्दिल करना है लेकिन बिहार के अन्दर यह काम नहीं हो रहा है । महोदय, खुद डी0आई0जी0, सारण ने इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार के अन्दर हर वर्ष चार हजार बच्चे ट्रेफिकिंग के शिकार हो रहे हैं । मेरा कहना यह है कि जब लगातार यह घटनायें घट रही है और सरकार ने कहा है कि हमने व्यवस्था किया है, थाना में इसके लिए आदमी को अधिकृत किया है, अलग से सेल बनाया गया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि विगत तीन वर्षों के अन्दर इस प्रकार के मानव तस्करी के आरोप में कितने लोग बिहार के अन्दर गिरफ्तार हुए और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने जो आकड़े दिये हैं और जो एफ0आई0आर0 हुए हैं, उसी के आधार पर रिकोवरी के बारे में बताया । अनट्रेस भी जो मैंने बताया, अपने मन से कोई बातें गवर्नमेंट के पास आती नहीं है । एक घटना कल की मैं बता रहा हूँ कि हमलोगों के पार्टी के नेता छातापुर से आये, मैं इसी प्रश्न को देख रहा था, कहा कि एक लड़का को माँ ने डांटा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गया आज, मारा भी एक थप्पड़ , अब वह गायब हो गया, पूरा गांव तबाही में था, अन्ततोगत्वा हरियाणा में उसका बाप

था, बाप ने फोन किया कि चिन्ता करने की जरूरत नहीं है । दिल्ली में हम जा रहे थे तो रास्ते में मिल गया । सर, तो इस तरह की बातें होती हैं ।

टर्न–2/शंभु/27.03.17

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, बच्चे गायब होने की बात नहीं है, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अन्तर्गत कितने लोग गिरफ्तार किये गये, बताइये। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, केवल बच्चों के गायब होने की कहानी बता रहे हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : आदत आपकी खराब हो गयी है।

श्री नन्दकिशोर यादव : आपकी आदत खराब है, आपके सरकार की आदत खराब है, मुद्दा को हल्का करना चाहते हैं आप।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जब यहां थे तो बड़ा शान्त भाव से थे, अब थोड़ा छपास की बीमारी हो गयी है, अब बतकट्टी ज्यादा करने लगे हैं।

श्री नन्दकिशोर यादव : छपास के लिए आपके सहयोग की जरूरत नहीं है– भगवान ने हमको इतनी ताकत दी है, इतनी ऊर्जा दी है कि छपने के लिए आपके सहायता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने काम की बदौलत छपते हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैं तो आपकी ताकत को चुनौती दे नहीं रहा हूँ।

श्री नन्दकिशोर यादव : दे भी नहीं सकते हैं आप।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : कभी जब यहां नहीं रहेंगे तो आप ही के यहां नौकरी की तलाश में आयेंगे तो आप ही मदद कीजिएगा।

श्री नन्दकिशोर यादव : आपको मेरी ताकत का अहसास बार–बार होता रहा है। आपको मेरी ताकत का अहसास होता है इसलिए चुनौती दे भी नहीं सकते हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : लेकिन जरा उत्ततेजना बढ़ गयी है, अब उसमें हमलोगों का कोई दोष नहीं है।

श्री नन्दकिशोर यादव : ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताइये न कि कितने लोग पकड़े गये ? कितने मानव तस्कर पकड़े गये।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अब यहां से लोगों ने वहां बैठा दिया।

अध्यक्ष : अब दोनों आदमी प्रश्न पर आ जाइये।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अब ये गलथेथरी कर रहे हैं तो हम क्या करें ? महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा है उसको मुस्तैदी से दिखाया जायेगा और माननीय सदस्य को अगर इस तरह की कोई सूचना उपलब्ध हो तो वह सूचित करें, इम्मीडियेट कार्रवाई की जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0–9, श्री अजीत शर्मा, उद्योग विभाग। अब कितना पूरक इसपर पूछेंगे ? इसमें कोई नयी बात तो आनेवाली नहीं है। चलिए, बैठिए। अंतिम पूरक पूछ लीजिए।

श्री प्रेम कुमार, ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, बहुत साफ पूछा गया है बात को– मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य नन्दकिशोर जी ने उठाया है कि तीन वर्षों में ट्रैफिकिंग मामले में ऐसे कितने गिरोहों को पकड़ा गया, बहुत ही स्पष्ट सवाल है, बताइये कितने लोगों को पकड़ा है, कितने पर कार्रवाई की है। लड़के कुछ वापस आ गये, मान लिया जाय, लेकिन जो इसमें ट्रैकिंग हुआ है, बड़ी संख्या में गिरोह सम्मिलित है, बच्चों की तस्करी में गिरोह सम्मिलित है अवैध कारोबार में, ऐसे कितने लोगों पर गिरोहों पर आपने कार्रवाई की है, इसका जवाब दे दीजिए आप।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इस बात को गंभीरता से देखवा लिया जायेगा और समीक्षा की जायेगी।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं0–9(श्री अजीत शर्मा)

श्री जयकुमार सिंह,मंत्री : महोदय, 1– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2008 को खादी वस्त्रों के उपयोग के संबंध में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्थित मरीजों की शैय्या हेतु सात दिनों के लिए अलग–अलग सात रंगों की चादर आपूर्ति की जाय ताकि सातों दिन चादर बदलने की जॉच आसानी से हो सके। जिसपर खादी तथा हैंडलूम की चादर की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया तथा इसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि खादी एवं हैंडलूम की चादर की आपूर्ति करने हेतु बिहार राज्य खादी बोर्ड नोडल एजेन्सी होगा।

2– अस्वीकारात्मक है। भागलपुर जिला में दो प्रकार के लूम उपयोग किया जा रहा है। पहला हस्तकरघा या हस्तचालित है, दूसरा विद्युत करघा या मोटरचालित है। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हस्तकरघा पर बने हुए सात रंग के चादर की आपूर्ति करने का आदेश बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्र नगर पटना को दिया गया है। जो सीधे स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालों को चादर आपूर्ति करता है। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ समिति, राजेन्द्र नगर, पटना के पत्रांक–117, दिनांक 07.03.2017 द्वारा भागलपुर जिला के सतरंगी चादर बुनाई करनेवाले कार्यरत बुनकरों की समिति का नाम एवं लूम संख्या की सूची उपलब्ध करायी गयी है। जो इस प्रकार है। क्रम सं0–1, मिरजा फरीद, ताती नं0–2, बुनकर संख्या संघ लि0 भागलपुर, यहां 12 लूम की संख्या है। दूसरा कमालचक, मुस्तफापुर, बुनकर संघ लि0 पुरैनी, भागलपुर। राजा सिल्क प्रा0 बुनकर संघ, शाहजंगी, हबीबपुर– हबीबपुर में 14

है। दरियापुर बुनकर संघ लि0, भागलपुर में 11 है। मिरनचक बुनकर संघ, भागलपुर में 7 है। महोदय, कुल 55 लूम की संख्या है।

3- कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब पूर्णरूपेण नहीं आया। मेरा कहना है कि वहां लाखों बुनकर भागलपुर में हैं और उनकी स्थिति बहुत बदतर है। वे लोग जो चादर बनाते हैं पहले हाथ से बनाते थे, अब भी कुछ लोग हाथ से बनाते हैं और कुछ लोग मोटर से बनाते हैं। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हाथ से बनाये हुए लिये जाते हैं। मेरा सवाल है कि हाथ से बना रहे हैं या मोटर से क्या सरकार चादर जो बुनकर की स्थिति खराब हो गयी है, गरीब अभी मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं क्या उनकी स्थिति सुधारने के लिए जो मोटर लगाकर कपड़े तैयार कर रहे हैं क्या वह चादर सरकार खरीदने का नियम बनायेगी ? दोनों को डिवाइड कर दें हाथ से चलानेवाले का और मोटर से चलाने वाले का, क्या सरकार विचार रखती है कि उनसे खरीदी जायेगी ?

श्री जयकुमार सिंह,मंत्री : महोदय, एक तो उद्योग विभाग बाजार उसको उपलब्ध कराने का ये कोई साधन नहीं है, लेकिन एक संकल्प हमलोगों ने लिया था 2007-08 में कि यदि सरकार की कोई रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट का 15 परसेंट हमारे यहां बना हुआ उद्योग को लिया जायेगा। महोदय, हम इसमें मदद करना चाहते हैं कि ये एक स्वास्थ्य विभाग के चादर का था तो यूजर डिपार्टमेंट ही इसका टेंडर निकालता है। हम तो सिर्फ मोनेटरिंग करते हैं, एक निर्णय लिया गया कि हस्तकरघा पर ही आधारित हम चादर लेंगे। हम उसकी मोनेटरिंग करते हैं चूंकि स्वास्थ्य विभाग इसका टेंडर निकालता है और उनको जो-जो सहयोग की आवश्यकता पड़ती है कि हस्तकरघा का ये है कि नहीं, भारत सरकार की एक एजेन्सी है.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य का प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो मैनुअली चलता है हैंडलूम उसी का लिया जाता है, जिस हैंडलूम का मशीनीकरण हो गया है उसके द्वारा उत्पादित चादर नहीं लिया जाता है। माननीय सदस्य का कहना है कि उसको भी लेने की अनुमति होनी चाहिए। इसलिए अपना जवाब इसी बिन्दु तक केंद्रित कीजिए।

श्री जयकुमार सिंह, मंत्री : महोदय जब ये बना था 2008 में तो इसकी एक नोडल एजेन्सी बनायी गयी थी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को और उसका उद्देश्य यही था कि बुनकरों को एक रोजगार जो लगे हुए हैं उनको एक बाजार मिले। हम तो उसके सहयोग में हैं, अब चूंकि हस्तकरघा पर ही आधारित 2016 में एक निविदा निकाला गया और निविदा में एल0-1 हुआ- यहां की जो उसकी समिति के संघ हैं जो राजेन्द्र नगर में है, उनको दिया गया है और उनको यह पहले हस्तकरघा का है कि नहीं पहले तो यही निर्णय है और भविष्य में यदि बातें मोटरचालित का होगा तो हमलोग उसपर विचार करेंगे।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बतायेगी कि 2007-08 के निर्णयानुसार जो चादरें स्वास्थ्य विभाग को खरीदनी थी क्या उसके अनुरूप स्वास्थ्य विभाग खरीदी है ? यह सुनिश्चित उद्योग विभाग किया है?

अध्यक्ष : उद्योग विभाग इसका जवाब कैसे देगा ?

श्री सदानन्द सिंह : सरकार का सामूहिक दायित्व है, मंत्रिमंडल का निर्णय है, विभाग ने निर्णय नहीं लिया, मंत्रिमंडल का निर्णय है। उसके अनुरूप या तो स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में पूछवाइये। कैसे इस बात को सुनिश्चित हम करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदानन्द बाबू, तब तो अधिक से अधिक यही न हो सकता है कि इस प्रश्न को स्वास्थ्य विभाग को भेजा जायेगा।

श्री सदानन्द सिंह : हां, फिर भेजिए।

अध्यक्ष : यह भले मंत्रिपरिषद् का निर्णय हो, लेकिन उस निर्णय का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह उद्योग विभाग कैसे जवाब देगा ?

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, तब तो यह आधा अधूरा रहा न ? या नहीं तो प्रश्नकर्त्ता सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह खरीदी जा रही है कि नहीं।

श्री जयकुमार सिंह,मंत्री : महोदय, अब इसका हमारा काम था कि इसको कैसे सुनिश्चित किया जाय, इसकी हस्तकरघा पर है कि नहीं- जो जो स्वास्थ्य विभाग हमसे सहायता मांगता है वह हम देते हैं। भारत सरकार की टेक्सटाइल कंपनी जो कलकत्ता में अवस्थित है। वह यह देखती है, जॉच करती है कि हस्तकरघा, हैंडलूम का यह है कि नहीं और हम उनको दिये हैं तो यह सुनिश्चित कराने के लिए उसमें कोई गड़बड़ी न हो इसलिए हम हमेशा उनकी हेल्प करते हैं और उसके रेट के निर्धारण में भी एक जो कमिटी बनी हुई है, बजाप्ते उसके रेट का निर्धारण किया गया है तो जहां भूमिका होती है उद्योग विभाग की वहां भूमिका हम करते हैं।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है। क्रमशः

टर्न-3/अशोक/27.03.2017

श्री सदानन्द सिंह : क्रमशः अध्यक्ष महोदय, आप ज्यादातर अस्पतालों में जाते होंगे स्वयं देखते हेांगे कहीं भी, खादी ग्रामोद्योग की चादर बहुत कम मिलती है, यह सरकार का जो निर्णय है वह कार्यान्वित नहीं हो रहा है, यह हम कह रहे हैं ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : अब आपका समय चला गया । आप उस समय दो पूरक पूछ चुके हैं ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, यह प्रश्न मूल रूप से स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया था और माननीय मंत्री महोदय ने जो अभी जवाब दिया है, बड़ा स्पष्ट जवाब है कि स्वास्थ्य विभाग ही मानक तय करता हैं कि किस प्रकार की चादर की आवयकता

हैं जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब उद्योग विभाग दे भी नहीं सकता हैं महोदय तो आखिर किस स्थिति में स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया कि हमारे विभाग का मामला नहीं है, इसको क्यों ट्रांसफर के लिए आग्रह किया ? मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले को टाला जा रहा है और इसको स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर करिये और स्वास्थ्य इस बात का जवाब दे कि जो मानक उसने तय किया हैं उसमें मोटर चालित हैण्डलूम का मानक तय करेगा कि नहीं करेगा, यह जवाब उसको देना चाहिए ।

अध्यक्ष : इसमें माननीय मंत्री जी, आप जैसा बतला रहे हैं, आप सिर्फ यह देखते हैं कि चादर हैण्डलूम से बना हुआ है कि नहीं । यही देखते हैं न ?

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : जी, जी । इसमें महोदय, इसकी जांच के लिए हम ही नहीं देखते हैं चूंकि भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, भारत सरकार का एक टैक्सटाईल कम्पनी हैं ....

अध्यक्ष : मंत्री जी, कोई देखता है, आप देखिये या भारत सरकार देखती है, वह क्या देखती है ? यही न कि हैण्डलूम से बना हुआ है या नहीं ।

श्री विजय कुमार सिंह, मंत्री : हैण्डलूम से बना हुआ है कि नहीं । बिल्कुल ।

अध्यक्ष : बाकी चादर सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह तो स्वास्थ्य विभाग देखता है ।

श्री जय कुमार सिंह : बिल्कुल, ऑरिजनल डिर्पाटमेंट का काम है महोदय । वह हमारा काम है नहीं। यदि मोटर चालित के लिए कहता है तो मुझे क्या एतराज है ।

अध्यक्ष : यह स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित हुआ ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-34,श्री सरोज यादव ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में तो कहा गया है चादर खरीदने की बात, यह कहां है कि स्वास्थ्य विभाग या और हॉस्पीटल में चादर की आपूर्त्ति के बारे में ...

श्री नंद किशोर यादव : स्वास्थ्य विभाग ही चादर खरीदता है, यह आपको मालूम नहीं है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-34 (श्री सरोज यादव)</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अस्वीकारात्मक है । श्री मनोज यादव पिता श्री रामाशंकर यादव, श्रीमती सुशीला देवी पति श्री सरोज यादव के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र का निष्पादन कर दिया गया है ।

श्री सरोज यादव: अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करा ली जाय । मैं चार प्वांयट पर कुछ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री सरोज यादव : हां पूरक ही पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, चार प्वायंट पर । पहला प्वायंट मंत्री जी बतायें कि श्री मनोज कुमार यादव को पुलिस अधीक्षक, आरा के पत्रांक 804 दिनांक 5.8.2016 द्वारा तथा श्रीमती सुशीला देवी सहित कुल 22 व्यक्तियों को पुलिस अधीक्षक, आरा के पत्रांक 856 दिनांक 3.9.2016 द्वारा शस्त्र लाईसेंस निर्गत कये जाने हेतु आवेदन पत्र विधिवत् अग्रसारित किया गया था, दूसरा प्वायंट, तीन दिन के अंदर संचिकाओं का निष्पादन करने का सरकार का निर्देश है, परंतु शस्त्र लाईसेंस संबंधी संचिकाओं का निष्पादन करने में जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया गया है तो इसके लिये सरकार उनके विरूद्ध कौन सी कार्रवाई करेगी और कब तक करेगी ? तीसरा, जिला अधिकारी को जिला दंडाधिकारी की हैसियत से कोर्ट में सुनवाई कर शस्त्र लाईसेंस पर निर्णय लेना है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला दंडाधिकारी की हैसियत से वर्ष 2013 से अबतक कितनी बार जिला दंडाधिकारी, भोजपुर सहित पूरे जिला में कोर्ट में सुनवाई की गयी है और चौथा है अध्यक्ष महोदय, कि क्या सरकार को कोई जानकारी है कि मेरे ऊपर विधायक बनने के बाद जानलेवा हमला किया गया तथा मेरी बहन की हत्या कर दी गयी थी अध्यक्ष महोदय, और आज तक मेरा भी आवेदन उनके यहां लम्बित पड़ा है, क्या अध्यक्ष महोदय, क्या हमलोगों का मौलिक अधिकार नहीं होता है आत्म सुरक्षा का ? अध्यक्ष महोदय, मुझे इसका जवाब चाहिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 14.03.2017 को माननीय सदस्य का और 14.02 (14 फरवरी) एवं 21.02. (21 फरवरी) को यह निर्गत करा दिया गया है । इतना लम्बित क्यों रहा, इसको हम दिखलवा लेंगे ।

श्री सरोज यादव: अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है, बार-बार जिलाधिकारी से बात करने के बाद भी वो बोलते हैं कि हम कर देंगे, कर देंगे, किसी का भी निष्पादन नहीं हो रहा है, मेरे पूरे जिला. . .

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि निष्पादन हो गया है और अगर निष्पादन नहीं हुआ है तो आप मंत्री जी को सूचना दे दीजयेगा, वे जांच करा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1799(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, अंशत: अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि एस.एल.बी.सी. एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक औरंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 2013-14 एवं 2014-15 में कमश: वार्षिक लक्ष्य का 44 प्रतिशत एवं 71 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि 44 प्रतिशत, हमने पूछा है कि 40 प्रतिशत, 44 प्रतिशत ही किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूॅ कि पूरे बिहार में इस तरह के मामला है यह तो औरंगाबाद का जिक्र हमने किया है.....

अध्यक्ष : आप औरंगाबाद में नवीनगर विधान सभा के नवीनगर एवं बारूण प्रखण्ड का ही चर्चा किये हैं पूरक भी उतना ही तक सीमित रखियें, आप बिहार में कहां उलझ रहें हैं ?

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : नहीं, उलझ मैं नहीं रहा हूॅ , मै यह कह रहा हूॅ कि....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : पूरक पूछ रहा है कि क्या सरकार सुनिश्चित करायेगी कि क्रेडिट कार्ड शत-प्रतिशत मिले ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, सरकार तो चाहती है कि शत-प्रतिशत वितरण हो क्रेडिट कार्ड का मगर जहांतक बैंकों का सवाल हैं, बैंक सीधे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है और केन्द्र सरकार की चाहे जन कल्याणकारी योजना हो या राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना हो उसकी समीक्षा के लिए स्टेट लेभल पर एस.एल.बी.सी. का गठन है, डिस्ट्रीक्ट लेभल पर बैंकर्स समिति का गठन है, प्रखण्ड लेभल पर प्रखण्ड बैंकर्स समिति का निर्णय हैं । हमलोग एस.एल.बी.सी. की मिटिंग में बार-बार यह मामला उठाते हैं और बार-बार हमलोगों ने प्रयास किया है, केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री से कि बैंक अपना रवैया बदले, बैंक पर कुछ नियंत्रण और अंकुश होना चाहिए मगर वह नहीं हो पाया है तो एस.एल.बी. सी. की अगली जो बैठक होगी उसमें फिर हम इस पर दवाब बनायेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक । तारांकित प्रश्न संख्या-119, श्री तारकेश्वर प्रसाद । गृह विभाग ।
एक मिनट, क्या है माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी ?

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में 44 प्रतिशत और 2015 में 71 प्रतिशत, इन्होंने कहा है कि एस.एल.बी.सी. की मिटिंग भी हुई, फिर इन्होंने कहा है, हम यह जानना चाहते है माननीय वित्त मंत्री जी से, सिर्फ कहने से नहीं, राज्य सरकार कोई कठोर निर्णय लेकर बैकों पर दवाब देने का कोई निर्णय लेने का कोई फैसला करेगी ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य वरीय सदस्य हैं, बैंक पर सीधा नियंत्रण हमारा, राज्य सरकार का कुछ नहीं है हालांकि मैं तो अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे कि बैंक शाखा खोलने, बैंक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं यहां, वह तो समझिये हम जवाब देते हैं मगर बहुत निस्सहाय अपने को फिल करते हैं जहां तक एस.एल.बी.सी. की मिटिंग है एस.एल.बी.सी. की मिटिंग में उनको कई तरह

चूंकि उस कमिटी के चैयरमैन हम होते हैं, हमने कई तरह से उन पर दवाब बनाया हमने यहां तक कहा है कि जिन बैंकों का इन कार्यो के लिए 33 प्रतिशत प्वायंट को एचिभ नहीं करेंगे वहां हम अपने सरकार का पैसा जमा नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक ।

टर्न-4/ज्योति

27-03-2017

अध्यक्ष : ठीक है, तारांकित प्रश्न संख्या 119 श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री श्याम रजक : महोदय, जो बैंक 33 प्रतिशत एचीभ नहीं करेंगें, उस बैंक में हम अपनी राज्य सरकार की राशि जमा नहीं करेंगें ऐसे कितने बैंक है जहाँ 33 परसेंट लक्ष्य की पूर्ति नहीं की गयी तो वहाँ से बैंक से रुपये निकाल कर दूसरे बैंक में जमा करने का काम किया गया ?

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, जदयू का आक्रमण राजद पर है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंत्री : महोदय, बात असल यह है कि नंद किशोर जी को अपना पुराना दिन याद आता है, मगर रही बात ऐसे बैंकों की सूची है और जिन लोगों ने 33 प्रतिशत से ऊपर जो बिहार गवर्नमेंट का टारगेट पूरा किया है, उसी में सकरार का पैसा जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 119 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र के डा0 राजेन्द्र प्रसाद पथ सहित पूरे शहर को जाम से निजात दिलाने के उदेश्य से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाती है जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिली है, परन्तु डा0 राजेन्द्र प्रसाद पथ में फल और सब्जी की मण्डी रहने के कारण ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है जिसके कारण कभी कभी जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसे थाना के द्वारा कार्रवाई कर नियंत्रित किया जाता है । जाम से छुटकारा पाने के लिए उक्त क्षेत्र सहित कटिहार नगर निगम क्षेत्र में प्रश्नाधीन स0अ0नि0- 1 एवं गृह रक्षक 16 की प्रतिनियुक्ति की गयी है जो सुबह 9 बजे से रात्रि 20 बजे तक यातायात सुचारु रखने हेतु कार्य करते हैं । नगर थानान्तर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 223 मोटर सायकिल, चार पहिया चालकों से कुल 2 लाख 62 हजार 6 सौ रुपया एवं सहायक थानार्न्तत कुल 660 मोटर सायकिल, चार पहिया चालकों से कुल 2 लाख 86 हजार 4 सौ रुपया फाईन कर सरकारी कोषागार में जमा किया गया है । फिर भी माननीय सदस्य की चिन्ता पर निर्देश दिया गया है कि और मुस्तैदी से इसकी कार्रवाई की जाय ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, डा0 राजेन्द्र प्रसाद पथ कटिहार नगर का एकमात्र पथ निर्माण विभाग का पथ है ।

अध्यक्ष : आपका कोई सुझाव है तो दीजिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : जी, वही दे रहा हूं । और इस पथ पर न्यू मार्केट जो कटिहार नगर निगम..

अध्यक्ष : सरकार ने तो स्वीकार किया है फिर क्या पूछ रहे हैं ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, हम बता रहे हैं, हम उसपर आ रहे हैं कि वह एक बड़ी सब्जी मण्डी है और कटिहार नगर निगम और उसके लेसी द्वारा जानबुझ कर सड़कों पर अपने फुटकर सब्जी बिक्रेता भाईयों को बैठाया जाता है और कर की वसूली होती है जबकि न्यू मार्केट का जो भीतर का क्षेत्र है वह काफी बड़ा है, अगर कटिहार नगर निगम और उसका लेसी चाहे तो सारे दुकानदारों को...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : हम पूछ रहे हैं । उसके अंदर बैठाया जा सकता है तो हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि डा0 राजेन्द्र प्रसाद पथ के जितने अपने फुटकर सब्जी बिक्रेता दुकानदार भाई हैं, उनको न्यू मार्केट के अंदर बैठाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? अगर वह लेसी उसको नहीं बैठा रहा है तो सरकार लेसी पर क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने नगर निगम से, नगर विकास विभाग से संबंधित प्रश्न किया है फिर भी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया जायेगा कि अगर जगह है तो सब्जी बाजार को उसमें लेकिन है यह कठिन काम गरीब लोग ही आकर चौराहे पर बेचते हैं तो अब बाजार बंद हो जाता है, रोड जाम हो जाता है, फिर भी निर्देश दिया जायेगा कि एमीकेब्ली आपस में बैठकर इस मामले को सलटाने का काम करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2453 (श्री विजय कुमार खेमका)

अध्यक्ष : पूछा हुआ प्रश्न है आपका ।

श्री अब्दुल गफूर, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दोनों छात्रावासों का लगभग 90 प्रतिशत योजना कार्य पूर्ण हो चुका है । योजना कार्य प्राक्कलन के अनुरुप है ।

3- योजना का शेष काम यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा ।

श्री विजय कुमार खेमरा : अध्यक्ष महोदय, यह गरीब छात्रों का मामला है और 2011 में एग्रीमेंट हुआ है और जो मंत्री महोदय कह रहे हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इनको गलत रिपोर्ट अधिकारियों ने दी है । आज भी आई0टी0आई0 में जो छात्रावास है पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिय में जो छात्रावास बन रहा हे उसमें जो अधूरा निर्माण है उसपर जंगल जो है, उपज के जगह जंगल उपज गया है अध्यक्ष महोदय, और घटिया सामान...?

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री विजय कुमार खेमका : मैं वही पूछ रहा हूँ कि मंत्री महोदय कहते हैं कि 90 परसेंट निर्माण हो गया है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि एक जॉच कमिटी बन जाय ताकि सामने में आ जायेगा कि कितना निर्माण हुआ है और जो दोषी व्यक्ति हैं उसको भी क्या सजा मिलती है और यह जॉच कमिटी कबतक गठित होगी इसका भी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय समय दें ।

श्री अब्दुल गफूर, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से हम जॉच करा लेते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2549 (श्री नंद कुमार राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के परसौनीनाथ पंचायत के अंडौल कब्रिस्तान की घेराबंदी आंशिक रुप से की गयी है उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया गया है । ग्राम नरियार कोल्ड स्टोरेज के दक्षिण कब्रिस्तान की घेराबंदी आंशिक रुप से की गयी है । प्रश्नगत जमीन की किस्म रैयती है । राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर ही अवस्थित संवेदनशील कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना है ।

तारांकित प्रश्न संख्या -2550 (श्री लाल बाबू राम)

श्री अब्दुल गफूर, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार द्वारा अल्प संख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जाता है । वर्तमान नीति के अनुसार प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2551 (श्री नितिन नवीन)

अध्यक्ष : यह तो पहले ही उत्तर हो चुका है ।

श्री नितिन नवीन : स्पष्ट नहीं आया था ।

अध्यक्ष : स्पष्ट नहीं आया था तो लगता है कि दोनों को एक ही जगह से आपूर्ति हुई थी ।

श्री नितिन नवीन : यह पेपर में आया था अध्यक्ष महोदय, फिर भी सरकार का निर्णय...

तारांकित प्रश्न संख्या -2552(श्री सैयद अबू दौजाना)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची के क्रमॉक 226 पर अवस्थित है । घेराबंदी न होने से यदा कदा पशुओं के प्रवेश करने की संभावना हो सकती है । प्राथमिक सूची के क्रमॉक 1 से 17 के कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्राक्कलन तैयार करने के लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमण्डल-1 सीतामढ़ी एवं कार्य प्रमंडल-2 पुपरी को निर्देश जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा दिया गया है । बारी आने

पर प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी करायी जायेगी । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवदेनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है।

श्री सैयद अबू दौजाना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सेन्सिटीव ग्रेभयार्ड के लिए कभी हमारे डी0एम0 साहेब मीटिंग बुलाये नहीं तो यह कैसे समझा जाय कि कब यह कंपलीट करेंगे सेन्सिटीव ग्रेभयार्ड को ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने बताया कि अभी प्राथमिकता सूची में नीचे है । आप कब कंपलीट करेंगे वह पूछ रहे हैं ।

श्री सैयद अबू दौजाना : कम से कम मंत्री जी निदेश दे दें डी0एम0 को इसके लिए कि जो सेन्सिटीव ग्रेभ यार्ड है ।..

अध्यक्ष : आप प्राथमिकता में लेने का न अनुरोध करिये ।

श्री सैयद अबू दौजाना : जी,जी । ठीक है तो सारे ग्रेभयार्ड तो प्राथमिकता में ही है लेकिन जो सेन्सिटीव हैं, उस ग्रेभयार्ड के लिए कम से कम डी0एम0 को निदेश दिया जाय कि विधायकों के साथ मीटिंग करके वो कब कंपलीट करेंगे कि नहीं करेंगे यह हमेशा जब भी बार बार पूछते हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मिलकर जिला पदाधिकारी से इन डिटेल लिखकर दे दें कि सेन्सिटीव का क्या आधार है, जो मापदंड के फ्रेम में आयेगा तो उसकी कार्रवाई की जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 2553(श्री मुद्रिका प्रसाद राय)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि इसुआपुर थानाध्यक्ष को अपराधर्मियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी । शाम कोड़िया की दूरी इसुआपुर थाना से करीब 5 कि0मी0 है तथा भौगोलिक परिस्थिति अभी सुगम है । उक्त स्थान पक्की मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है । उक्त क्षेत्र में स्थानीय थाना द्वारा सतत् निगरानी, गश्ती कर अपराध एवं विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखा जाता है, वर्तमान में उक्त स्थान पर ओ0पी0 खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

टर्न–5/27.3.2017/बिपिन

श्री मुद्रिका प्रसाद राय:महोदय, वहां रेलवे स्टेशन भी है और चौक है एक, जहां अपराधियों का बराबर वहां हमला होते रहता है । रात में जब पैसेंजर उतरता है तो रात में लूटपाट करते हैं । बैंक लूट की कितनी घटनाएं हुई है वहां । संजय तिवारी की हत्या भी लूट से बचाने के क्रम में हुई है । हम चाहते हैं कि सरकार वहां ओ.पी. खोलना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : वह बता चुकी हैं कि अभी विचार नहीं है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव मंत्री: महोदय, जिस स्थान का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह मूल थाना से केवल 05 कि.मी. की दूरी पर है ।

तारांकित प्रश्न सं0: 2554(श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत् कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक-93 पर अंकित है ।

प्राथमिकता सूची के अनुसार क्रमांक-69 तक के कब्रिस्तानों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 41 तक की घेराबंदी कार्य पूर्ण है । बारी आने पर प्रश्नगत् कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई जाएगी ।

कबिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

तारांकित प्रश्न सं0: 2555(श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत् कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

प्रश्नगत् कब्रिस्तान के अतिक्रमण की जॉच के बिन्दु पर अंचल अधिकारी, भरगामा को नापी कराने का निदेश जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा दिया गया है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

तारांकित प्रश्न सं0: 2556(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण का कार्य जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जाता है । प्राथमिकता सूची में कोलसों खूर्द ठाकुरबाड़ी मंदिर क्रमांक-12 पर है तथा राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर प्राथमिकता क्रमांक-14 पर है ।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मंदिर चहारदीवारी निर्माण हेतु शिवहर जिला को कुल रू0 05.00 लाख आवंटित किया गया है जिसके आलोक में प्राथमिकता क्रम में 01 से 04 तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि रू0 52.00 लाख की है ।

4. प्राथमिकता सूची के आलोक में शेष मंदिरों की चहारदीवारी निर्माण का कार्य होगा ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान:अध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारित कर दिया जाए ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में, बता दिया है उन्होंने ।

तारांकित प्रश्न सं0: 2557(श्री मुद्रिका प्रसाद राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि स्व0 संजय तिवारी के अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य राशि 1,65,275/- एवं ग्रूप बीमा की राशि 30,199/- का भुगतान किया जा चुका है ।

सी.पी.एफ. के अन्तर्गत कटौती की गई राशि का भुगतान हेतु ऑन-लाईन फॉर्म कोषागार पदाधिकारी, सारण को दिनांक-02.11.2016 को समर्पित किया जा चुका है ।

स्व0 संजय तिवारी की पत्नी प्रियंका कुमारी द्वारा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया था जिसे जिला अनुकम्पा समिति के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग '3' के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया था । वर्त्तमान में अनुकम्पा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्ति शून्य रहने के कारण पुन: सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त कर नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश दिनांक-02.02.2017 को दिया गया है जिसके आलोक में आवेदिका प्रियंका कुमारी, पति स्व0 पु0अ0नि0 संजय कुमार तिवारी से अभी तक आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है । आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

4. कंडिका '3' में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

लेकिन महोदय, एक बात हम बताना चाहते हैं कि हमने पूछवाया कि क्या बात है तो पता चला कि उनकी पत्नी पुलिस में नौकरी करना नहीं चाहती है ।

तारांकित प्रश्न सं0: 2558(श्री मुजाहिद आलम)

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री: 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सरकार उद्योग नहीं लगाती है बल्कि उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करती है तथा औद्योगिक निवेदन प्रोत्साहन नीति में घोषित सहायता एवं सुविधा प्रदान करती है । उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्टार्ट-अप योजना, स्टैंड-अप योजना, कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कलस्टर योजना एवं बुनकर योजना के माध्यम से राज्य में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है । उक्त जिले में रोजगार हेतु युवाओं को पलायन जैसी कोई भी सूचना उद्योग विभाग को प्राप्त नहीं है ।

2. वर्तमान मे किशनगंज जिले में जूट उद्योग लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुजाहिद आलमः अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिले से मैं समझता हूं कि पांच लाख से ज्यादा युवा देश के अन्य प्रदेशों में जैसे दिल्ली, गुजरात में सूरत, उत्तर प्रदेश में मोरादाबाद, हरियाणा में फरीदाबाद, अलग-अलग उद्योगों में काम करते हैं और सभी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सीमांचल और किशनगंज की बदहाली पर ऑसू बहा रहे हैं और वहां पर जूट की बहुत बड़ी तादाद में खेती होती है और इसके अलावा..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मुजाहिद आलमः पूछ रहा हूं सर । वहां मकई की खेती बहुत बड़ी तादाद में होती है । अनानास की खेती होती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप वहां फुड प्रौसेसिंग यूनिट जैसे पाइन ऐपुल की बहुत बड़ी तादाद में खेती होती है, मकई की खेती होती है, जूट की होती है, इसको प्रोत्साहन कर लगाने का विचार करें, यही मैं आग्रह करूंगा ।

श्री जय कुमार सिंह,मंत्रीः महोदय....

अध्यक्ष : उन्होंने आग्रह किया है, जवाब किस चीज का दे रहे हैं ?

श्री जय कुमार सिंह,मंत्रीः महोदय, हमलोगों ने नई पॉलिसी लाया है और हमने प्रोत्साहन नीति जो निवेश प्रोत्साहन नीति हमलोगों ने बताया है महोदय, अभी हमारे यहां सब ऑनलाईन एप्लाई हो रहा है तो जो भी निवेशक आएंगे, हमलोग उनको प्रोत्साहन नीति के तहत उसको सहायता करने की हमलोग कोशिश करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0: 2559(श्रीमती गायत्री देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1435 दिनांक-14.03.2017 के द्वारा श्री लालबाबु सिंह के केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में दिनांक-06.01.2017 से 01.03.2017 तक डी0आई0आर0 कानून में निरूद्ध रहने से संबंधित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विभागीय उच्चस्तरीय समिति की दिनांक-23.03.2017 को सम्पन्न बैठक में श्री सिंह को छः माह से अधिक अवधि के लिए पेंशन की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

3. उपरोक्त खंड-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्रीमती गायत्री देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि कब तक उनको राशि का भुगतान किया जाएगा ? समय सीमा बता दिया जाए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः जल्दी ही उसका भुगतान कर दिया जाएगा । कुछ फॉर्मलिटी वगैरह होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां जमा करने के बाद उसके भुगतान की कार्रवाई की जाएगी ।

तारांकित प्रश्न सं0: 2560(श्री(मो0)आफाक आलम)

अध्यक्ष : उन्होंने नवाज आलम जी को अधिकृत किया है ।

श्री नवाज आलमः महोदय, पूछता हूं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्रीः महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

प्रश्नगत् ग्राम मझगॉवा बाजार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 477 है । मझगॉवा बाजार को पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो रही है । वर्तमान में मझगॉवा बाजार में कोई बैंक शाखा खोलना प्रस्तावित नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0: 2561(श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष : अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न सं0: 2562(श्री सैयद अबु दौजाना)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत् कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धरित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

टर्न : 06/कृष्ण/27.03.2017

तारांकित प्रश्न संख्या : 2563 (श्री शमीम अहमद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बंजरिया थाना से फुलवार ग्राम की दूरी 12 किलोमीटर है, जो पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में बंजरिया थाना द्वारा सतत् निगरानी एवं सघन गश्ती कर विधि-व्यवस्था तथा अपराध पर नियंत्रण रखा जा रहा है ।

वर्तमान में फुलवारा ग्राम में ओ0पी0 खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, वहां मोतिहारी से सटे बंजरिया थाना है और वहां से दूरी लगभग 12 से 18 किलोमीटर है और वहां सुगौली थाना भी 18 किलोमीटर की दूरी पर है । इधर दरपा थाना दूर है, आदापुर थाना दूर है । वहां पर अपराध नियंत्रण के लिये बीच में बहुत जरूरी है । इसलिये सरकार वहां पर ओ0 पी0 खोलने का विचार करे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, हरसिद्धि प्रखंड में हरसिद्धि थाना का जो भौगोलिक स्थिति है ।

अध्यक्ष : यह तो फुलवारा दक्षिण का मामला है । आप उसमें हरसिद्धि कहां से ला रहे हैं ? सिर्फ जिला से नहीं होता है न ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2564 (श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. सन् 1970 में पासमंदा मुसलमानों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी किसी प्रकार का आदेश उपलब्ध नहीं है ।

महोदय, दूसरी बात कि 1970 में तो स्व0 कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे भी नहीं, 1977 में था, 1971 में थे ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है।

बिहार राज्य में पासमांदा मुसलमानों को 1 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया है । अन्य राज्यों में पासमांदा मुसलमानों को आरक्षण दिये जा रहे से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

3. आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित है जिस के तहत राज्याधीन सेवाओं में आरक्षित वर्गों को नियुक्ति में निम्नवत् आरक्षण प्रतिशत का प्रावधान किया गया है :

अनुसूचित जाति - 16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति- 01 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 18 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग - 12 प्रतिशत
पिछडा वर्ग महिला - 13 प्रतिशत

कुल - 50 प्रतिशत ।

अनुसूचित जाति को छोड़कर सभी आरक्षित वर्गों में पासमांदा मुस्लिम तबके के लोग शामिल हैं तथा उन्हें देय आरक्षण का लाभ प्राप्त हो रहा है ।

अत: राज्याधीन सेवाओं में मुस्लिम पासमंदा तबके के लिये अलग से आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, माननीय वित्त मंत्री सिद्दीकी साहब यहीं हैं । वे अच्छी तरह जानते हैं कि 3 परसेंट स्व0 कर्पूरी ठाकुर के समय में, फाईल मंगाकर देख लिया जाय, 3 परसेंट उन्होंने दिया था अपने रीजिम में, पासमांदा मुसलमानों को, जेनरल मुसलमानों को नहीं, पासमांदा मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान हैं और अन्य राज्यों में भी उनलोगों के लिये व्यवस्था की गयी है । केरल में 12 परसेंट दिया गया है और अन्य राज्यों में भी

दिया गया है, कहीं 3 परसेंट, कहीं 3.4 परसेंट तो क्या सरकार का विचार है कि बिहार में भी पासमांदा मुसलमानों को आरक्षण देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, नोटिफिकेशन दे दें, समीक्षा कर के माननीय सदस्य को उत्तर दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2565 (श्री राज कुमार राय)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

हसनपुर प्रखंड की आबादी 1.05 लाख नहीं, बल्कि 2.27 लाख है । प्रखंड में बैंकों की कुल 8 शाखायें हैं, जिन में भारतीय स्टेट बैंक की 3 तथा बिहार ग्रामीण बैंक की 5 शाखायें हैं । ये शाखायें निम्नवत् हैं :

भारतीय स्टेट बैंक,कृषि शाखा, हसनपुर, भारतीय स्टेट बैंक,चीनी मिल शाखा, हसनुपर, भारतीय स्टेट बैंक, मंगलगढ़ शाखा, बिहार ग्रामीण बैंक, हसनपुर, बिहार ग्रामीण बैंक, पटसा, बिहार ग्रामीण बैंक, दूतपूरा, बिहार ग्रामीण बैंक,नयानगर, बिहार ग्रामीण बैंक, गोहा ।

विथान प्रखंड की आबादी 1.49 लाख है । प्रखंड में तीन बैंक की शाखायें हैं:

भारतीय स्टेट बैंक,विथान, बैंक ऑफ बडौदा,विथान एवं बिहार ग्रामीण बैंक, विथान ।

श्री राज कुमार राय, महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया, वास्तव में वहां बैंक हैं । लेकिन सरकार की जो कल्याणकारी योजनायें चल रही हैं, सारे चीज बैंक के माध्यम से जुड़ गये हैं । जिस से लोगों को काफी कठिनाई होती है । मैं माननीय मंत्री महादेय से आप के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि हसनपुर और विथान में भारतीय स्टेट बैंक की एक-एक शाखा और खोलने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : ठीक है । आप तो आग्रह किये हैं कि और शाखा खोलवा दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2566 (श्रीमती समता देवी)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के ग्राम सिन्धुगढ़ में वर्ष 1989 में मुठभेड़ के पश्चात् वहां पुलिस पीकेट रखा गया था, जिस के बाद उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी । स्थिति सुगम होने के पश्चात् वर्ष 2006 में पुलिस पीकेट हटा लिया गया है ।

2. स्वीकारात्मक हैं ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि सिन्धुगढ़ क्षेत्र मोहनपुर थानान्तर्गत है तथा पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है । सिन्धुगढ़ क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में है । क्षेत्र में सुरक्षा

बनाये रखने हेतु ग्राम सिन्धुगढ़ से दक्षिण 16 कि0मी0 की दूरी पर बरवाडीह में सी0आर0पी0एफ0 कोबरा बटालियन-205, उत्तर में करीब 16 कि0मी0 की दूरी पर फतेहपुर थाना तथा पश्चिम में 16 कि0मी0 की दूरी पर मोहनपुर थाना एवं एस0 एस0 बी0 आठवीं वाहिनी की एक कंपनी अवस्थित है, जिस के द्वारा क्षेत्र में समय-समय पर नक्सलियों के विरूद्ध अभियान चलया जाता है एवं थाना द्वारा सतत् निगरानी एवं गश्ती कर अपराध एवं विधि-व्यवस्था को नियंत्रण में रखा जाता है ।

अतः वर्तमान में सिन्धुगढ़ में ओ0पी0 खोलने को कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्रीमती समता देवी : महोदय, गया जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के ग्राम सिन्धुगढ़ में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में प्रश्न किया गया है । माननीय मंत्री गोलमटोल जवाब दिये हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है । वहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, अनेक घटनायें घट चुकी है और हाल ही में उसी के बगल में उग्रवादियों के द्वारा 10 गाड़ियों को जला दिया गया है। अगर शीघ्र ही सिन्धुगढ़ में पीकेट नहीं खोला गया तो कभी भी घटना घटी सकती है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सिन्धुगढ़ में 1989 से 2010 तक ओ0पी0 कारगर था, वहां पर तीन मंजिला भवन भी बना हुआ है । सरकार में वहां पर चौकी के लिये प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

अध्यक्ष : आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, सूचना के माध्यम से पूरक पूछना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर वहां चौकी खोलने की कार्रवाई विभाग में चल रही है । वहां पर फतेहपुर थाना, मोहनपुर थाना है, इन दोनों थानों के बीच काफी गैप है और झारखंड सीमा से जुड़ा हुआ जगह है और जंगली इलाका है, वह काफी संवेदनशील इलाका है, आये दिन वहां घटनायें घट रही है, उस को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुनः उस ओ0पी0 को खोलना चाहते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने उत्तर दिया कि सी0आर0पी0एफ0 का बटालियन है, एस0एस0बी0 का आठवीं बटालियन है, कोबरा बटालियन है, वहां इतनी सब चीजें हैं फिर भी माननीय सदस्य को शंका है तो निर्देश दिये जायेंगे कि ये लोग और ज्यादा एक्टिव ड्यूटी करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2567 (श्रीमती सावित्री देवी)

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3. सखुआ के पत्ता के पत्तल, विन्दा निर्माण हेतु लघु उद्योग केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । निजी क्षेत्र में जो उद्यमी

उद्योग स्थापित करने को इच्छुक हैं तो राज्य सरकार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सुविधायें प्रदान करने पर विचार करेगी ।

महोदय, यह बहुत छोटा उद्योग है । हम इस के लिये प्रचार-प्रसार भी कर रहे हैं और ऐसे उद्यमियों को हम प्रशिक्षित भी कर रहे हैं । एक छोटा उद्योग है । हम चाहेंगे, इसको लगाने का हम प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सभा पटल पर रख दिये जाय । कार्य-स्थगन प्रस्ताव ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 मार्च, 2017 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :-

श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विद्या सागर केशरी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री राणा रणधीर, श्री ललन पासवान, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री अरूण कुमार सिन्हा ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 172 (iii) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

टर्न–7/राजेश/27.3.17

शून्यकाल

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम ।

श्री लाल बाबू रामः महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड रेफरल अस्पताल के भवन जर्जर है जिससे मरीज के इलाज एवं चिकित्सकों को कार्य करने में काफी कठिनाई होती है, साथ ही अस्पताल क चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है । अतः भवन का निर्माण एवं चहारदीवारी कराने की कार्रवाई की जाए।

श्री शमीम अहमदः महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत बनकठवा प्रखंड के फुलवार पंचायत के गोड़िया पुल के पास से गोड़िया होते हुए वृजी बाजार तक कच्ची सड़क है । अतः सरकार से मांग करते हैं कि जनहित में इसको जल्द से जल्द बनवाए ।

श्री अमीत कुमारः महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 एवं राशन कार्डधारी को निर्धारित अनाज का वितरण, जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी दुकानदार नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण गरीब भूखे रहने को विवश है । जनहित में शीघ्र सभी गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय ।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के पीपरा पीच रोड से निकलकर लालू बाबा के मठिया पचरुखिया पथ तक जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण आम लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है । अतः जनहित में सरकार उक्त पथ का पिचकरण शीघ्र करायें ।

श्री संजीव चौरसियाः महोदय, पटना स्थित गर्दनीबाग थाना के पास से कूड़ा डंपिंग यार्ड हटाने की बात हुई थी, विगत कुछ दिनों तक वहॉ से कूड़ा डंपिंग यार्ड हटा भी दिया गया, परन्तु वर्तमान में पुनः वहॉ पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिसके कारण वहॉ पर आवासीत लोगों को काफी परेशानी हो रही है । अतः गर्दनीबाग से कूड़ा डंपिंग स्थाई रुप से हटाने की मांग करता हूँ ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी गोपालपुर नहर के पास अर्जुन मांझी, 35–वर्ष, ग्राम–कुशाबीजा टोला मुंगेश्वरपुर थाना–डोभी एवं बौली रविदास, 27 वर्ष ग्राम–पुना, थाना–परैयाा की मृत्यु सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर–डम्फर की टक्कर में दिनांक 26.3.2017 को हो गई है । मृतकों के आश्रितों को आपदा राहत कोष से 4–4 लाख रुपये मुआवजा की मांग करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंहः महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड में रफीगंज से कसमा तक 9 किलोमीटर सड़क की मरम्मति कार्य की जा रही है । मरम्मति कार्य में विभागीय

पदाधिकारियों एवं संवेदक की मिलीभगत से प्राक्कलन के प्रवृष्टियों के विपरीत कार्य हो रहा है । जांच कराकर दोषी पदाधिकारी एवं संवेदक पर कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, नबीनगर प्रखण्ड में मगध प्रमण्डल का सबसे प्रखण्ड है । नबीनगर में दो बड़ी बिजली परियोजना है। झारखण्ड सीमा पर अवस्थित क्षेत्र अति उग्रवाद प्रभावित है। अनुमण्डल कार्यालय नहीं रहने से जनता को प्रशासनिक कार्यों में काफी परेशानी होती है।

अत: सरकार से नबीनगर को अनुमण्डल बनाने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री रामदेव राय: महोदय, राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वैश्य (पोद्दार) को 2000 में पिछड़ा वर्ग-2 के क्रमांक 20 पर बनिया जाति की उप जाति के रूप में शामिल किया गया है, जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रुप से समाज का सर्वाधिक कमजोर गरीब वर्ग के है । अत: सरकार से उन्हें अनुसूचि-1 में रखने की मांग कर रहा हूँ ।

श्री ललन पासवान: महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत रोहतस प्रखण्ड के कौड़ियारी गाँव के सुरेश उराँव के अवसानी नदी पर पुल नहीं रहने से बरसात के दिनों में आदिवासी एवं बनवासी का रास्ता चार माह बंद हो जाता है । वहाँ से रोहितासगढ़ किला पर जाने का वही रास्ता है।

सरकार से मांग करते हैं कि उक्त पुल को बनावें ।

श्री डॉ मो0 नवाज आलम: महोदय, भोजपुर जिला अन्तर्गत बाल विकास परियोजना में महिला प्रवेक्षिका की नियुक्ति 2013 में की गई थी, 4 साल से ज्यादा होने जा रहा है इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया हैं।

अतएव मैं सदन से माँग करता हूँ महिला प्रवेक्षिका का स्थानान्तरण किया जाये ।

श्री राणा रणधीर: महोदय, ''पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल में अपराधियों के द्वारा लगातार रंगदारी माँगे जाने से पूरे अनुमंडल के व्यवसायियों में भय एवं दहशत का माहौल है। अनुमंडल भर के व्यवसायी ने अनिश्चित काल तक अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय किया है । मैं सरकार से अविलम्ब अपराधियों को पकड़ने की माँग करता हूँ।''

श्री सुदामा प्रसाद: महोदय, भोजपुर जिले में आरा-शहर के आभूषण-व्यवसायी हरिशंकर सोनी वल्द- भरत प्रसाद की 24.03.2017 को डुमरा में गोली मारकर हत्या कर दी गयी, जिसका केस नं. आरा मुफ्फसील थाना कांड सं. 57/17 है. मैं हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी, मृतक-पत्नी को 10 लाख का मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग करता हूँ।

श्री महबूब आलम: महोदय, बांका के चांदन थाना के चंदवारी में 7.1.17 को तथा जमुई के खैरा थाना के महेन्ग्रो में 13.02.2017 की रात माले नेता रामायणतुरी व जेठूहेम्ब्रम को पुलिस घर से बुलाकर ले गयी और 'माओवादी' कहकर जेल भिजवा दिया, मैं दोनों की बिना शर्त्त रिहाई की मांग करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, जमुई-जिला के खैरा थाना ग्रा.-दानसिंहडीह में 5.3.17 को महादलित अनिल दास के घर से निकली बारात को दबंग अपराधियों ने रोकते हुए मारपीट कर कई को घायल किया, गाड़ी का शीशा फोड़ा और जातिसूचक गालियां दीं, जिसपर खैरा थाना कांड सं. 53/17 के तहत केस है, हमलावरों की गिरफ्तारी तथा महादलितों के घर से निकलने के रास्ते की मांग करता हूँ ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: महोदय, एन0एच0 110 जहानाबाद-अरवल पथ का निर्माण कार्य हो रहा है । इसमें बहुत सारे पुल पुलिया का निमार्ण कराया जा रहा है जो निम्न स्तर का है । इसमें जो सामग्री लगाई जा रही है वह बिल्कुल निम्न स्तर का है।

अत: सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा: महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर प्रखंड के संसा ग्राम पंचायत एवं अकोढ़ा ग्राम पंचातय को जोड़ने वाली सड़क करमाही पुल से शंकर बिगहा तक जाने वाले ग्रामीण जनता को आजादी के 70 साल के बाद भी पगडंडी से ही जाना पड़ता है। इस सड़क के बन जाने से दर्जनों गांवों की जनता लाभान्वित होंगे।

अत: इस सड़क को तत्काल बनाने का मांग करता हूँ ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, गोपालगंज जिले के सिधवलिया थानान्तर्गत बलरा निवासी कंचन प्रसाद (30) की निर्मम हत्या विगत 24 मार्च 2017 को अपराधियों ने कर दिया । राजमिस्त्री का कार्य करने वाले मृतक के दो बच्चे और गर्भवती पत्नी बेसहारा हो गयी है। अपराधियों की गिरफ्तारी तथा सरकार द्वारा आश्रित को 5 लाख मुआवजा दिया जाए।

श्री विजय कुमार खेमका: महोदय, पूर्णियां में 1952 में स्थापित राज्य पुस्तकालय भवन पूरी तरह से जर्जर तथा दीवार और छत से प्लास्टर गिर रहा है। रख-रखाव के अभाव में कीमती पुस्तकें खराब हो रही है । बिजली विच्छेदन के कारण पुस्तक प्रेमी को पुस्तकालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

अत: मैं सरकार से जर्जर पुस्तकालय के जीर्णोद्धार की मांग करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह: महोदय, 07.03.2017 को विक्रमगंज में धक्का लगने से अजय कुमार सिंह की मृत्यु हुई तथा प्रभाशंकर पाण्डेय घायल हुए । लोगों द्वारा घटनोपरांत सड़क जाम करने पर स्थानीय पुलिस द्वारा कांड संख्या-61/17 दर्ज कर 20 नामजद बेगुनाहों को तंग किया जा रहा है । सरकार इस केस को वापस ले ।

श्री आनन्द शंकर सिंह: महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत, औरंगाबाद मुख्यालय अवस्थित सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में बी0 फार्मा कोर्स के छात्रों का विगत 4 वर्षों से परीक्षा आयोजित नहीं की गई, जिससे लगभग 500 छात्रों का भविष्य अधर में है ।

अत: आपसे आग्रह है की जल्द ही परीक्षा आयोजित करवा कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कराया जाये ।

टर्न–8/सत्येन्द्र/27–3–17

श्री सुबोध राय:अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड प्रखंड के खुलनी पंचायत में पचरूखी मुख्य पथ पर शिक्षा विभाग की निधि से उच्च विद्यालय का नवनिर्मित भवन बनकर एक साल से तैयार है । अतएव मैं सरकारी नवनिर्मित भवन में शिक्षण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग करता हूँ ।

श्री नीरज कुमार: अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत एस0एच0–77 के नरैहिया गांव से रामनगर कोशी धार नागर धार होकर टीकापट्टी एस0एच0–65 तक ग्रामीण पथ पर पूल सहित निर्माण करने की मांग करता हूँ । उक्त पथ के निर्माण से तीन प्रखंड के किसानों को बहुत लाभ होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय बाजार के बगल में स्थित जलमीनार से बाजार एवं आस पास के लोगों को पानी सप्लाई होता है । सड़क निर्माण के क्रम में पानी सप्लाई पाईप लगभग 60 फीट टूट गया है जिसके कारण बाजार के आधी भाग में पानी की सप्लाई हो रही है और आधे भाग के लोग पानी के बिना त्राहिम्राम कर रहे हैं । अत: सरकार पाईप की मरम्मति कराकर पानी की सप्लाई करे ।

श्री अमरनाथ गामी: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेड़ी अचंल पर दो दिनों से अंचलाधिकारी के खिलाफ रूपोलिया में अग्निकांड से प्रभावितों एवं अन्य मांगों को लेकर सर्वदलीय समर्थक अनशन पर है । अत: सरकार से मांग करता हूँ कि अंचलाधिकारी का स्थानांतरण एवं अग्निपीड़ितों को गृह क्षति अनुग्रह अनुदान देकर अनशन समाप्त करावें ।

श्रीमती बेबी कुमारी: अध्यक्ष महोदय, किडनी के बीमार मरीज को डायलेसिस सुविधा अनुमंडल स्तर पर दिये जाने एवं इन्दिरा गांधी इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईन्स, शेखपुरा, पटना में बिना भर्त्ती हुए इलाज करा रहे मरीज को भी डायलेसिस सुविधा प्रदान करने की मैं मांग करती हूँ ।

श्री यदुवंश कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला के वीरपुर थानान्तर्गत ग्राम भवानीपुर में स्थानीय विधायक एवं उनके समर्थकों ने दिनांक 14–3–17 को बिजली विभाग के संवेदक को बुरी तरह मारपीट किये जाने के विरूद्ध थाना कांड संख्या– 59/17 दर्ज कर पुलिस प्रशासन बैठ गयी है । अत: बिजली संवेदक को बुरी तरह मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार सोनवरसा एवं सुरसंड प्रखंड में दिनांक 24–3–17 की रात्रि में भारी ओलावृष्टि हुआ है जिससे फसल की क्षति हुई है । अत: सरकार से मांग करती हूँ कि पीड़ित किसान के फसल क्षति के लिए मुआवजा की घोषणा करे ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, रोगी कल्याण समिति में जिला स्तर/अनुमंडील स्तर/रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पूर्व की तरह एम0एल0ए0 को अध्यक्ष बनाने की मांग करता हूॅ ।

श्री विद्या सागर केशरीः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत जोगवनी बोर्डर से सटे भारत नेपाल सीमा चेक पोस्ट को तीसरे देश के नेपाल जाने एवं आने वाले समानों से भारत सरकार को मिलने वाली टैक्स(कर) को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा रहा है । अतः सदन से उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूॅ ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक एन0एच0-28 पर गोलम्बर नहीं रहने से आये दिन दुर्घटना हो रही है । बच्चों को स्कूल सहित शहर जाने के लिए चौक को पार करना पड़ता है । अतः जनहित में गोलम्बर बनाने की मांग करता हूॅ ।

श्री तारकिशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के हसनगंज प्रखंड में पावर सब स्टेशन का निर्माण प्रारम्भ नहीं होने से विद्युत आपूर्त्ति बाधित है । अतः निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करावें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हाः अध्यक्ष महोदय, पटना में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चौधरी टोला घाट पर गंगा रीवर फ्रंट का निर्माण कार्य एक माह से रूका हुआ है जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है । इस रूके हुए कार्य को अतिशीघ्र प्रारम्भ करने की मांग सरकार से करता हूॅ।

अध्यक्षः शून्यकाल की सूचनाएं समाप्त हुई । अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री ललन पासवान,रामप्रीत पासवान एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा सरकार(विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)की ओर से वक्तव्य।

श्री ललन पासवानः सूचना पढ़ी हुई है।

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय,प्वायंट ऑफ आर्डर है। कुछ देर के लिए देखा कि नेता विरोधी दल सदन के गायब थे लगता है कि भोज की तैयारी में लगे हैं । क्या देखने गये थे व्यंजन ?

श्री ललन पासवानः सर, सूचना पढ़ा हुआ है ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्रीः महोदय, सासाराम जिला में शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम की स्थापना के लिए निम्न भू-स्थल का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:(1)शिवसागर अंचल के मौजा करूप थाना संख्या 351 खाता संख्या 220 खेसरा संख्या 2043, 2044 एवं 2046 कुल संख्या 10.26 एकड़ कैसरे हिन्द पुरानी परती भूमि (2)प्रखंड करगहर मौजा शिवम थाना संख्या 78 खाता संख्या 382 खेसरा सख्या 2214,2218 2216 1875 एवं 1873 रकवा

11.25 एकड़ किस्म भूमि पिण्ड रैयत अनावाद बिहार सरकार, अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापना के लिए भूमि का उपयोग एवं अन्य अपेक्षित आवश्यकताओं की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराकर समीक्षोपरांत उचित निर्णय लिया जायेगा ।

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से हम जानना चाहते हैं सरकार का जो मापदंड है, सरकार का सभी जिला मुख्यालय में अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का निर्णय है । महोदय, पत्रांक संख्या 1288 दिनांक 28-12-2012 रोहतास जिलान्तर्गत मोजा करूप थाना संख्या 351 खाता संख्या 220 खेसरा संख्या 2043, 2044 के रकवा क्रमशः 6.75, 2.25 एवं 1.62 एकड़ कुल रकवा 1062 एकड़ कैसरे हिन्द किस्म पुरानी परती भूमि पर स्वीकृति दी गयी जिसकी संविदा मुख्य अभियंता(दक्षिण)भवन निर्माण विभाग के पत्रांक संख्या 370 अनु0 दिनांक ...

अध्यक्षः यह तो आप सब उसी को पढ़ रहे हैं इसका तो जवाब सरकार ने दिया है । पूरक पूछिये न, यह सब तो इसमें लिखा हुआ ही है ।

श्री ललन पासवानः सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जब चयन कर ली, एन0ओ0सी0 हो गया महोदय भूमि का सासाराम मुख्यालय में और मुख्यालय में 1 कि0मी0 की दूरी पर और टेंडर भी हो गया, एकरारनामा की कौपी है 92 करोड़ का महोदय.....

अध्यक्षः अब पूरक पूछिये न ?

श्री ललन पासवानः सर, मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा जान लिया जाय कि सरकार क्या कर रही है । सरकार इसकी स्वीकृति दी, बीड हो गया, एकरारनामा हो गया, टेंडर हो गया और अब काम प्रारम्भ करना है और सरकार जवाब यह दे रही है, इतनी असत्य, सरकार इतनी गलत बयानी कर रही है महोदय, सरकार का मापदंड क्या है, जब एकरारनामा कर ली गयी ..

अध्यक्षः हम कह रहे हैं पूरक पूछने के लिए न ।

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूँ । तीन दिन पहले एक पत्र निकला है, अभी निकला है महोदय और ये हमारी निविदा हुई है जान लिया जाय सर तब न पूरक पूछेंगे ।

अध्यक्षः यह सब इसमें लिखे हुए हैं न ।

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, निविदा निकल गयी, एकरारनामा हो गया और सरकार अब पत्र लिख रही है कि हम नयी जमीन का चयन कर रहे हैं । महोदय, जो पहली कमिटी चयन की थी क्या वह गलत की और गलत नहीं की तो सरकार किस मापदंड के तहत इसको ले जाना चाहती है? करगहर 28 कि0मी0 पर सरकार की क्या मानसिकता है, इये मुख्यालय में क्यों नहीं बनवाना चाहती है, सरकार की कौन मजबूरी है, क्या सरकार किसी के दवाब में है, सरकार यह बतावें ?

टर्न-9/मधुप/27.03.2017

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, हमारी सरकार ने सात निश्चय के तहत एक निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज लगायेंगे । महोदय, चूंकि एक जमीन का ब्यौरा पहले आ चुका था और जब समाहर्त्ता, रोहतास ने एक दूसरे भूखण्ड का ब्यौरा दिया है तो मैंने तो इतना ही कहा कि दोनों का अद्यतन स्थिति जानकर हम एक वरीय पदाधिकारी से उसकी उच्चस्तरीय जॉच कराकर हम निर्णय लेंगे ।

श्री ललन पासवान : नहीं-नहीं महोदय । जब एकरारनामा हो गया, सरकार उस समय क्या सोयी हुई थी ? क्या सरकार के संज्ञान में नहीं था ? एन0ओ0सी0 हो गया, टेन्डर हो गया, एकरारनामा हो गया, बीड खुल गया, अब सरकार को शिलान्यास करना है तो अब सरकार भूमि की बात कर रही है ? कलक्टर से रिपोर्ट अगर मापदंड के खिलाफ है तो क्या कलक्टर पर सरकार कार्रवाई करेगी ? क्या सरकार का मापदंड है ?

अध्यक्ष : ललन जी, सरकार ने कहा है कि उसको दो जगह की अनुशंसा कलक्टर से प्राप्त हुई है। आप जो उपयुक्तता की बात कह रहे हैं, उसी के बारे में सरकार ने कहा है कि यहॉ से उच्चस्तरीय कमिटी का गठन करके दोनों की जॉच कराकर जो उपयुक्त होगा, निर्णय लिया जायेगा । वही तो सरकार कह रही है ।

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि 2012 का यह मामला है, सरकार निविदा निकाली, सरकार एकरारनामा कर दी, सरकार बीड खोल दी, सरकार जमीन का एन0ओ0सी0 कर दी, वह भी कैसरे-हिन्द की जमीन है, वह भी सरकारी जमीन है, सरकार किन परिस्थितियों में आज से 15 दिन पहले निर्णय ले ली कि अब दूसरी चयन की समिति आयेगी, दूसरा जगह अब करगहर में बनेगा ? कौन-सी वरीयता सरकार की हो गई, सरकार यह तो बतावे कि कौन-सी वरीयता में सरकार निर्णय लेना चाहती है ? कलक्टर का कौन-सा मापदंड है ?

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, अब वहॉ के एक माननीय विधायक वशिष्ठ जी हैं और उन्होंने चूंकि डी0एम0 को आवेदन दिया और जिला समाहर्त्ता चूंकि कोई माननीय सदस्य कोई आवेदन करेंगे, तो नेचुरली है कि जिला समाहर्त्ता कुछ तो लिखेंगे । एक जो भूखण्ड का दिये तो सुटेबल वह लगा और डी0एम0 ने हमारे विभाग को दे दिया है । तो एक प्रक्रिया है कि जब डी0एम0 ने माननीय सदस्य के आवेदन के आलोक में, उन्होंने एक सूचना दिया है, तो एक प्रक्रिया है, उसको जानने के बाद ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं ।

श्री ललन पासवान : महोदय, कैबिनेट के फैसले के बाद, मैं ही क्यों नहीं माननीय सदस्य हूँ, कैबिनेट के निर्णय के बाद दोबारा कैबिनेट नहीं हुआ, किस परिस्थिति में आपने कैबिनेट

के फैसले को, सरकार निर्णय को बदलना चाहती है ? क्यों सरकार कैबिनेट के अपने फैसले को बदलना चाहती है ? सरकार बतावे ।

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, हमने तो कैबिनेट के फैसले की बात को कहाँ कहा ? हमने कहा कि जिला समाहर्त्ता से कोई माननीय सदस्य के द्वारा कोई लिखित दिया गया, उस सूचना के आलोक में मुझे जब समाहर्त्ता का पत्र आया है, तो हमने कहा कि एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत उन दोनों भूखण्डों को हम देखवा लेंगे अपने वरीय पदाधिकारी से ।

श्री ललन पासवान : महोदय, मंत्री जी बतावें कि कैबिनेट के फैसले के बाद, तब तो कोई आम पब्लिक, कोई जन-प्रतिनिधि, हम भी कल कहें कि नहीं, वहाँ नहीं बनेगा तो मेरी बात की जाँच कराकर ले चलेंगे चेनारी ? माननीय मंत्री जी, मैं भी एम0एल0ए0 हूँ, माननीय सदस्य हूँ, मैं भी कम्पलेन करूँगा तो क्या चेनारी.....

अध्यक्ष : अभी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ललन पासवान : महोदय,मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसका बीड खुल गया, टेन्डर हो गया, निविदा क्यों कैंसिल करने का और जमीन पर रोक लगाने का किस आधार पर सरकार ने नोटिस किया ? काम कब शुरू करेगी सरकार ? सरकार उस पर काम कब प्रारंभ करेगी ?

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : सरकार अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से वह कार्य शुरू करेगी ।

श्री ललन पासवान : उस जगह पर काम कब शुरू करेगी ?

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : मैंने पहले कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, दो पत्र जिला समाहर्त्ता की तरफ से आया है, तो उसमें कुछ करना भी है तो एक प्रक्रिया है । मैंने पहले भी कहा कि एक प्रक्रिया के तहत उसमें निर्णय लिया जायेगा ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार जो कह रही है.....

अध्यक्ष : सरकार कह रही है कि उसको दो प्रस्ताव मिले हैं, उसकी उच्चस्तरीय जाँच करायेंगे तो इसमें क्या कहा जाय !

श्री ललन पासवान : महोदय, हमारे पास कागज है.....

अध्यक्ष : कागज सब आप सरकार को उपलब्ध करा दीजिये ।

श्री ललन पासवान : तब तो न्यायालय में.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : न्यायालय जाने के लिये तो कोई स्वतंत्र है, उस बात का जिक्र यहाँ करने की क्या आवश्यकता है ?

माननीय सदस्य,श्री सदानन्द सिंह । सूचना पढ़ें ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब दिलाया जाय ।

अध्यक्ष : सरकार तीन बार वही जवाब कह रही है ।

श्री ललन पासवान : सरकार किससे जॉच करायेगी ?

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, वरीय पदाधिकारी हमारे डायरेक्टर हैं, मैं उनसे देखवा लेता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सदानन्द सिंह एवं श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानार्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के विक्रमशीला विश्वविद्यालय के स्थल पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक भूमि अधिगृहित नहीं की गई है । इस आलोक में जिला पदाधिकारी, भागलपुर समाहरणालय के पत्रांक-LVIII-4206-909, दिनांक-21.03.2016 द्वारा अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को 500 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण करने हेतु अनुमानित कुल राशि 4,17,87,94,920/- (चार अरब सतरह करोड़ सतासी लाख चौरानवे हजार नौ सौ बीस) रूपये व्यय होने की सम्भावना व्यक्त की गई है । भूमि अधिग्रहण में हो रहे विलम्ब के कारण केन्द्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण बाधित है ।

अत: शीघ्र भू-अर्जन कर विक्रमशीला विश्वविद्यालय के स्थल पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में कहना है कि भारत सरकार के दिनांक 24.11.2015 के अर्द्ध-सरकारी पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री पैकेज के तहत भागलपुर के निकट ऐतिहासिक विक्रमशीला विश्वविद्यालय के आसपास एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय से अवगत कराया गया तथा इसके लिये 50 करोड़ रूपये आवंटन की चर्चा की गई । परन्तु इस प्रकार की कोई राशि अब तक विभाग के पास प्राप्त नहीं है ।

केन्द्र सरकार के उक्त पत्र में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 500 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने की अनिवार्यता बतलाई गई है । तथा इसके लिये 3 उपयुक्त स्थलों का चयन कर भारत सरकार को सूचित किया जाना है ताकि तीनों चयनित स्थलों में से किसी एक स्थल पर चयन केन्द्र सरकार के स्तर से समिति कर सके । केन्द्र सरकार के उक्त निर्देश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक 5 दिनांक 9.1.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर को भागलपुर के निकट प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कम से कम 500 एकड़ भूमि उपयुक्त तीन स्थलों पर चयनित कर विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया है जिसके प्रत्युत्तर में जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने पत्रांक 99 दिनांक 21.3.2016 द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगॉव अनुमंडल में मात्र एक स्थल पर कुल रकबा 500 एकड़ रैयती

भूमि का चयन कर विभाग को प्रतिवेदित किया गया है जिसके अधिग्रहण में लगभग 543 करोड़ रूपये की आवश्यकता दर्शायी गई है । प्रतिवेदन में भूमि का विस्तृत ब्यौरा संलग्न नहीं है जिसके कारण केन्द्र सरकार को प्रतिवेदित किये जाने में कठिनाई है ।

केन्द्र सरकार के निर्देश के तहत पुनः विभागीय पत्रांक 72 दिनांक 17.1.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर को तीन उपयुक्त स्थलों पर 500 एकड़ भूमि का चयन कर भूमि विवरण के साथ विस्तृत प्रतिवेदन की माँग की गई है । जिला पदाधिकारी, भागलपुर से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भूमि चयन की विस्तृत विवरणी के साथ केन्द्र सरकार को प्रतिवेदित किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा सहमति दिये जाने के पश्चात् किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वयं माननीय मंत्री जी ने महसूस किया है कि 2016 की चिट्ठी के बाद फिर विभाग ने अभी पिछले महीने पत्र लिखा है । हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि कबतक बिहार सरकार (शिक्षा विभाग) उस चयनित भूमि की पूरी जानकारी लेकर केन्द्र सरकार के द्वारा जो घोषित की गई है, उसके लिये अधियाचना यानी राशि की माँग कबतक करेगी ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी को जमीन का चयन करना है और 17.1.2017 को वापस में हमलोगों ने रिमाइन्ड किया है डी0एम0 को और भारत सरकार ने तीन स्पेसिफिक लैण्ड का स्पेसिफिकेशन माँगा है, अभी जो हमारे पास प्राप्त है, वह मात्र एक का प्राप्त है । एक का भेजने में यह है कि भारत सरकार का जो अनुपालन है, वह पूरा प्रतिवेदित नहीं हो पायेगा क्योंकि उनका मिनिमम दो और मैक्सिमम तीन माँगा गया है इसलिये हमलोगों ने डी0एम0 को भेजा है । इसमें सरकार संवेदनशील है, सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी विक्रमशीला विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाय । इसको हमलोग तुरंत फौलो-अप कर लेंगे ।

श्री सदानन्द सिंह : क्या माननीय मंत्री कोई समय-सीमा जिला पदाधिकारी को निर्धारित करके भेजे हैं कि इतने समयसीमा के अन्दर वह प्रतिवेदित करें शिक्षा विभाग को ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : डी0एम0 को खोजना पड़ता है, 500 एकड़ एक जगह लैंड की आवश्यकता है, 17.1.2017 को हमलोगों ने भेजा है, मैक्सिमम हम हायर एजुकेशन की एक कमिटी बनाकर डी0एम0 के यहाँ भेजेंगे, इसको जल्दी से जल्दी फौलो-अप करने के लिये ।

श्री सदानन्द सिंह : सिर्फ समय-सीमा । दो महीना, तीन महीना में कम्पलीट कर लीजियेगा, यह भी तो कहिये ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : हमारी जो भूमिका है, हमारी भूमिका है कि इसको एक्सपेडाइट करना, वह हम एक्सपेडाइट करेंगे । लैंड का सेलेक्शन डी0एम0 को करना है । तीन महीना के अन्दर हमने कहा है कि हम कमिटी का गठन करके बजाप्ता कैम्प करवायेंगे ।

श्री सदानन्द सिंह : माननीय मंत्री जी, डी0एम0 आपके अधीन हैं, आप निर्देशित कीजिये ।

टर्न–10/आजाद/27.03.2017

अध्यक्ष : ठीक है ।

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, ''दरभंगा प्रमंडलीय मुख्यालय है, जिसका पुराना बस स्टैण्ड शहर के अन्दर है, जिसकी स्थिति अत्यन्त नारकीय है एवं वहां भारी जाम लगा रहता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जमीन पर दिल्ली मोड़ के निकट राष्ट्रीय सम विकास योजना से 5 वर्ष पूर्व से ही 6 करोड़ की राशि से नया बस स्टैण्ड बनकर तैयार है लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के आपसी विवाद के कारण बना हुआ बस स्टैण्ड प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

अतः जनहित में नये बस सटैण्ड को प्रारम्भ कराने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ । ''

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित बस स्टैण्ड दरभंगा नगर निगम सीमा से बाहर है । सम विकास योजनान्तर्गत बस पड़ाव का निर्माण ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के द्वारा कराया गया है । समाहर्त्ता दरभंगा के पत्रांक–2114, दिनांक 05.12.2016 के माध्यम से नगर निगम, दरभंगा को निःशुल्क हस्तानान्तरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप से देने के पूर्व बस स्टैण्ड का रख–रखाव एवं संचालन आदि नगर निगम स्तर से ही करने के बिन्दु पर स्पष्ट प्रस्ताव की मांग की गई थी ।

इस आशय का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 31.12.2016 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है तथा नगर निगम, दरभंगा के पत्रांक–386, दिनांक 14.02.2017 द्वारा समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचित किया गया है । उक्त बस स्टैण्ड नगर निगम, दरभंगा को हस्तांतरित होने के पश्चात् चालू करा दिया जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, वही मैं बोल रहा था और वह इसमें भी है राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग । इसमें इनको कुछ नहीं करना है, इसमें जवाब देना है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को । मैंने उनसे ही आग्रह किया है और उन्हीं को जवाब देना है । पिछले 4–5 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक थी और वहां पर मुख्य सचिव भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निदेशित किया, कड़ाई से बोला, वहां पर सभी माननीय मंत्री वगैरह थे, इतनी कड़ी टिप्पणी की, जो यहां नहीं बोला जा सकता है । उन्होंने स्पष्ट कहा और मुख्य सचिव ने कहा कि तीन दिनों के अन्दर फाईल

मंगवाईए, उसको तुरंत करेंगे । इसमें राजस्व विभाग जो है, उसमें कहीं न कहीं मामले को लटकाये हुए हैं । इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निदेश के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है । इसमें जवाब राजस्व विभाग को देना है क्योंकि नगर विकास विभाग तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हस्तांतरण कर देगा, उसके बाद नगर विकास करेगा । इसलिए सर, इसमें राजस्व विभाग को जवाब देना है, अभी राजस्व मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, इसको कल जो है, करा दीजिए सर ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको स्थगित करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानान्तरित । माननीय वित्त मंत्री । इसको तो होने दीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार आन्दोलित है बिजली वृद्धि के सवाल को लेकर । गांव, गरीब, किसान सब लोग सड़कों पर है और 38 जिलों में आन्दोलन और प्रदर्शन हो रहा है । इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि सदन का समय मात्र 4 दिन रह गया है, सरकार टाल-मटोल नीति के बजाय महोदय सरकार सदन में घोषणा करे .....

अध्यक्ष : आपकी बात को मानकर सरकार ने कहा है कि दो-तीन दिनों के अन्दर निर्णय लेकर के चलते सत्र में बतायेगी । माननीय वित्त मंत्री ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : जनता सड़कों पर है महोदय, सरकार घोषणा करे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपना काम निकाल लिये और उसके बाद शोरगुल करने लगे । यह तो बड़ा स्वार्थी का लक्षण है । आप अपना काम निकाल लिये और सदन का काम बाधित करिए, यह बिल्कुल गलत है । आपके कार्य में भी कल बाधा हो सकती है , मैं कह देता हूँ ।

माननीय वित्त मंत्री ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में चले आये)

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं, बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (1) 'राज्य का वित्त' (2) 'राजस्व प्रक्षेत्र' तथा (3) 'सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र' को जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 238 के उपबंध के अुनसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय में उपस्थापित किया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (1) 'राज्य का वित्त' (2) 'राजस्व प्रक्षेत्र' तथा (3) 'सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात्, उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (1) 'राज्य का वित्त' (2) 'राजस्व प्रक्षेत्र' तथा (3) 'सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात्, उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन जिसे विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-241(ख) के अधीन इस पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन यथा बिहार विधान सभा को उपस्थापित किया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम,2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय,मैं वित्तीय वर्ष 2017-18 के परिणाम बजट की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2017-18 के जेन्डर बजट की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

टर्न -11/अंजनी/दि0 27.03.2017

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा-31(3) के अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से समिति का प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) संख्या-614, 615, 624, 625, 627, 628, 630 एवं 631

अधिकाई व्यय के विनियमन पर प्रतिवेदन संख्या-617 एवं 620 तथा सी0ए0जी0 के विभिन्न वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं पर प्रतिवेदन संख्या-623, 626 एवं 629 की एक-एक प्रति बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम-239 के तहत सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है

टर्न-12/शंभु/27.03.17

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। वित्तीय कार्य लिये जायेंगे।

वित्तीय कार्य

गृह विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
जनता दल युनाइटेड	-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	39 मिनट
इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	-	20 मिनट
सी0पी0आइ0एम0एल0	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा	-	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	02 मिनट
निर्दलीय	-	03 मिनट

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 74,47,94,90,000/-(चौहत्तर अरब सैंतालीस करोड़ चौरानवे लाख नब्बे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री संजय सरावगी, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं और जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/- रू0 से घटायी जाय।''

राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी राज्य खुशहाल और विकसित तभी हो सकता है जब वहां की जनता अमन चैन से रहे और विधि व्यवस्था अच्छा कानून रहे। महोदय, राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चली है और वह पुनः 2005 के पहले की स्थिति में पहुंच रही है। प्रतिदिन अखबारों में अपराध और अपराधियों के कारनामे सुर्खियों पर होता है और दूसरी तरफ सरकार केवल चुप्पी ही नहीं कहें, बल्कि अपराधियों को पकड़े जाने या उनपर मुकदमा होने पर कमजोर पैरवी के कारण उनका बेल हो रहा है। साफ तौर पर कहें तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सरकार इन अपराधियों के सपोर्ट में खड़ी दिखती है। आज हत्या, लूट, रंगबाजी, डकैती, चोरी, बलात्कार आम बात हो गयी है। पत्रकार, राजनेता, इंजीनियर, व्यवसायी, ठीकेदार, मुंशी, छात्र-छात्राएं, अमीर गरीब, आम आदमी की हत्या प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। पुलिस महकमा भी भ्रष्टाचार में व्याप्त है। पूर्व डी0जी0 भिजलेंस पहले ही इसका खुलासा कर चुके हैं सारे सबूत के साथ। सरकार सड़क तथा अन्य योजनाओं में भी लगी निर्माण कंपनियों की समुचित समीक्षा नहीं कर पा रही है। यही नहीं सरकार के प्रशासन की स्थिति यह है कि 120 से ज्यादा आइ0ए0एस0 अधिकारी न्याय के लिए सड़कों पर उतरे हैं और आइ0ए0एस0 अधिकारियों का पुलिस पर भरोसा नहीं है। यही नहीं एक तरफ तो सरकार 350वें गुरू गोविन्द सिंह जयंती प्रकाशोत्सव के लिए पीठ थपथपाने का काम कर रही है, बड़ाई की बात है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पतंग उत्सव में प्रशासन की लापरवाही साफ उजागर हुई और कमजोर व्यवस्था के कारण 35 लोग गंगा नदी में डूबकर मौत के मुंह में चले गये। महोदय, सरकार जिसके दम पर कानून के राज का दावा करती है, उन्हीं पुलिसकर्मियों होमगार्ड के जवानों की सुविधा का ध्यान नहीं रखती। आज समान काम समान वेतन के उनके वाजिब मांग पर होमगार्ड के लोग हड़ताल पर हैं और सरकार के कान में जूँ नहीं रेंग रहा है।

अध्यक्ष : आज आपने अपने लिये 2 मिनट ही क्यों रखा, अन्य दिन तो 3 मिनट रखते थे।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : और लोगों को भी बोलने का समय मिलना चाहिए।

अध्यक्षः उस हिसाब से तो तीन मिनट से अधिक हो गया।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, कानून व्यवस्था में यह सरकार प्रतिदिन फेल हो रही है। अतः कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को खबरदार और सचेत करना चाहता हूँ, चेते नहीं

तो सिंहासन खाली करने की बात जनता करेगी। आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनपर काफी दबाव है इसीलिए उतना समय नहीं ले पाते हैं। हम तो कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से अरूण बाबू बोलें।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : हमें और लोगों का भी ध्यान रखना है।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आज माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा गृह विभाग का मांग प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में और अरूण कुमार सिन्हा जी के द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। महोदय, आज गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अनुदान मांग पर आपने समय दिया है सदन में बोलने के लिए इसके लिए आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। साथ-साथ गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के अनुदान मांग पर अरूण बाबू कटौती प्रस्ताव कर रहे थे। यह तो कटौती प्रस्ताव का लगता है माफिया शब्द असंसदीय नहीं हो तो यह तो लगता है कि कटौती प्रस्ताव का माफिया हो गये हैं। इनका प्रत्येक दिन कटौती प्रस्ताव रहता है- चाहे ग्रामीण विकास का हो.....

अध्यक्ष : आप गृह विभाग पर बोलिये।

श्री ललित कुमार यादव : निकाल दीजिए यदि माफिया शब्द असंसदीय है तो प्रोसीडिंग के पार्ट से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष : अगर अरूण बाबू का कहीं कटौती प्रस्ताव आता है तो अरूण बाबू तो काफी सज्जन व्यक्ति हैं आपको क्या एतराज है ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम आगे जाना चाहते हैं ये पीछे क्यों.....

अध्यक्ष : ललित जी, गृह विभाग।

श्री ललित कुमार यादव : गृह विभाग पर ही कह रहा हूँ। ये गृह विभाग पर कटौती प्रस्ताव लाये हैं तो कितना उचित है, कितना अनुचित है यह हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये ग्रामीण विकास विभाग पर भी इनका कटौती आता है। ग्रामीण विकास इनको गांव गंवई, किसान मजदूर से क्या लेनादेना है। ये नगर विकास पर इनका आता है तो ठीक है यानी कटौती प्रस्ताव गृह विभाग जैसे- माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की ये अवधारणा है कि सुशासन का राज, न्याय के साथ विकास का काम हम करेंगे और सुशासन का राज हम स्थापित करेंगे बिहार में, चाहे कितना बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे जो भी अपराधीकरण में सम्मिलित होंगे या अपराध में संलिप्त होंगे वे बख्शे नहीं जायेंगे। महोदय, ये बता रहे थे कि अपराधी लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। महोदय, चाहे सत्तापक्ष के लोग हों या कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, सरकार के द्वारा किन्हीं को संरक्षण और बचाव नहीं किया गया है। यह उदाहरण है, आप चाहियेगा तो सैकड़ों उदाहरण पेश कर सकते हैं। सरकार की नीति और नीयत साफ है, सरकार की नीति

और नीयत साफ है। सरकार का सुशासन का कार्यक्रम साफ है कि उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के साथ बिहार की जनता को हम सुशासन का राज देंगे। हम बिहार में सुशासन कायम करेंगे चाहे इसके लिए जितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देना पड़े नीतीश कुमार जी कृतसंकल्पित हैं और किसी से समझौता करनेवाले नहीं हैं। जनता को सुशासन मिलेगा.....क्रमशः।

टर्न–13/अशोक/27.03.2017

श्री ललित कुमार यादव : क्रमशः और न्याय के साथ विकास भी होगा । अध्यक्ष महोदय, हमलोगों की बिहार की धरती, हमेशा क्रांतिकारी की धरती रही हैं, एक से एक महोदय यहां आंदोलन हुआ है । चाहे हम पश्चिम चम्पारण का गांधी जी का सत्याग्रह की बात करें, चाहे हम महोदय जे.पी. की आंदोलन की बात करें चाहे महोदय हम 1990 में गरीब, दलित, अकलीयत के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालने की बात हो, यह क्रांतिकारी भूमि है, बिहार है, बिहार से ही क्रांतिकारी हुई है और लालू प्रासाद जी ने जो गरीब गुरूबा अल्पसंख्यक दलित को जो कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अमन–चैन दिया बिहार में महोदय, जिनको, हमलोग के पुरखा को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होता था महादेय, प्रखण्ड में हमलोगों को कुर्सी पर बैठकर पदाधिकारी से बात नहीं करते उसके आहाता में हमको जाने का इजाजत नहीं मिलती थी महोदय, महोदय इतना ही नहीं हमको बस में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, किसी भी कार्य में हम को अपना जो अधिकार है, हमको अपने अधिकारी से वंचित किया जाता था । 1990 में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ महोदय और लालू प्रसाद इस राज्य के मुखिया बने उसी का कारण है कि हमलोगों को बिहार में सामाजिक न्याय की झंडा का परचम फहरा रहा हैं । महेादय, मैं दूसरी उदाहरण देना चाहता हूँ 2014 का, जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी पूरे राज्य में घूम–घूम करके क्या क्या सपना लोगों को दिखलाया महोदय, एक लाख पच्चीस हजार करोड़ बोली लगाया महोदय, इस देश की इस राज्य की जनता को एक लाख पच्चीस हजार करोड़ के जो लोक–लुभावन वाले वायदा किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया महोदय और 2015 में आ जाइये महोदय, जो महागठबन्धन बना, जिसके नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री, जो सरकार के मुखिया हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और कांग्रेस की आदरणीय चैयरपरसन सोनिया जी, ये महागठबन्धन बना महोदय और जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी ने 2015 के नवम्बर में, कितना अंतर से? हमलोग दो तिहाई बहुमत से

चुनाव जीतकर आये महोदय, इनकी संख्या-91 हुआ करती थी महोदय, भारतीय जनता पार्टी की 91 की संख्या थी, इस विधान सभा के पहले महोदय 14 वीं विधान सभा में, 14 वीं विधान सभा में महोदय इनकी संख्या 91 थी और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के अगुआई में इनका जो सुशासन का कार्यक्रम, न्याय के साथ जो विकास का कार्यक्रम, उसके बल पर ये लोग कहां आ गये? ये लोग 53 पर पहुंच गये, इनको एहसास होना चाहिए कि सुशासन का राज्य है बिहार में, सुशासन के राज्य में, बिहार में महोदय, इनको अभी महोदय उत्तर प्रदेश में इनको जनमत मिला है, इनको..(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपस में टोका-टोकी नहीं करें, अभी माननीय सदस्य को बोलने में असुविधा हो रही है । आप भी बोलेंगे और कोई टोकेगा तो आपको भी असुविधा होगी । क्यों असुविधा का महौल पैदा कर रहे हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इनको यू.पी. में जनमत मिला है, हम यह नहीं कह रहे कि यू.पी. में आप जनमत, आप सीखिये संजय जी, सीखिये (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ललित जी, ये लोग जो बैठे-बैठे बोलते हैं, उसका संज्ञान आप नहीं लीजिये, आप अपनी बात बोलते रहिये, ये आपको उलझाना चाहते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : हम इनकी बात को संज्ञान में भी नहीं लेते हैं । ये खुद उलझ जायेंगे महोदय, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग साम्प्रदायिक पार्टी है महोदय और नीतीश कुमार जी हमारे जो मुखिया हैं महोदय, साम्प्रदायिक सद्भाव और साम्प्रदायिक सद्भावना को बिहार में महोदय बिगड़ने नहीं देंगे, इन लोगों को कुचल देंगे, इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मनसूबा रहता है कि बिहार में दंगा हो महोदय, लेकिन बिहार दंगा मुक्त प्रदेश रहेगा महोदय, हमारे मुखिया माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी का संकल्प हैं, ये लोग कितना भी दंगा फैलाना चाहेंगे, दंगा फैलने नहीं दिया जायेगा बिहार की धरती पर । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, ये एकदम कृतसंकल्पित हैं महोदय, जितना भी ये लोग भगवाकरण कर लें महोदय, बिहार में भगवाकरण चलने वाला नहीं हैं महोदय, अभी तो 53 पर आयें हैं महोदय हो सकता अगली बार तीन पर आ जायें महोदय । आज महोदय इनको लार टपक रहा है, इनको खराब लगेगा महोदय, इनको लार टपक रहा है, (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अरूण बाबू, सारी बातों का जवाब, जब आपके सदस्य बोलेंगे तो उनके माध्यम से दे दीजियेगा । ललित जी जारी रखिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अपने को ये राष्ट्रभक्त कहते है महोदय, दूसरे को ये राष्ट्रद्रोही कहते हैं महोदय, बहुत बड़ा राष्ट्र भक्त हैं ये लोग, ये भाई-भाई को कटवाना चाहते हैं महोदय । ये बिहार में दंगा करना चाहते हैं लेकिन इनकी जो मनसूबा हैं वह बिहार में पूरी नहीं

होगी । जाइये यू.पी. में यह मनसूबा कितना पूरा होगा आपका यह हम नहीं जानते हैं । आपको यू.पी. में मैन्डेट मिला है, आपने सरकार बनाया है, हम स्वागत करते हैं । जनमत को हमलोग सम्मान करते हैं महोदय, लेकिन कैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है उस पर भी टिका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं लेकिन कह रहे हैं कि अवैध बूचड़खाना होता हैं उसको हम बंद करेंगे, आप बंद कर दीजिये । आप बूचड़खाना बंद करिये हमलोगों को कोई एतराज नहीं है लेकिन महोदय ये भारतीय जनता पार्टी के जो एक्सपोर्टर है भारत के, बीफ के जो एक्सपोर्टर हैं महोदय, कितने लोगों का नाम है उसमें, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, वे बीफ के एक्सपोर्टर हैं महोदय और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में, हम ए.बी.पी. न्यूज पर देंख रहे थे, 50-50 लोग कौन खुराना, कौन पुराना तीन व्यक्ति का नाम दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हम 50-50 लाख रूपया चंदा दिये हैं वे कौन लोग थे । बीफ के एक्सपोर्टर सात लोग हिन्दू हैं महोदय, सात लोग हिन्दू हैं बीफ के एक्सपोर्टर और आप कहते हैं हम राष्ट्र भक्त हैं और दूसरे को राष्ट्र द्रोह कहना चाहते हैं आप यदि हिन्दू हैं तो हमलोग भी हिन्दू हैं, हमलोग आपसे बड़ा हिन्दू है, हमलोग हिन्दू के पुजारी हैं, आप दिखवाटी हैं, हमलोग असली हैं । उसमें जो महोदय, ये लोग बेनकाब हो जायेंगे, चार लोग उसमें हैं, चार लोग महोदय, चार लोग माड़वाड़ी हैं, तीन लोग ब्राह्मण हैं, कौन हैं बीफ एक्पोर्टर? बताये भारतीय जनता पार्टी के लोग । भारतीय जनता पार्टी से उसका संबंध है, महोदय, ये महोदय ये क्या बतायेंगे ? गृह विभाग सुन लीजिये, आपके सीट के तले आपका, नहीं कहेंगे इससे आगे, आपकी बैचेनी हो जायेगी । आपका जो है, आपका जो हैं, बिहार का जो है आप देंख लीजिये, बिहार की हत्या महोदय राष्ट्रीय औसत हैं 2.6 और बिहार का स्थान कौन है महोदय 12 वां । महोदय डकैती में 0.3, बिहार का क्या स्थान है महोदय छट्ठा, लूट में महोदय 2.9, इसका स्थान क्या है बिहार में 15 वां, चोरी में महोदय 22 वां, राष्ट्रीय औसत 37.2 हैं, महोदय, अपहरण में महोदय, महिला अपहरण में 26वां स्थान हैं, राष्ट्रीय औसत 53.9 है, महोदय बलात्कार में 5.7 है, इनका बिहार का स्थान है महोदय 30 वां, साम्प्रदायिक दंगा का महोदय, दसवां स्थान है बिहार का महोदय और इनका केन्द्र में भाजपा शासित राज्य है महोदय, उनका आंकड़ा सुन लीजिये, देख लीजिये आपको लगेगा, इनको महोदय पुलिस बल की संख्या जो इनको महाराष्ट्र में जो भाजपा शासित राज्य वहां उनकी जनसंख्या 11 करोड़ और प्रति लाख इनको पुलिस बल कितना महैया है महोदय-170.01 । महोदय मध्यप्रदेश में इनकी आबादी के अनुसार प्रति लाख 104 पुलिस बल की हैं, गुजरात में महोदय इनको 113.16 है महोदय । महोदय, छत्तीसगढ़ में इनको 184.50 है, झारखण्ड में इनको इस तरह से महोदय बिहार को महोदय कितना उपलब्ध हैं महोदय 68.81 महोदय ।

...क्रमशः...

टर्न–14/ज्योति

27–03–2017

क्रमशः

श्री ललित कुमार यादव : इस तरह से बिहार में कितना उपलब्ध है ? 68.81 प्रतिशत, हमको करीब 67 प्वायंट कुछ है पुलिस बल महोदय, हमारी सीमित संसाधन से जो पुलिस बल की हमारे पास प्रति लाख उपलब्धता है, उसका फीगर बता रहा हूँ और इनको महोदय, महाराष्ट्र में गुजरात में क्या और ये कहाँ हैं ? इनका जो ग्राफ है ये कहाँ हैं ? इनके राज्य में बिहार से ज्यादा लूट में, हत्या में, बलात्कार में, अपहरण में, डकैती में सारे केस में भाजपा शासित राज्य में ये आगे है । इनके भाजपा शासित राज्य की स्थिति जान लीजिये महोदय, ये किस स्थान पर हैं ? महोदय, मध्यप्रदेश में इनकी स्थिति जो है, ये दिल्ली सर, जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी रहते हैं जो हमारे देश की राजधानी है, उसका पुलिस विभाग, गृह विभाग किसके अंदर आता है ? वहाँ के प्रधानमंत्री के अंदर में आता है और प्रधानमंत्री के देख रेख में वहाँ का गृह विभाग हैं, राजनाथ जी वहाँ मुख्यालय में रहते हैं। महोदय, इनका राष्ट्रीय औसत 9.8 है और इनका दिल्ली में प्रतिशत 61.1 है कितना महोदय, इनका ज्यादा है 7.1 है दिल्ली में क्राईम रेट । इनका गृह भेदन में 61.1 है । इनका मध्यप्रदेश में 14.7 है । इनका हरियाण में 24.4 है । महोदय, महाराष्ट्र में इनका 13.9 है । छत्तीसगढ़ में 12.9 है । बिहार में मेरा कितना है 9.8 । सारे इनके राज्य से मेरा कम है महोदय और सीमित संसाधन है । हमको 67–68 के बराबर प्रति लाख पर पुलिस है इनको महोदय, कितना ज्यादा है दुगुना तीगुना इनको पुलिस बल है प्रति लाख जनसंख्या पर आप कहते हैं बिहार में कानून का राज्य नहीं है, बिहार में सुशासन नहीं है। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं जिस क्षेत्र में जाईये आपको लगेगा कि सुशासन का राज, कानून का राज है बिहार में । आप भाजपा शासित राज्य में जाईये आपको क्या स्थिति है आपके दिल्ली जैसे हम 9.8 है गृह भेदन में और आप हैं दिल्ली में 61.1 । आप मध्यपद्रेश में 14.17 है । हम आंकड़ा बतायें , इसीतरह से इनका चोरी में दिल्ली में है 500.3 । इनका हरियाण में 75.7 है । महाराष्ट्र में 51.3 है , बिहार में हम कितना है ? 21.8 हैं । आप आंकड़ा नेशनल क्राईम की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि तिगुना, चौगुना हरेक आपका जो आंकड़ा है क्राईम कंट्रोल का है , हमलोग बिहार बहुत पीछे है अन्य राज्य से क्राईम में हरेक मामले में , गृह भेदन में चोरी में, समान अपहरण में फिरौती अपहरण में महोदय, डकैती में महाराष्ट्र में इनका 0.7 है । झारखण्ड में 0.6 है । हम बिहार में 0.4 हैं । कहाँ आपका भाजपा शासित राज्य है । आपको पुलिस बल आपको तीगुना हमसे मिला हुआ है, दुगुना हमसे मिला हुआ है प्रति लाख पर लेकिन फिर भी आपके राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है, अराजकता की स्थिति है लेकिन हमलोगों का बिहार कितना पीछे है ? सुशासन

का राज है । महोदय, कानून का राज है । ये बता रहे थे कि एक से एक, बड़े से बड़े आदमी आए चाहे सत्ता पक्ष का एम.एल.ए. क्यों नहीं हो लेकिन आज जेल के अंदर है, उनको छोड़ा नहीं गया है । यही है सुशासन । यही है नीतीश कुमार का सुशासन और आपको लार टपकता है हमलोग जान रहे हैं । आपको महागठबंधन में दरार याद आते रहता है तो महागठबंधन में दरार दाल में कुछ काला है । क्या काला है ? इनका लार टपकता है कि कब हमको सरकार में नीतीश कुमार जी सम्मिलित कर लें, ये व्याकुल आत्मा है । भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है यह हमारे घर का मामला है । राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का मामला है, कौंग्रेस का मामला है, हम आपास में भाई भाइ हैं, हम परिवार हैं, हम संभाल लेंगे, हम साम्प्रदायिकों से हाथ मिलायेंगे क्या ? हम साम्प्रदायिक लोग से हाथ नहीं मिला सकते । हमारे मुखिया नीतीश कुमार साम्प्रदायिक लोग से चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शासन में रहें, नहीं रहें साम्प्रदायिक शक्ति से हाथ मिलाने का काम नहीं करेंगे । आप इस आशा में मत रहिये । अध्यक्ष महोदय, इनका झारखण्ड में धनबाद में जो डिप्टी मेयर थे दिन में सर ए0के0- 47 से भूंज दिया गया बीच चौराहे पर जैसे द्रौपदी का चीर हरण होता है, उसतरह से सरेआम लोग देखते रह गया और चार आदमी की और मृत्यु हो गयी । आज भाजपा के विधायक का नाम आ रहा है क्यों नहीं उसपर कार्रवाई की ? झारखण्ड सरकार को है हिम्मत कि उसपर कार्रवाई करे लेकिन इतना देर में नीतीश कुमार कार्रवाई करके दिखा देते । कौन आदमी है जो बच गया? हमारे जदयू के मेवा लाल चौधरी थे उनपर भी यदि एफ.आई.आर. हुआ तो वे भी कानून के शिकंजे से नहीं बचे, राज वल्लभ यादव पर भी कानून का शिकंजा कसा गया । एम.ल.सी. मनोरमा देवी का पुत्र का नाम आया उसपर भी कार्रवाई हुई । जो लोग महोदय, शासक नीतीश कुमार पर आप ऊंगली उठाते हैं, आप कहते हैं निरुपमा चौधरी ये महोदय, तीन चार घटना है ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की घटना हुआ, आपके मुजफ्फरपुर में निरुपमा चतुर्वेदी या चौधरी जो भी थी , निरुपमा चतुर्वेदी को हो, सिवान में राजदेव हत्या काण्ड हो, महावीर मंदिर से मूर्ति चोरी का मामला हो , बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मामला हो या विद्यालय परीक्षा समिति का पेपर लीक का मामला हो । महोदय, बिहार की पुलिस इतना काम कर रही है । आपने सी.बी.आई. को लेकर हंगामा किया कि सी.बी. आई. को जॉच दीजिये । ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्या काण्ड में कितना ताण्डव मचाये क्या हुआ सी.बी.आई. की जॉच तो हुई ? हमारी सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सी. बी.आई. की जॉच करवा दी, निरुपमा चक्रवर्ती जो मुजफ्फरपुर का मामला हुआ था महोदय, बालिका का अपहरण हुआ था या जो भी हुआ उसका मामला सी.बीब.आई. में गया उसका क्या हुआ ? राजदेव हत्या काण्ड की, रंजन पत्रकार हत्या काण्ड की, सी.बी. आई. जॉच हुई क्या हुआ ? आज जितने मामले में चाहे बिहार चयन आयोग कर्मचारी

चयन आयोग का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, सारे में बिहार पुलिस एस.आई. टी. का गठन हुआ है और जितनी मुस्तैदी से और जितनी कार्रवाई हुई है, सी.बी.आई. सौ साल में नहीं कर पायी । सी.बी.आई. की रिपोर्ट और बिहार पुलिस के एस.आई.टी. की रिपोर्ट देख लीजिये । आप किस पर शंका कर रहे हैं ? आप जो अच्छा काम कर रहै उसको आप रोज दिन कहते हैं कि बिहार पुलिस काम नहीं कर रही है, आप मनोबल बढ़ा रहे हैं कि मनोबल तोड़ रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, आज हम अमन चैन से है। जिसतरह से देश के बोर्डर पर हमारे आर्मी सिपाही रहते है, उसीतरह से बिहार में हमारे सिपाही हमारे जो पदाधिकारी हैं, उसके बल पर अमन चैन से बिहार की जनता है। महोदय, और उसी की आप आलोचना करते हैं, आप क्या चाहते हैं ? ये भाजपा के लोग क्या चाहते हैं ये पुलिस इंसपेक्टर बननाा चाहते हैं क्या? ये बिहार के एस0पी0 बनना चाहते हैं क्या ? ये डी.जी.पी. बनना चाहते हैं क्या ? कौन्सटेबुल बनना चाहते हैं क्या ? क्या जॉच खुद करेंगे क्या, कैसे इनको संतुष्टि होगी ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं, महोदय, मेरा समय है पार्टी का । जो शेष समय

अध्यक्ष : आप ही ने अपने लिए समय लिखकर भेजा है ।

श्री ललित कुमार यादव : मैं ही महोदय लिखकर भेजा हूं मैं ही महोदय अनुशंसा करता हूँ शेष समय में जो माननीय सदस्य हैं बोलेंगे । महोदय, ये बहुत जो हमारे बिहार पुलिस इतने अच्छे ढंग से काम कर रही है और ये एस.आई.टी. का गठन हुआ सारे में दूध दूध और पानी का पानी हुआ महोदय, ये कह रहे हैं कि महोदय, ये बोल रहे हैं कि जॉच निष्पक्ष नहीं हो रही है। लोगों को बचाया जा रहा है ? किस घटना में, आप नाम लीजिये, सारी घटना में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है । यहॉ सुशासन का राज्य है और हर हालत में सुशासन का राज कायम होगा । महोदय, हम एक दो बिन्दुओं की ओर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहते हैं । महोदय, नीतीश कुमार जी सुशासन का राज कैसे स्थापित किए हैं । हमारा राज्य छोटा है । हमारा क्षेत्रफल छोटा है । हम इससे अ्रांक नहीं सकते हैं ।

क्रमशः

टर्न–15/27.3.2017/बिपिन

श्री ललित कुमार यादवः क्रमशः आपका हो सकता है, आपका देश, देश के स्तर पर क्षेत्रफल बना है लेकिन बिहार राज्य महोदय, छोटा है । हम महाभारत का एक छोटा–सा उदाहरण महोदय, देना चाहते हैं । जब महोदय, धृतराष्ट्र ने जब दुर्योधन और युधिष्ठर का एक ही युवराज होगा, तो महोदय उन्होंने निर्णय किया कि किनको बनाया जाए, युधिष्ठिर को बनाया जाए कि दुर्योधन को बनाया जाए । महोदय, वह निर्णय नहीं ले सके । तब उन्होंने राज्य का विभाजन कर दिया महोदय और हस्तिनापुर का नरेश युवराज दुर्योधन को

बना दिए जो अहंकारी, अन्यायी, अत्याचारी था महोदय और युधिष्ठिर को, जो धर्मराज थे महोदय, उनको महोदय, खाण्डवप्रस्थ दे दिया और उस खाण्डवप्रस्थ को अपने मेहनत से उसको इन्द्रप्रस्थ बनाकर परिवर्त्तित किया महोदय । महोदय, कहीं-न-कहीं तो उसके मन में चोट था कि खाण्डवप्रस्थ इन्द्रप्रस्थ जो बनाए, वह बहुत छोटा राज्य है । हस्तिनापुर बहुत बड़ा राज्य है । महोदय, उनको, व्यास ऋषि जी आए और उनको महोदय, कहा कि युधिष्ठिर, तुम ऐसा राज्य स्थापित करो जो दुनिया का नजर तुम पर पड़े । महोदय, उन्होंने कहा कि हम छोटा-सा राज्य को हम कैसे दुनिया के नजर में और संसार के नजर में हम कैसे इतना बड़ा हम आगे हम राज्य को बढ़ा सकते हैं । कहा कि किसी भी राज्य की कसौटी क्षेत्रफल बड़ा हो या छोटा हो इससे नहीं आँकी जाती है । उस राज्य के राजा कितने शासक, कितना उनका शासन अच्छा है, कितना न्यायप्रिय शासन देता है और कितना आर्थिक-सामाजिक और गैर-बराबरी को मिटाने का काम करेगा, कितना छोटे-नीच के खाई को भरने का काम करेगा और जनता के बीच कितना सुशासन देने का काम करेगा । तो महोदय, युधिष्ठिर ने दिखा दिया । उसी तरह से बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार ने बिहार को सींच कर दिखा दिया है महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी को । आज बिहार से लोग सीखने का, बिहार को अनुकरण करने का महोदय, कोशिश करता है महोदय । बिहार को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है महोदय । हम छोटा राज्य हैं, हम छोटे राज्य के मुखिया हैं लेकिन हम इस राज्य को इस रूप में हम विकसित किए हैं, न्याय के साथ विकास किए हैं हम, अब आर्थिक-सामाजिक गैर-बराबरी को हम दूर किए हैं महोदय, हम महोदय, छोटे-बड़े के अंतर को हम समाप्त किए हैं महोदय । हम महोदय, इस राज्य को इतना ऊचाई पर ले गए हैं महोदय, जो आज देश और दुनिया में लोग बिहार के अनुकरण और सीखने का कोशिश कर रहे हैं महोदय । महोदय, आज जो बिहार का सुशासन है महोदय, हम बिहार के सुशासन, आर्थिक और सामाजिक न्याय की जो गैर-बराबरी की बात भी महोदय, हमारे जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, हमारे डिपुटी सी.एम., उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और इनका नेतृत्व महोदय, बिहार में चलता रहेगा और ये भाजपा के लोग कितना भी चाहेंगे, इनका लार टपकते रहेगा, इनको सत्ता से दूर होगा महोदय । अगले बार ये 53 से 3 पर आएंगे महोदय । इसी बात को कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही अहम् विषय पर चर्चा के लिए समय दिया है, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आज जिस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, तो हमलोगों के प्रख्यात कवि नीरज की पंक्तियों को मैं उल्लेख करना चाहता हूं महोदय --

एक मुहिम ऐसा भी चलाया जाए,

जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।

महोदय, उसी तर्ज पर हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के परिप्रेक्ष्य में उनकी जो सोच है महोदय –

एक मुहिम ऐसा भी चलाया जाए,
जिसमें बिहार के विधि–व्यवस्था को
मजबूत बनाया जाए।'

महोदय, राज्य ही नहीं देश भर में पूर्ण शराबबंदी का अभियान चलाया जाए । बिहार ही नहीं, देश भर में नशामुक्त समाज बनाया जाए । महोदय, मैं कहूंगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे देश में अगर कोई सोचता है तो हमारे मुख्यमंत्री सबसे पहले सोचते हैं और विधि–व्यवस्था तो, जो हमारा बिहार का है, वह पूरे देश के लिए आईकॉन है, पूरे देश के लोग बिहार की विधि–व्यवस्था से बिहार की सरकार के सोच से, बिहार के सरकार के कार्यक्रमों से सीख लेते हैं और पीछे–पीछे उसका अनुकरण करते हैं महोदय । यह बिहार की विधि–व्यवस्था है । बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर सामाजिक न्याय पर आधारित, सोशल जस्टिस पर आधारित कानून–व्यवस्था लागू कर रहे हैं और इसमें हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को सुलभ न्याय मिले, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील रहती है, चिंतित रहती है महोदय । यहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, राजा हो, प्रजा हो, चाहे व्यापारी हो, हर लोगों के साथ समान व्यवहार, सम्मान, इज्जत, उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, इस तरह का माहौल आज राज्य के अंदर जो हमारे विकास का दर बढ़ने का क्या कारण है महोदय ? राज्य के विकास के दर को बढ़ने में विधि–व्यवस्था एक बहुत बड़ा एक कारण है । बिहार की विधि–व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि आज देश के अन्य राज्य के लोग बिहार की विधि–व्यवस्व्था को सापेक्ष रूप में देखते हैं महोदय । यहां पर जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है महोदय, हर तरफ से हमलोग उसमें अगर देखा जाए तो हमारा राज्य इतना अच्छा है, आप किसी भी, चाहे हत्या का मामला हो, उसमें बिहार 12वें में है, डकैती का मामला हो, छठा है, लूट में पंद्रहवां है, गृह भेदन में 28वाँ है, चोरी में 22वाँ है, सामान्य अपहरण में 15वां है, फिरौती हेतु अपहरण में 17वाँ है, महिला अपराध में छब्बीसवां है, अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार में तीसरा है, बलात्कार जैसी घटनाओं में 30वां है, सामान्य दंगा में दूसरा है, साम्प्रदायिक दंगा में 10वां है, राज्य के विरूद्ध अपराध में तीसरा है, मतलब हम कहीं भी किसी भी आंकड़े में नम्बर वन नहीं हैं । हम हर जगह पर आंकड़े में बहुत दुरूस्त है महोदय । नम्बर वन अगर हैं तो हमारे जो साथीगण सामने बैठे हुए हैं अरूण बाबू, गृह विभाग पर भी कटौती लाए हैं । इनको तो गृह विभाग पर दस रूपया बढ़ाने का प्रस्ताव लाना चाहिए था कि राज्य में गृह, जो हमारा कानून–व्यवस्था मजबूत

हो, इसके लिए इनको उपाय बताना चाहिए था । तो सब चीज पर तो कटौती प्रस्ताव अरूण बाबू लाते ही हैं, आज गृह पर भी ले आए । चलिये ठीक है । आपकी पार्टी का फैसला है । चाहे घटोत्तरी में, कटौती प्रस्ताव लाइए या बढ़ोत्तरी का लाइए, आपको तो हम सलाह देंगे कि अंत में चर्चा के बाद आप अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ताकि बिहार का जो कानून-व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने में आपका भी योगदान हो । आज देश भर में आपका जहां-जहां भी राज्य है, चाहे आज आपको उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम दिन से आए हैं, लेकिन झारखंड बगल का हमलोग बिहार का हिस्सा है । झारखंड में ले लीजिए, झारखंड में आपके लोग रेकर्ड पर बोलें, न बोलें लेकिन अनचाहे बोलते हैं ...

(इस अवसर पर माननीय सभापति श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, झारखंड की सरकार, बिल्कुल ही कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। बगल में आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । आप कहीं भी देख लीजिए कि कहीं भी झारखंड में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है । आप बिहार की कानून-व्यवस्था के बारे में बोलते हैं । दिल्ली जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के देखरेख में चलता है, दिल्ली को आप देख लीजिए कि दिल्ली में आपका कानून-व्यवस्था क्या है । आप चाहे महाराष्ट्र में है, आपका गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, आपके जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, बिहार से उनका ग्राफ काफी ऊंचा है । हमारे ललित बाबू ने उन आंकड़ों को पढ़ा है, मैं नहीं चाहता हूं कि उन आंकड़ों को दुहराया जाए । आंकड़े जो हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री या प्रभारी मंत्री जवाब देंगे तो सभी आंकड़ों को आपको बताएंगे विस्तार में कि बिहार कौन-सा अपराध में कहां पर है । हमारे जो राज्य की पुलिस है, इतनी मजबूत है कि हर क्षेत्रों में कामयाबी उनका है, किसी भी तरह से यहां पर कोई हमारे पुलिस के आगे कोई चुनौती नहीं है... क्रमशः

टर्न : 16/कृष्ण/27.03.2017

श्री विनोद प्रसाद यादव (क्रमशः) आप अपराध पर तो कोई नियंत्रण नहीं लगा सकते हैं । आप कोई भी राज्य देख लीजिये । हमलोग रामराज को देख लें, रामराज में भी दंड प्रक्रिया थी तो दंड प्रक्रिया होना क्या द्योतक है ? रामराज में भी अपराध होते थे लेकिन रामराज में उस अपराधी को उनके अपराध के अनुकूल सजा दिया जाता था । इसीलिये उस को रामराज कहा गया । आज माननीय श्री नीतीश कुमार जी का भी जो राज है, अपराधी अपराध करते हैं ...

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है और सरकार के सभी मंत्री गायब हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मंत्रीगण है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री भी हैं । कृषि मंत्री हैं । समाज कल्याण मंत्री हैं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य,आप बैठ जाय । टोका-टोकी न करें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, हम चर्चा कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, 8 से 10 साल पहले भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चली, आज बिहार का मान-सम्मान देश में अदब से नाम लेते हैं । अपराधी चाहे जिस भी ऊंचाई का हो, जिस भी कद को हो हमारे राज्य की पुलिस उस के अपराध का उद्भेदन करने में कहीं कोई कोताही नही करते हैं, बड़ा से बड़ा आदमी अगर अपराध करता है तो राज्य की हमारी जो पुलिस हैं, उन को पाताल से भी खोज कर के उन को न्यायालय में समर्पित करने का काम करते हैं । इतनी हमारी पुलिस व्यवस्था मजबूत है । महोदय, हमलोगों को राज्य की पुलिस व्यवस्था पर फख्र है । हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो पुलिस पदाधिकारी है, वे दिन-रात विधि-व्यवस्था के संधारण के लिये, राज्य की उन्नति के लिये लगे रहते हैं, वे खाना, पीना, सोना भी त्याग सकते हैं लेकिन हमारे पदाधिकारीगण राज्य की विधि-व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं । सामान्य प्रशासन के हमारे अधिकारी भी राज्य की तरक्की के लिये सदैव काम करते रहते हैं । यही कारण है कि आज बिहार द्रुत गति से विकास कर रहा है, बिहार का विकास तेजी से हो रहा है । हमलोग चाहते है कि बिहार का विकास देश में ही नहीं, दुनिया में माना जाय, इसके लिये हमारा अधिकारियों से भी अनुरोध है कि आप बिहार के नाम को रौशन करने के लिये, बिहार को तरक्की के नंबर - वन पर लाने के लिये, दुनिया में बिहार का नाम रौशन हो, इसके लिये काम कीजिये और इसके लिये लोगों को उन के काम के अनुसार उन्हें ईनाम देने का भी काम किया है, उन्हें प्रोत्साहित करने का भी काम किया है । हमारे जो भी अधिकारी विधि-व्यवस्था को बढ़ाने में काम करते हैं, उन्हें सदैव समय-समय पर सम्मानित किया जाता है । मैं आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के लोगों को गुमराह कर के एक प्रचण्ड बहुमत देश के स्तर पर प्राप्त करने का काम किया है, आप गुमराह कर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किये लेकिन इन के सरकार बनने से असहिष्णुता का वातावरण बन रहा है, देश में या इन के शासित राज्यों में कहीं पर देखियेगा तो वहां के कई वर्गों के लोगों के मन में भय है । इनके शासन से लोग आतंकित हैं, उन के मन में लगता है कि सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करेगी । आज उत्तर प्रदेश में शासन में आते ही उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, उनके मन में भय व्याप्त है, उन के अंदर में काफी चिन्ता है कि यह जो सरकार है, भगवाधारी जो लोग हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिहार की विधि-व्यवस्था पर बोल रहे हैं या उत्तर प्रदेश की विधि व्यवस्था पर बोल रहे हैं ?

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : उदाहरण दे रहे हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं तो कह रहा हूं कि कैसे देश के अंदर असहिष्णुता का वातावरण बन रहा है । बिहार में कोई भी वर्ग, धर्म या सम्प्रदाय के लोगों के मन में टीस नहीं है, वह इसलिए कि यहां की सरकार सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति, सम्प्रदाय के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करती है, एक तरह से का कम करती है। लेकिन जो इन के राज्य हैं, वहां पर भेदभावपूर्ण शासन चलता है । वहां पर सत्ता के लोगों के लिये कुछ, विपक्ष के लोगों के लिये कुछ, कुछ सम्प्रदायों के लिये कुछ, इस तरह का माहौल देश के अंदर बनाने का काम किया जा रहा है । इस से देश की संप्रभुता कमजोर पड़ सकती है । मैं तो सलाह दूंगा कि ये अपने नेताओं को कहें कि इन के लोगों की अन्य राज्यों में जो सरकार हैं, सभी लोगों को ले कर के चले, सभी लोगों को मान-सम्मान दें । हमारे यहां विधि-व्यवस्था में सब लोग हर तरह से देश और राज्य की सरकार को सहयोग करते हैं ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री का नारा है कि सब का विकास । हमारी सरकार 16 राज्यों में है और केन्द्र में सरकार है तो जनता साथ है तब न हमारी सरकार वहां चल रही है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष का हमलोग सम्मान करते हैं मगर ऐसा केवल कथनी में नहीं, करनी में भी होना चाहिए । अगर ऐसी बात है तो आप के शासित राज्यों में लोग भयाक्रांत क्यों हैं ? उन के मन में डर क्यों है ? उन के मन में आक्रोश क्यों है ? आप देख लीजिये, जितने भी इनके शासित राज्य हैं, वहां पर तरह-तरह की सम्मान की बात है, वहां पर विसंगतियां हैं, वहां असहिष्णुता का वातावरण है, दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के साथ भेदभाव होता है । आज प्रधानमंत्री जी जैसा कि माननीय नेता,प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे देश के लोगों को मैं क्या कहूं, असंसदीय बात होगी, माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के लोगों को चकमा देने का काम किये हैं । क्या भाई, 15 लाख देंगे हरेक के खाते में, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल । किसानों को ड्योढ़ा लागत कुल जोड़ कर उन के फसल का देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिहार के चुनाव में कहा कि सवा सौ करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन सारी चीज भूल गये तो कैसे माने कि हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के साथ न्याय कर रहे हैं । उन का न्याय बिहार के साथ नहीं है । महोदय, मैं एक बात इन के सापेक्ष में कहना चाहूंगा कि इन का क्या काम है ? इनका काम है ।

''शहर में आये हैं बौने जब से,
लड़ाई होती है सदा कद और कामत के लिये । ''

महोदय, जब से ये सत्ता में आये हैं तब से ढिंढोरा पीटते हैं कि हम लोगों के कल्याणकारी काम कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे है । लेकिन जुमलेबाजी के सिवाय इन के प्रधानमंत्री और इन के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार से सीखना चाहिए, उन से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए । हमारे नेता इतने अग्रसोची हैं कि हर विषय पर उन का अपना एक विजन है और उसी विजन के आधार पर बिहार को आगे तरक्की पर ले जा रहे हैं । हमलोग बिहार के रास्ते देश को दिशा दिखलाना चाहते हैं कि बिहार जिस तरह से पिछड़ा हुआ राज्य था, आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जैसी तरक्की की है, वैसे ही हर जगह तरक्की हो । हर लोगों के जीवन में खुशहाली आये, हर लोगों को न्याय मिले चाहे, वह छोटा हो, बड़ा हो, कानून की दृष्टि से सबों को न्याय मिले, हमारा जो सात निश्चय है वह सात निश्चय लागू होगा, महिलाओं को पुलिस में भी 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, महिलायें पुलिस में आयेंगी और इस के साथ जब राज्य तरक्की पर जायेगा तो बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया में वह एक नम्बर पर होगा और नीतीश कुमार जी का विजन पूरी दुनिया में सराहा जायेगा । मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब इनलोगों की एक ही बात रह गयी है । लोग कहते हैं कि इनका कारोबार अब क्या है ? एक व्यक्ति से पूछे तो उस ने कहा कि :

''पूछते हो क्या कारोबार का,
अंधों के शहर में आईना बेचता हूं । ''

महोदय, इन का काम है यही है कि लोगों को गलत तरीके से भरमाना, लोगों को डायवर्ट करना, आपस में असहिष्णुता का वातावरण तैयार करना,भाई-भाई में झगड़ा पैदा करना, गरीबों से अमीरों को लड़ाना । महोदय, यही काम इन का अब रह गया है । पूरे देश की जनता इन के चरित्र को पहचान चुकी है । देश की जनता सही समय, सही वक्त का इंतजार कर रही है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण सिंह) : आप एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : सभापति महोदय, पूरे देश के लोग इन को सबक सीखने का काम करेंगे। मैं कुछ सुझाव पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को देना चाहता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप का काम सराहनीय है । आप राज्यभर के थानों को मजबूत बनाईये, राज्य भर के थानों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराईये, उन को नये-नये वाहन उपलब्ध कराईये, पेट्रौल, डिजल के मद में उन को काफी राशि दीजिये ताकि उन को काम करने में कोई कठिनाई न हो । राज्य में जितने थाने हैं, उन में जनता पुलिस सहयोग का माह में एक बैठक जरूर करने का निदेश दीजिये ताकि जनता और पुलिस के बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप है, जनता और पुलिस दोनों एक साथ थाने में बैठ

कर के समस्या का निराकरण करे । इस तरह का जरूर सुझाव राज्य के अंदर दीजिये । सभापति महोदय, मैं केवल एक बात मैं और कहना चाहता हूं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आप का समय समाप्त हुआ ।

टर्न–17/राजेश/27.3.17

श्री विनोद प्रसाद यादव : क्रमशः... सभापति महोदय, एक बात और मैं केवल अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा गया जिला झारखंड राज्य का सीमावर्ती जिला है और वहाँ करीब–करीब 40 थाने से भी ज्यादा थाने हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बोर्डिंग एरिया में हमारी सरकार ने जो शराबबंदी लागू किया है और झारखंड की सरकार हमारे शराबबंदी अभियान में सहयोग नही कर रही है, उसके लिए जैसे हमारे गया जिला का शेरघाटी अनुमंडल, झारखंड के सीमा पर है, शेरघाटी अनुमंडल के मोहनपुर, बाराचट्टी, शेरघाटी, डोभी.....

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप भाषण समाप्त करें । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: एक मिनट सर । महोदय, शेरघाटी, डोभी, इमामगंज, बॉके बाजार इत्यादि बोर्डर एरिया है, इन थानों को विधिवत् संचालन के लिए माननीय डी0जी0पी0 साहब यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, शेरघाटी अनुमंडल को पुलिस जिला बनावें और एक आई0पी0एस0 पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें शेरघाटी में, ताकि हम अपने शराबबंदी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू कर सके .....

(व्यवधान)

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार।

श्री जिवेश कुमार: सभापति महोदय, मैं माननीय श्री अरुण बाबू द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जाले विधान सभा की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ, अपने नेता को धन्यवाद देता हूँ । महोदय, हमारे यहाँ एक कहावत है कि:

''कापर करुं श्रृंगार, पिया मोरे आंधर ।''

महोदय, जिस विभाग के लिए आज बोलने के लिए उठे हैं,माननीय ललित बाबू हमारे जिला से आते हैं और बड़ी–बड़ी बात कर रहे हैं लेकिन सरकार का जो आईना है, हम उसी को दिखा देने का काम करेंगे अभी और महोदय, एक निवेदन करेंगे, हम आपका संरक्षण चाहते हैं सभापति महोदय.....

(व्यवधान)

श्री सदानन्द सिंह: महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । ''कापर करुं श्रृंगार पिया मोरे आंधर'', यह शब्द प्रोसिडिंग से निकल जाना चाहिए और यदि श्रृंगार करना है, तो नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर कर लीजिये ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, हमको आपका संरक्षण चाहिए । महोदय, हमें अच्छा लगा कि सदन के वरिष्ठतम सदस्य ने हमारी बात में बोलने के लिए .....

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखे । आप अपना बहुमूल्य सुझाव दें, अपने क्षेत्र की समस्या को रखें ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं, सत्तापक्ष के लोगों से निवेदन है कि उनके पास हमसे ज्यादा समय है, अगर कोई टिका-टिप्पणी करना हो, तो वे अपने समय में करें, हम तो केवल आईना दिखाने आये हैं, विपक्ष होने के नाते ।

महोदय, बिहार के अंदर माफियाओं को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण मिलने से शराबबंदी फेल हुई और गंभीर अपराध बढ़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि अपराधियों को सजा दिलाने में 68 प्रतिशत तक बिहार में कमी क्यों आ गयी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए । महोदय, आज अगर संज्ञेय अपराध की बात करें, कमाल है, काबिल सदस्य लोग उदाहरण दे रहे थे कि दूसरे स्टेट में जो बलात्कार हो रहे हैं, उससे कम हमारे यहाँ हो रहे हैं, भाई कुछ तो शर्म करें, आपको तो जवाबदेही लेनी चाहिए कि आपके स्टेट में एक भी बलात्कार ना हो, इसका अगर आप उदाहरण देते, तो मैं भी ताली बजाता आपके इस भाषण में । महोदय, संज्ञोय अपराध एक लाख, 89 हजार, 681 है, महोदय मर्डर प्रतिदिन बिहार में 7 से 8 होता है, अभी-अभी सीतामढ़ी में आधा घंटा पहले एक आदमी को गोली मार दी गयी है, अभी तुरत, तो 7 से 8 मर्डर प्रतिदिन बिहार के अंदर आज होता है, अगर रोकना है, तो इसे रोक लीजिये, आप कुछ कहने से पहले एक बार जरुर सोचिये कि 349 डकैती आपके यहाँ पिछले साल हुआ है, लूट के मामले में 1410 लूट, आप ही के नेतृत्व में इस बिहार में हुआ है और अगर महिलाओं के साथ छेड-छाड़ की बात करियेगा, तो 4511 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आप ही के इस बिहार में हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ महोदय और तो और बिहार में जो सरकार है, उसमें चोरवो का बहार है, 22,228 चोरी हुआ है पिछले साल, तो इसतरह से चोर भी मालामाल है महोदय, इसको रोकना चाहिए और अगर राईट की बात करते हैं, सम्प्रदायिक-सम्प्रदायिक चिल्लाने वाले बंधुओं आपके राज्य में 11,617 राईट हुआ है, आईना देखिये अपना और उसके बाद बोलियेगा, उसी तरह से किडनैपिंग के मामले में 7,324 किडनैपिंग आप ही के राज्य में हुआ है और यह दिसम्बर 16 तक का ही डाटा है, अगर तीन महीने का डाटा अभी आ जायेगा, तो पुराना रिकार्ड भी आपका फेल हो जायेगा और फिरौती के लिए महोदय, 37 किडनैपिंग

हुआ है, तो जो पार्टनर आये हैं, उसकी धमक सुना रही है, पहले जो फिरौती के लिए किडनैपिंग बंद हो गया था लेकिन आज पार्टनर का कमाल है कि उनके आते ही 2016 में 37 फिरौती के लिए किडनैपिंग हो गयी है महोदय और महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले लोग, आपके राज्य में 1,008 महिलाओं का 2016 में बलात्कार हुआ है, आपको जवाब इसका देना चाहिए और मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि उन सिसकती महिलाओं पर थोड़ा सा तो एहसान करो, कम से कम दोषियों को तो गिरफ्तार करो और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों केवल आई0ए0एस0 ही नहीं, अपने मंत्रियों पर भी कार्रवाई करो, तब सही सत्ता चलाने की बात करना और महोदय शादी के लिए रोज 8 से 9 अपहरण हो जाता है और प्रेम प्रसंग में इसी बिहार में रोज 4 से 5 लड़कियों को भगाकर ले जाया जाता है, पिछली बार सरकार ने जवाब दिया था कि दूसरे कॉस्ट में शादी करने का बढ़ावा दियाजा रहा है, हमको तो लगता है कि कहीं उसी का तो परिणाम नहीं है या पुलिस सोयी हुई है, यह उसका परिणााम है, निर्णय तो सरकार को करना है महोदय और अगर आप 15 दिनों का ट्रैक रिकार्ड देख लें सरकार का, तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आदरणीय ललित बाबू को भी इसका जवाब मिल जायेगा और पहले बोलने वाले साथी को भी जवाब मिल जायेगा ।

महोदय, 24 तारीख को 3 मर्डर बिहार में, 25 तारीख को एक मर्डर बिहार में, 26 तारीख को एक मर्डर बिहार में और तो और हुजूर नीतीश की लाश बोरे में मिली,यह मैं नहीं कह रहा हूँ अखवार कह रहा है, महोदय, 21.3.17 को प्रेम प्रसंग में नीतीश की लाश बोरे में मिली है हुजूर, यह अखवार कह रहा है, सड़क किनारे लाश मिला, उसपर किया ग्रामीणों ने हंगामा, 7 से 8 मर्डर प्रतिदिन , ए0टी0एम0 काटकर चोर उड़ा ले गये 12 लाख हुजूर इसी बिहार में और तो और गृह जिला में भी प्रेम प्रसंग में हत्या हो गयी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, यह तो कमाल ही हो गया, घर का ताला तोड़कर इस पटना की राजधानी में 40 लाख की लूट और तमंचा दिखाकर तमंचा पर डिस्को इस बिहार में और 7 लाख की लूट, इसी बिहार में हुजुर और चाकू मारकर युवक की हत्या इसी बिहार में हुजूर, पिस्तौल सटाकर ऑटो में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ इसी बिहार में हुजूर, पुनपुन में सो रही महिलाओं को गोली मार कर हत्या इसी बिहार में हुजूर और पुलिसकर्मी बना लुटेरा इसी बिहार में हुजूर, फुलवारीशरीफ में सामूहिक दुष्कर्म इसी बिहार में हुजूर और तो और कैशियर और गार्ड की हत्या इसी बिहार में हुजूर, पेट्रोल पंप से लूट इसी बिहार में हुजूर और बक्सर जेल के कक्षपाल को .....

(व्यवधान)

श्री मनीष कुमार: सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो ऑकड़ा पेश कर रहे हैं, वह किस किताब में लिखा हुआ है हुजूर .....

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखें । माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, बक्सर जेल के कक्षपाल को गोली मारी गयी इसी बिहार में हुजूर, महोदय, घर से बुलाकर छात्रा को गोली मारा इसी बिहार में हुजूर, मोतिहारी में एस0पी0 कार्यालय के सामने गोली मारा गया, इसी बिहार में हुजूर ।

क्रमशः

टर्न-18/सत्येन्द्र/27-3-17

श्री जिवेश कुमार (क्रमशः): हत्या के गवाह को जिन्दा जलाया गया इसी बिहार में हुजूर, जमुई में दो व्यवसायी की हत्या इसी बिहार में हुजूर, गोपालगंज में व्यवसायी से 50 लाख रू0 रंगदारी मांगी गयी इसी बिहार में हुजूर, दिन दहाड़े व्यवसायी पुत्र को मारी गोली इसी बिहार में हुजूर, मुंगेर में रोड पर दो युवकों को मारी गोली इसी बिहार में हुजूर, जमुई में दो व्यवसायियों की हत्या इसी बिहार में हुजूर, बाढ़ में चालक और गार्ड की हत्या कर कैश वैन से 60 लाख की लूट इसी बिहार में हुजूर ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): टोका टाकी नहीं करें ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, राज्य के 40 पुलिस जिलों में 33 जिला नक्सल प्रभावित है और चुनावी वर्ष में हुजूर शिक्षकों पर बड़ा प्यार आ रहा था आपको अब तो शिक्षक भी लाठी खा रहे हैं इसी बिहार में हुजूर और होमगार्ड के 70 हजार जवान जो आपकी सरकारी व्यवस्था को चला रहे हैं हुजूर और 70 हजार जवान अगर समान काम के लिए समान वेतन मांगते हैं तो उस पर लाठी इसी बिहार में हुजूर और थाने में पुलिस बल का अभाव जो है हुजूर और जो पुलिस बल है वह दारू पकड़ने में मशगूल है नतीजा कानून व्यवस्था ठप्प, सरकार बताये कौन है सुरक्षित बिहार में । पत्रकार की हत्या इसी बिहार में हुजूर, पुलिस की हत्या इसी बिहार में हुजूर, इंजीनियर ठीकेदार की हत्या इसी बिहार में हुजूर, राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की हत्या इसी बिहार में हुजूर, छात्र की हत्या इसी बिहार में हुजूर, व्यवसायी की हत्या इसी बिहार में हुजूर, घर से लूट इसी बिहार में हुजूर, बैंक में लूट इसी बिहार में हुजूर, रास्ते में लूट इसी बिहार में हुजूर, दुकान से लूट इसी बिहार में हुजूर, महिलाओं से बलात्कार इसी बिहार में हुजूर, नावालिगों से बलात्कार इसी बिहार में हुजूर, दलितों का उत्पीड़न इसी बिहार में हुजूर, डॉक्टा, जजों और ठीकेदारों से रंगदारी इसी बिहार में हुजूर और तो और राजधानी का आंकड़ा देते हैं हुजूर छोटा सा कि 2014 में 395 लड़का गायब हो गया पटना से केवल 176 को ढूंढ पायी सरकार 219 लड़कों का पता नहीं चला इसी बिहार में हुजूर और 214 में 245 लड़की का अपहरण हुआ इस बिहार में हुजूर, 28 वेटियां अभी तक बरामद नहीं हो सकी इसी बिहार में हुजूर और तो और 2015 में 348 बच्चों का इसी राजधानी से अपहरण हो गया

इसी बिहार में हुजूर और केवल 199 को खोज पायी पुलिस इसी बिहार में हुजूर और तो और 285 वेटियों में अबतक 79 वेटियां गायब हैं इसी बिहार में हुजूर और पूरे राज्य की ट्राफिक व्यवस्था का आईना दिखला दूं महोदय, अभी पूरे राज्य की ट्राफिक व्यवस्था को मैं जरा दिखला दूं आईना सरकार के लोग, मुखिया जहां बैठते हैं सरकार के पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी ट्राफिक में 540 पुलिस का पद खाली इसी बिहार में हुजूर और दरभंगा का इतना बुरा हाल है ट्राफिक में इसी बिहार में हुजूर और हम अपने जाले जाते वक्त बिना जाम झेले घर नहीं पहुंचते हैं इसी बिहार में हुजूर और महोदय, सरकार बताये कि पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर 7871 लाख रू0 में सरकार कितना खर्च पायी है। महोदय, राज्य के 55 जगहों में ई0पी0आर0 सिस्टम का क्या हुआ इस राज्य में हुजूर और मिस्ड टेक्नोलोजी पर हमें जवाब देने वाले हैं और दिये थे पिछली वार सदन में माननीय प्रभारी मंत्री बैठे हुए हैं, अगलगी पिछली वार रेकर्ड कायम किया था इसी बिहार में हुजूर और अभी तक मिस्ड टेक्नोलोजी वाला दमकल मिस्ड है, मिस्ड है, गायब है इसी बिहार में हुजूर और दो महीने बाद जब अगलगी शुरू होगी तो माननीय मंत्री मिस्ड टेक्नोलोजी वाला मशीन इसी बिहार खोजेंगे हुजूर और हुजूर ..

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री जिवेश कुमार: टाईम बचा हुआ है हुजूर, दो मिनट मेरा बचा हुआ है।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) एक मिनट आपका और समय बचा है ।

श्री जिवेश कुमार: मैं चाहता हूॅ आपसे दो मिनट हुजूर और न्याय की बात करने वाले उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े हो गये और कहे कि आपलोग गुंडागर्दी कर रहे हैं किसी को दो लड़का हो तो दोनों में बराबरी करना चाहिए अगर कब्रिस्तान के लिए 700 करोड़ देते हैं तो 80 प्रतिशत दूसरे लड़के के लिए 2800 करोड़ देना चाहिए था तब न्याय के साथ सरकार चल रही थी इसी बिहार में हुजूर ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मंदिर की भी घेराबंदी सरकार करा रही है ।

श्री जिवेश कुमार: बजट में पैसा नहीं है हुजूर और हुजूर (व्यवधान) जो वैध नहीं है, वही अवैध है और कानून जिसकी इजाजत नहीं देता है वही अवैध है और अवैध बूचड़खाने बंद होना आवश्यक है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) माननीय सदस्य, अब अपना भाषण समाप्त करें । आपका समय हो गया है एक मिनट अधिक हो गया है ।

श्री जिवेश कुमार: आखिरी हुजूर,...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव)माननीय सदस्य,आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री जिवेश कुमार: उप मुख्यमंत्री जी को बिहार दिवस में नहीं बुलाया गया हुजूर ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव)माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार ।

श्री ललित कुमार यादवः सभापति महोदय, माननीय सदस्य दरभंगा से आते हैं दरभंगा की पुलिस 25 वर्ष से कुख्यात अपराधी करतार सिंह जो सैंकड़ों लूट हत्या में फरार था महोदय अभी पुलिस कप्तान ने पकड़ा है । महोदय, दरभंगा में डबल मर्डर इंजीनियर की घटना हुई थी महोदय अभी दरभंगा पुलिस के कप्तान ने पकड़ा है । माननीय सदस्य दरभंगा से आते हैं एक शब्द उनको बोलना चाहते हैं महोदय, ये कहते हैं हुजूर, ओम नमः शिवाय, हुजूर, ओम नमः शिवाय।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) माननीय सदस्य आप अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

श्री राजेश कुमारः सभापति महोदय, मैं आज गृह कारा विभाग के आय व्यय शीर्ष के पक्ष में और विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । सभापति महोदय, हमारी जब महागठबंधन की सरकार जब बिहार में कानून की राज के सपनों को लेकर माननीय नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी और राहूल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में जब हमारी ये सरकार आयी तो बड़ा ही सोच के साथ आयी न्याय के साथ विकास सर्वोच्च प्राथमिकता थी विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करना और कानून का राज स्थापित करना । सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के लोग बहुत देर से जो है कुछ न कुछ कह रहे हैं लेकिन गृह विभाग ने भू-अर्जन के मद में 10 करोड़ रू0 का जो प्रावधान किया है वह समझिये कि ये बिहार के विकास के लिए और गृह विभाग के लिए यह महत्वपूर्ण जो है योजना साबित हुई है । आप कब्रिस्तान की बात करते हैं तो हमारे प्रतिपक्ष के लोग को पेट में दर्द होने लगता है, पता नहीं वह दर्द इनका किस टाईप का है और ये दर्द इतना पूराना है, इनका ये जो है उन 56 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं और वह दर्द खत्म हो नहीं रहा है इसीलिए मैं बतलाना चाहता हूँ कि गृह विभाग ने 8064 कब्रिस्तानों का घेराबंदी किया । (क्रमशः)

टर्न-19/मधुप/27.03.2017

...क्रमशः ...

श्री राजेश कुमार : 5234 कब्रिस्तानों का लक्ष्य था, वह पूरा किया और 1382 कब्रिस्तानों का कार्य प्रगति पर है । सभापति महोदय, बी0जे0पी0 के लोग बार-बार यह कहते हैं कि हम श्मशान की भी घेराबंदी कराते हैं लेकिन आपको यह जानना चाहिये कि मुख्यमंत्री स्वैच्छिक निधि विकास फंड जिसको विधायक स्वैच्छिक निधि भी कहा जाता है, पहले ही हमलोगों ने अपने क्षेत्रीय विकास के फंड से श्मशान के लिये अनुशंसा कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, यदि राष्ट्रीय आंकड़ा देखा जाय तो हम बताना चाहते हैं कि पिछले राज्य के कुल संज्ञेय अपराधों में वर्ष 2006 से 2015 तक राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार बिहार में 0.3 परसेंट का आंकड़ा है । जिस गुजरात मोडल

की बात की जाती है, हम गुजरात मोडल की बात करते हैं तो हमझते हैं कि यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि गुजरात में 3.38 परसेंट का अपराधिक आंकड़ा है । यदि हम आगे चलें तो हमारा पड़ोसी राज्य जो झारखंड है, विगत दिनों में ये बहुत जंगलराज की बात कर रहे हैं लेकिन झारखंड की बात क्यों नहीं करते हैं ? झारखंड में धनबाद भी एक जगह है और एक सप्ताह पहले वहॉ पर मेयर को जिस तरह से ए0के0-47 से भूना गया और चार लोगों की हत्या हो गई, उसपर क्यों नहीं बोलते हैं ? उस पर भी आपको बोलना चाहिये, झारखंड में तो आपका राज है । आप यह डायलेमा में मत रहिये, आपका आंकड़ा अलग होता है लेकिन मैं वास्तविक आंकड़ा के साथ आपके बीच सदन में खड़ा हूँ । आपको यदि यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको यह आंकड़ा उपलब्ध कराने को तैयार हूँ । आप आंकड़ें की बात करते हैं और आप जंगलराज की बात करते हैं, तो यह एकपक्षीय नहीं चलेगा । चूंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश का आंकड़ा 1.3 परसेंट है, महाराष्ट्र का 10.23 परसेंट और झारखंड का 0.62 परसेंट है और राजस्थान में आप विगत 10 वर्षों से राज कर रहे हैं और जिस तरह से राजस्थान का आंकड़ा आपको आईना दिखा रहा है, आप उस आंकड़ा का अध्ययन कीजिये, राजस्थान का आंकड़ा 5.36 परसेंट है । आप दिल्ली की बात करते हैं । दिल्ली में यह ठीक है कि किसी अन्य पार्टी के मुखिया हैं लेकिन दिल्ली का आंकड़ा जो देश का हमारा कैपिटल है, दिल्ली का आंकड़ा आपके बदौलत, आपके असहयोग के रवैया से 22.96 है चूंकि आप केन्द्र शासित राज्य के नाम पर दिल्ली को भी उचित सहयोग नहीं देते हैं और गृह विभाग वहॉ के केन्द्र सरकार के अधीनस्थ है इसलिये यह आंकड़ा आप पर है । इसपर भी आपको सोचनी चाहिये । दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि वर्त्तमान में जिस तरह से झूठ की खेती करके जनता को गुमराह करके 5 राज्यों में आपने सत्ता हासिल किया । कहा जाता है कि मैजिक है, किसका मैजिक है भाई तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैजिक है । हम यह मैजिक नहीं मानते हैं, आप सुनिये, यह मैजिक नहीं था, यह कोई प्रधानमंत्री का मैजिक नहीं था । यहॉ पर जो आंकड़ा बताता है, सरकार के विरोध में हवा थी, सरकार का एंटी-इंकंबेंसी था और विपक्ष के लोग उसको दर्शा नहीं पाये, उसको कलेक्ट नहीं कर पाये, उसके चलते आपको उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिल गया । यदि बी0जे0पी0 की हम बात करें आपको कुल 42 परसेंट वोट मिला और यदि एस0पी0 और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो 28.5 परसेंट का वोट प्राप्त हुआ और यदि अकेले बी0एस0पी0 की बात करें तो 22.5 परसेंट वोट मिला है । टोटल मिलाकर 51 परसेंट हुआ और लालू जी, नीतीश कुमार जी, सोनिया जी और राहुल जी ने, इस आंकड़ा को यहॉ लालू जी और नीतीश कुमार जी ने समझा और हमलोग प्रधानमंत्री का जो विजय रथ था, उसको बिहार की धरती पर रोक दिया । शायद इस आंकड़ा को वहॉ के विपक्ष के लोग यदि समझते तो आपकी रथ वहॉ भी

रूक जाती । मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि आप आंकड़ा देखकर बहुत उधम मचाते हैं कि हमारा बिहार में जंगलराज है लेकिन आप कहीं न कहीं भूल जाते हैं कि आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त का अपना सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन कहीं न कहीं आप जाकर बिहार की छवि खराब करने का काम करते हैं । आपने वोट के पोलराइजेशन के लिये, वोट एकत्रित करने के लिये अभिव्यक्ति के अधिकार को भी खतम कर रहे हैं । अभी उत्तर प्रदेश में योगी की आई हुई सरकार का कुछ दिन हुआ नहीं है, वहाँ एंटी-रोमियो काम चल रहा है और एंटी-रोमियो में हम समझते हैं कि लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है और किसी के अधिकार के हनन का आपको कोई अधिकार नहीं है । ठीक है, जनता ने आपको कुछ दिनों के लिये सत्ता दे दिया है । जो बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त देश का सपना देख रहे हैं, 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस ने आपको पीछा किया है तो यह भूल जाइये, 56 वर्षों से आप कांग्रेस को कोसते आये हैं और आज महागठबंधन को कोसते हैं, महागठबंधन की सरकार में फूट डालो और राज करो की नीति पर आप चल रहे हैं, हम समझते हैं कि आपकी फूट डालो राज करो नीति नहीं चलेगी, बिहार के लोग और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ महागठबंधन की सरकार विकास करेगी । आप कहते हैं, आप बोलते हैं कि हम मन्दिर की बात करते हैं मस्जिद की बात नहीं करते हैं । उत्तर प्रदेश में आप एक चीज बताइये, आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे लेकिन आप बताइये कि वहाँ अल्पसंख्यकों को कितना सीट आपने चुनाव लड़ने के लिये दिया ? आप कैसे एक भी सीट आपने अल्पसंख्यकों को लड़ने के लिये नहीं दिया और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ?

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपके पास सिर्फ एक मिनट का वक्त है ।

श्री राजेश कुमार : मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि आप विपक्ष की भूमिका जरूर निभाइये लेकिन कहीं न कहीं सरकार की छवि खराब करने के चक्कर में आप बिहार की छवि को खराब करते हैं । बिहार में जिस तरह से हमलोग अपनी सफलता का डंका बजाते हैं आप उतना ही बिहार की छवि को खराब करते हैं । हमने गुरू गोविन्द सिंह जी का 350वाँ जयन्ती मनाया, पूरे देश में क्या.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राजेश कुमार : पूरे विश्व में हमलोगों ने उसका डंका बजाया और आप उसका भी विरोध करते हैं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राजेश कुमार : हुजूर, एक मिनट । हमारी क्षेत्रीय कुछ बात है । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को कंक्लुड करता हूँ लेकिन एक छोटा-सा मेरे क्षेत्र की समस्या है कि मैं कुटुम्बा विधान सभा रिजर्व कंस्टीच्यूयेंसी से आता हूँ, मैं पहली बार सदन में आया हूँ,

वहॉ पर एक कुटुम्बा और एक अम्बा प्रखंड है और दो थाने हैं । इन दो थानों में दिनांक 10.3.2017 को कांड सं0 20/17 के अनुसार 400 अनामजद अभियुक्त बनाये गये थे ।

....क्रमशः ....

टर्न–20/आजाद/27.03.2017

....क्रमशः ....

श्री राजेश कुमार : लेकिन इसमें थोड़ा सा सरकार से आग्रह है, इसमें पहल की आवश्यकता है, उसमें दलित लोग हैं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राजेश कुमार : थैंक यू सर ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी । सेठ जी एक मिनट ।

श्री मो0 इलियास हुसैन : महोदय, मेरा एक सुझाव है, गुस्ताखी माफ करेंगे । माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी बोल रहे थे, अगर दुश्मन खेमे से अच्छी बात आती है तो उसे स्वीकार करनी चाहिए समाज हित में । बोलते–बोलते वो बोल गये कि योगी जी एन्टी रोमियो तो कौन बुरा काम कर रहा है, 10 लड़कियां कॉलेज में और 20 लोफर दरवाजे पर खड़े हैं, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, आज सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में राज्य आज अमन चैन की तरफ आगे बढ़ रहा है । महोदय, बिहार की भूमि सामाजिक परिवर्तन का अगुवा रही है चाहे वह चम्पारण का आन्दोलन हो या जे0पी0 आन्दोलन हो । 1990 में भी एक क्रांति हुई और बिहार की धरती पर गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए । अभी हाल में 2015 में बिहार ने एक आन्दोलन चलाया और 2014 से चल रही नरेन्द्र मोदी जी के आंधी को रोक कर महागठबंधन को अभूतपूर्व बहुमत दिया । महोदय, आप सभी लोग जानते होंगे कि लगभग 80 तरह का संगठन इन लोगों के पास चलता है और जब हमलोगों का महागठबंधन अंतिम क्षण में केवल एक साथ हो गया तो 100 से ज्यादा इनका संगठन चलता था, फिर भी सत्ता में हमलोग हैं और विपक्ष में ये लोग हैं और कटौती प्रस्ताव लगातार ये ला रहे हैं और आगे भी लाते रहे, हम इनसे अपेक्षा यही करते हैं कि हमलोग हमेशा पक्ष में रहे । चूँकि सरकार आती है और जाती है और लोग यहां के इतिहास के बारे में गवाह हैं । लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स करना ही गलत है लेकिन आज क्या एम0एल0ए0 में लोग नहीं

जीतते हैं, क्या आप उन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे तो आप अपनी ही चर्चा करें । जिस व्यापारी वर्ग के वोट बैंक पर आपलोग आते हैं, लेकिन आप व्यापारी हित की कौन सी बातें करते हैं । कौन सा संविधान में उनके एगेंस्ट में बात होती है तो आप उनके लिए रक्षक की तरह खड़े रहते हैं । ऐसा क्या आपने कभी किया है, ऐसा कोई कानून बनाया है तो कोई बड़ी बात हो सकती है ? नगर विकास की चर्चा हुई और नगर विकास में हमारे माननीय सदस्य उसी पक्ष से आते हैं । लेकिन कटौती प्रस्ताव एक चल रहा है, परिपार्टी है । ठीक है परिपार्टी चलती रहे, हमें कुछ नहीं कहना है ।

महोदय, हम अपने पक्ष को रखना चाहेंगे । बिहार की प्रबुद्ध जनता को जब 1 लाख 25 हजार करोड़ की अभूतपूर्व पैकेज का लालच भी दिया गया परन्तु जनता ने इस लालच पर भी ध्यान नहीं दिया और लालच और लालच देने वाले दोनों लोग ठुकरा दिये गये । बिहार की सरकार और बिहार की जनता खोज रही है परन्तु 1 लाख 25 हजार करोड़ रू0 का पता नहीं, कहां है, कहां है यह बिहार है, यह बिहार है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आसन की तरफ देखकर बोलें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : हमारी सरकार लोक कल्याण के लिए विकास की अमृतधारा को गांव-गली, दलित-पिछड़ों-अल्पसंख्यकों तक पहुँचाने के लिए कृतसंकल्पित है । हमारी सरकार लोक कल्याण के लिए विकास की अन्य धारा को उस रूप में उस जगह तक पहुँचायेगी । महोदय, ये लोग शोर मचाते रहते हैं अपराध के बारे में । भाजपा शासित राज्यों में, केन्द्र शासित दिल्ली में क्या हो रहा है ?

अगर अप्रील, 2015 से जनवरी, 2016 की आंकड़ों की तुलना अप्रील, 2016 से जनवरी, 2017 के आंकड़ों से की जाय तो अपराध के विभिन्न शीर्षों यथा हत्या में 22 प्रतिशत की कमी, लूट में 18 प्रतिशत की कमी, डकैती में 23 प्रतिशत की कमी, गंभीर दंगा में 33 प्रतिशत की कमी, फिरौती हेतु अपहरण में 42 प्रतिशत की कमी, बैंक डकैती में 11 प्रतिशत की कमी, बैंक लूट में 40 प्रतिशत की कमी, अनुसूचित जाति-जनजाति के विरूद्ध अपराध में 10 प्रतिशत की कमी आयी है ।

महोदय, अगर सही ढंग से देश के विभिन्न प्रान्तों से यदि अपराध के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो एक लाख की आबादी पर जितने अपराध पूरे देश में अलग-अलग प्रान्तों में होते हैं, उसमें बिहार 22वें नम्बर पर है और एक नम्बर पर दिल्ली जहां विधि-व्यवस्था केन्द्र सरकार के जिम्मे है। हमलोग वहां देखे हैं, पाये हैं, गये हैं । बिहार में हमारी महागठबंधन की सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने में समुचित कार्रवाई की है तथा राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम करने में पूर्णतः सफल है ।

साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर कमी आयी है । वर्ष 2014 में साम्प्रदायिक तनाव की 262 घटनायें प्रतिवेदित हुई, 2015 में 199 घटनायें

प्रतिवेदित हुई, 2016 में 181 घटनायें, वर्ष 2017 जनवरी तक 12 घटनायें प्रतिवेदित हुई हैं ।

इन सब सुधारों के पीछे हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश जी हैं । पिछले 11 वर्षों से अधिक से माननीय मुख्यमंत्री जी दिन-रात बिहार के विकास की ही बात सोचा करते हैं और यही कारण है कि शराबबंदी लागू की । शराबबंदी के लिए कोई जन आन्दोलन नहीं हुआ था । सभापति महोदय, आन्दोलन बिहार में नहीं हुआ था बल्कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ महिलाओं ने आवाज उठायी थी और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने उसे ग्रहण करते हुये शराबबंदी का कानून लागू किया । यह शराबबंदी राज्य में ही नहीं पूरे देश में प्रथम है । शराबबंदी गुजरात में भी हुई है परन्तु वहां शराब मिलना आम बात है । पता नहीं भौगोलिक ज्ञान ले लीजिए तो पता चलेगा कि आपका भौगोलिक क्या है और गुजरात का भौगोलिक क्या है ? हमने सिर्फ राज्य में शराबबंदी की बल्कि राज्य के कर्मचारियों, पदाधिकारियों के लिए भी शराबबंदी करते हुए उनको भी प्रतिबंध लगाया है । अगर वे अन्य राज्यों में भी शराब का सेवन करेंगे तो उनपर कठोर कार्रवाई की जायेगी । आज यही कारण है कि राज्य में अपराध घटा है और तेजी से अपराध घटा है और शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है । जो गरीब, मजदूर, कारीगर शराब पीकर अपने पत्नी एवं बच्चों को प्रताड़ित करते थे, उन्हें देय सुविधाओं से वंचित रखते थे, वह आगे बढ़कर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने एवं महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं ।

महोदय, मद्य निषेध के मामले में कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सुपौल, पूर्णिया, रून्नीसैदपुर, बैरगनिया, सीतामढ़ी, मुफस्सिल मोतिहारी, मखदुमपुर(जहानाबाद), मसौढ़ी, पटना, सुल्तानगंज भागलपुर, चांद, कैमूर, डेहरी, रोहतास मरंगा, पूर्णिया के थानाध्यक्षों को निलंबित किया गया है । विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । बेऊर थाना के थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी और थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ, दुल्हिन बाजार को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित किया जा चुका है । 3 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है । नगर थाना, गोपालगंज थाना में पदस्थापित 29 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में इन्हें निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

महोदय, यहां पहले एन0डी0ए0 की सरकार थी, जिसके नेता हमारे मुख्यमंत्री थे लेकिन जब भाजपा ने आक्षेप करना शुरू किया, देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना शुरू किया तो मुख्यमंत्री जी ने कठोर निर्णय लिया और अलग हो गये । उस समय भाजपा के लोग बहुत वाहवही करते थे कि भाजपा के ही वोट से मुख्यमंत्री हैं और जब 2015 का जब चुनाव हुआ तो इनकी सारी हेकड़ी गुम हो गई । हमारे मुख्यमंत्री जी

बने बनाये रास्ता पर चलना पसन्द नहीं करते बल्कि अकेले ही नया रास्ता बनाते हैं, भले ही अकेला चलना शुरू करते हैं लेकिन लोग जुड़ते चले जाते हैं, कारवां बनता चला जाता है ।

2014 के लोकसभा चुनाव में देश को भ्रम में डालकर के भाजपा के लोगों ने जो वोट हासिल किया, उसको अगले ही वर्ष 2015 में उसको बचा नहीं सकें । उनको समझ में आ जाना चाहिए था कि वोट आदमी के चाल, चरित्र और चेहरा से मिलता है, नारों से एकाध बार कोई दिग्भ्रमित कर सकता है लेकिन स्थायी रूप से किसी व्यक्ति को भ्रमित नहीं किया जा सकता है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व 7 निश्चय की घोषणा की थी, जिसके लिए राज्य की जनता ने वोट देकर के किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आते ही 7 निश्चय पर काम करना प्रारंभ कर दिया और उसी क्रम में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सरकारी नौकरी में आरक्षण सहित पेयजल, शौचालय, गली, नाली पक्कीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया । ऐसा शायद ही देश में कोई मुख्यमंत्री होगा, जो पूरे राज्य में घूम-घूमकर अपने निश्चयों को क्रियान्वित करने के लिए उस स्थिति में लाये होंगे ।

..... क्रमशः .....

टर्न-21/अंजनी/दि0 27.03.2017

श्री समीर कुमार महासेठ...क्रमशः....: सभापति महोदय, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून स्थापित करने की रही है और उसी के तहत सरकार ने यहां पुलिस विधेयक लाकर नये पारदर्शी कानून को लागू किया है । कानून का शासन स्थापित करने हेतु पुलिस आधुनिकीकरण के अंतर्गत पुलिस लाईन का निर्माण किया जा रहा है । जिसमें मधुबनी जिला भी पहला इसमें आनेवाला है । अपराध के वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत कार्रवाई किया जा रहा है । महोदय, मैं सदन को विभिन्न अपराधों में राष्ट्रीय औसत और उसमें बिहार के स्थान से अवगत कराना चाहता हूँ । हमारे बिहार का विभिन्न अपराधों में राष्ट्रीय स्तर पर स्थान निम्नप्रकार है । हत्या-12वां, डकैती 6वां, लूट-15वां, गृह भेदन 28वॉं, चोरी 22वॉं है । हमने विस्तृत चर्चा इसमें की है । महोदय, सही माने में जो भी हम कहें, एक तरफ लोग कहते हैं कथनी और करनी में बहुत अन्तर है । सोच अगर उस ढ़ंग से बनाते हैं तो उसी तरह का होगा । आप निश्चिततौर पर बिहार को बदनाम नहीं करें । हरेक जगह प्रिंट मीडिया, इलौक्ट्रोनिक मीडिया में आप आकर बिहार को बदनाम करते हैं । उसी तरह का पूरे देश में बिहार को जो उस शीर्ष पर लाया है, पुनः आप उसे कहां ढ़केलना चाहते हैं ? एलेक्सन तो होते रहेंगे बिहार के बदनामी में, कहीं-न-कहीं आपके बाल-बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है कि बिहार कहां जा रहा है । हम आपसे अनुरोध करते हैं अनुनय करते हैं, विनती करते हैं ।

व्यापारी वर्ग के जो आप अभिप्राय हैं आप उसको लेकर अपने आप को सबसे बड़ा मुखौटा समझते हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप उन चीजों को जरूर याद कीजिए । आदरणीय रमा देवी कितनी बार चुनाव जीती, स्वर्गीय मदन जायसवाल जी कितने बार जीते, संजय जयसवाल कितनी बार जीत गये लेकिन उनको कहीं मंत्री के लायक लोग समझ रहे हैं ? लेकिन हमारे गिरिराज भाई, पहली बार जीते और भारत के मंत्री बन गये तो यह बात आपको सोचनी चाहिए । पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है । आप कहां हैं, किसकी चर्चा करते हैं, किसके बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं ? 23 और 22 प्रतिशत हैं, उस आधार पर आते हैं लेकिन उसका प्रतिनिधित्व उस आधार पर नहीं देते हैं । आप कहां हैं, किसलिए हैं ? अन्त में, मधुबनी की चर्चा इसलिए करना चाहेंगे कि.....

(व्यवधान)

अभी तो हुआ है कब्रिस्तान का, आप कितने लोग कब्रिस्तान में राशि दिये हैं, इस बात की तो चर्चा करिए । मंदिर और मस्जिद में हमलोग तो देते ही रहे हैं । अगर हिम्मत है तो दीजिए । आपको कौन रोक रहा है ? केवल कब्रिस्तान पर चर्चा करके पूरा उत्तरप्रदेश जीतना चाहते हैं, यह गलत है, यह नहीं चलेगा । महोदय, अंत में मधुबनीवासी को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए चूंकि बहुत बेतरतीब तरीके से मधुबनी की आबादी बढ़ रही है । मधुबनी जिला की 40 लाख आबादी है और वहां पर एक भी ट्रैफिक थाना नहीं है, इसलिए हम सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप एस0पी0 से रिपोर्ट मंगाइए और जो अव्यवस्थित है ट्रैफिक सिस्टम उसमें सुधार कीजिए । साथ-ही पूरे प्रदेश में जो इनकम टैक्स देते हैं और जो आर्म्स अपनी सुरक्षा के लिए लेना चाहते हैं, इसके लिए सरकार इस पक्ष में रहे और वह एक ऐसा आधार बनाये ताकि उनको मिल सके । चूंकि पुलिस बल सभी को नहीं दिया जा सकता है । अगर हम अपने आत्मरक्षार्थ के लिए राइफल, रिवाल्वर लेते हैं.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका एक मिनट बचा हुआ है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : तो सरकार इसके लिए नियम बनाये । किसी व्यवसायी पर रंगदारी नहीं चले और अगर आप इनकमटैक्स पेयी हैं तो उसके लिए एक आधार बनाइए और उस आधार पर पूरे बिहार में संबंधित लोगों को राइफल, रिवाल्वर, बन्दूक देने का काम कीजिए ताकि वे सुरक्षित रह सके । कहीं उनको डर, भय न रहे और वह समाप्त हो जाय । इसके लिए सरकार को एक सोच बनानी होगी और कहीं-न-कहीं उनको उस रूप में समदर्शी रखना होगा । आधार ऐसा हो कि भविष्य में कहीं कोई गलती नहीं हो। मेरा मानना है कि पांच लाख-दस लाख जो टैक्स देते हैं, वह अपने रक्षार्थ के लिए अगर लेते हैं तो इसके लिए उन्हें छूट दी जाय । धन्यवाद ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री रमेश ऋषिदेव जी । आप अपना भाषण प्रारंभ कीजिए ।

श्री रमेश ऋषिदेव : सभापति महोदय, आज गृह विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, बिहार में सुशासन का राज चल रहा है । महागठबंधन सरकार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री, दलितों, शोसितों के मसीहा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं । बिहार सरकार अपने आप को छाती पर पत्थर रखकर इतना बड़ा कदम उठाया और वह बिहार में ही नहीं, पूरी दुनिया में जगजाहिर है । महोदय, जो शराबबंदी कानून लागू हुआ है, इससे खासकर जो बच्चियां हमारी स्कूल जाती थी साईकिल पर चढ़कर उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है । चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, हमारी बच्चियां साईकिल पर चढ़कर स्कूल जाती हैं, आज उनको आने-जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है । इतना-ही-नहीं सभापति महोदय, खासकर पूरे बिहार में, सभी जिला में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए थाना खोला गया है और खासकर आधी आबादी महिला के लिए महिला थाना खोला गया है । उसके लिए थाना में नयी गाड़ी की व्यवस्था की गई है । महोदय, पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए और क्रिमनलों से लड़ने के लिए आधुनिक हथियार की भी व्यवस्था की गयी है। सभापति महोदय, शराबबंदी जो हुआ, उसमें हमारे कुछ लोग चुटकी ले रहे थे कि यह चलने वाला नहीं है लेकिन अभी दिखायी पड़ रहा है शराबबंदी से कि सभी तपकों को लाभ हुआ है । चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, घर में जाते हैं तो चैन की नींद सोते हैं और हमारा पुलिस प्रशासन भी उतने परेशान नहीं रहते हैं । शादी-व्याह में शराब पीकर लड़ाई झगड़ा होता था, बहुत सारे लोग मारे जाते थे । जब किसी पर्व में मूर्त्ति का विर्सजन होता था तो उसमें भी नशा से लोग गोली मार देते थे । यह घटना बराबर होता था लेकिन जब से शराबबंदी हुआ है तो सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है । यह कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है । सभापति महोदय, अभी जो परीक्षा हुआ है मैट्रिक और इंटर की, उसमें किसी भी तरह का धांधली नहीं हुआ है और हमारे पुलिस प्रशासन को किसी भी तरह का मस्सकत नहीं करना पड़ रहा है । पहले जब परीक्षा होती थी तो किसी-किसी केन्द्र पर गाड़ी को जला दिया जाता था, दंगा होता था, जब से माननीय मुख्यमंत्री कमान संभाले हैं आज तक किसी भी तरह का दंगा नहीं हुआ है । वर्ष 2005 से ही सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है । सभापति महोदय, वर्ष 2015 की अपेक्षा वर्ष 2016 में अपराध में कमी आयी है । वर्ष 2015-16 में कुल संज्ञेय अपराध 2.93 प्रतिशत की कमी आयी है, हत्या में 18.78 प्रतिशत की कमी आयी है, डकैती में 18.07 प्रतिशत की कमी आयी है, लूट में 14.02 प्रतिशत की कमी आयी है, गंभीर दंगा 12.72 प्रतिशत की कमी आयी है, फिरौती में 36.21 प्रतिशत की कमी आयी है,

बलात्कार में 3.87 प्रतिशत की कमी आयी है, चोरी में 1.03 प्रतिशत की कमी आयी है, रोड डकैती में 3.42 प्रतिशत की कमी आयी है । सभापति महोदय, अन्य राज्य में, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां ज्यादे हुआ है ।

...क्रमशः.....

टर्न–22/शंभु/27.03.17

श्री रमेश ऋषिदेव : क्रमशः.....सभापति महोदय, जे0पी0 आंदोलन में जो हमारे सेनानी थे उनके लिए भी माननीय नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था किया है, उनको भी 5 हजार रूपया दिया जाता है। सभापति महोदय.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, केवल 2 मिनट आपका समय है। आप अपने क्षेत्र की बात रखें।

श्री रमेश ऋषिदेव : स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जे0पी0 सेनानी एवं उनके पति–पत्नी को भी आरक्षण दिया जाता है। वैसे स्वतंत्रता सेनानी को जिन्हें केन्द्रीय सरकार से पेंशन की स्वीकृति प्राप्त है उन्हें 1 अगस्त, 2015 के प्रभाव से विशेष भत्ता की राशि 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार प्रतिमाह के दर से किया गया है। सभापति महोदय, भागलपुर दंगा में जो मारे गये थे उनके आश्रितों को सरकार के द्वारा राशि मुहैय्या करवाया गया है। महोदय, दलित को पहले फुसलाकर के केस करवाया जाता था, जब से बिहार के विकास पुरूष नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने है तो टोला सेवक और विकास मित्र का बहाली करके पढ़ाने, लिखाने का काम किया है, सभी बस्तियों में पढ़ाया जाता है। तब से हमारे दलित लोग जिनसे बहला फुसलाकर के मुकदमा करवाता था, तब से कमी आया है। ये माननीय बिहार के विकास पुरूष नीतीश कुमार जी की देन है। अब कहीं कोई फुसलाकर केस नहीं करवा सकता है, गलत केस नहीं करवा सकता है।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : एक मिनट का समय बचा है माननीय सदस्य आपके पास।

श्री रमेश ऋषिदेव : सभापति महोदय, यू0पी0 में जो नये मुख्यमंत्री जी हुए हैं योगी जी, वहां दलित से महादलित से झाड़ू दिलवाने का काम कर रहे हैं। वह दिखायी नहीं दे रहा है हमारे बी0जे0पी0 के माननीय सदस्य को। महोदय, हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे मंत्री जी भी हैं कि 302 के मुकदमा में जिस कैदी को 20 वर्ष का सजा हुआ है और सजा उनकी पूरी हो गयी है। हमारे पुलिस प्रशासन के भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनको जिनका समय पूरा हो गया है उनपर भी विचार किया जाय और उनको छोड़ा जाय। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य डा0 रविन्द्र यादव जी। आपके पास 6 मिनट का वक्त है।

डा0 रविन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय हमारे दल के नेता का जो कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है दल के नेता के द्वारा उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अरूण बाबू ने कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : हुजूर, नेता बदल रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। हमलोग तो कब से टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि नेता अरूण बाबू बन जाएं।

डा0 रविन्द्र यादव : श्रीमान् हमारे दल के सचेतक हैं ये सचेतक नेता नहीं होते हैं क्या ? श्रवण बाबू, गृह एवं आरक्षी विभाग....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आसन की ओर मुखातिब होकर बोलें ।

डा0 रविन्द्र यादव : गृह एवं आरक्षी विभाग के मांग पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। महोदय, हमारे पूर्व के साथी कटौती की चर्चा कर रहे थे। ये सदन की परिपाटी है, सत्तापक्ष और विपक्ष, सत्तापक्ष के पास शासन की चाभी होती है और विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। जो विपक्ष सरकार को आइना दिखाता है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है वह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसके द्वारा ही दिखाये गये, कहे गये बात को- देखिए जब राजा चाटुकारों से घिर जाता है तो वह पतन और विनाश की ओर जाता है। इसीलिए कहा है हमारे यहां विद्वानों ने कि- निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय- निंदक को अपने निकट रखना चाहिए।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : ये संत कबीर की पंक्ति है।

डा0 रविन्द्र यादव : मेरा यह मानना है कि विपक्ष की बातों को भी धैर्य से सुनना चाहिए। आज एक ऐसे विषय पर हमलोग चर्चा कर रहे हैं।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : सरकार सुन रही है।

डा0 रविन्द्र यादव : मेरा यह मानना है कि सरकार जो है एक महत्वपूर्ण विषय पर यह सदन चर्चा कर रहा है और ये गृह एवं आरक्षी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। श्रीमान् मैं जो देख रहा हूँ जो स्थिति है कहां से शुरू करूँ कहां से अंत- मेरे पास जितना समय है श्याम जी उतने में ही गागर में सागर डालने का काम करूँगा। सर, मैं दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि- बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा और ये इतरा रहे हैं। तीन पार्टी की सरकार है, सरकार आपको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से चलानी चाहिए। आपकी स्थिति प्रदेश में अच्छी नहीं है और आप उस पार्टी से टक्कर लेने की बात करते हैं जो अभी-अभी चार राज्यों में जीतकर और केन्द्र में उसकी सरकार है। मित्रों साथियों, मैं अहंकार नहीं करता, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके नेता, आपके महागठबंधन के नेता नोटबन्दी का विरोध कर रहे थे। नोटबन्दी का विरोध मैं सोचता हूँ बोलना नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपके जेहन में यह बात दे देनी है। नोटबन्दी का विरोध कर रहे थे आपको शायद यह जानकारी नहीं है। माननीय

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नोटबन्दी का गरीबों ने पुरजोर समर्थन किया है और जहां-जहां भी नोटबन्दी के बाद चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत आया है और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी- श्रीमान् गृह आरक्षी विभाग की यह स्थिति है कि बिहार के अधिकांश जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं और उसमें हमारा एक जिला है जमुई।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : सुझाव दीजिए उसी पर ।

डा0 रविन्द्र यादव : हम उसी पर बोल रहे हैं। अजीब स्थिति है हमारे यहां पुलिस थाना जाने से पहले लोग सोचते है। हमारे यहां ही नहीं माननीय सदस्य सभी के यहां हमारे साथी बैठे हैं, आपसे मैं पूछता हूँ कि थाने की क्या स्थिति है- थाने की स्थिति है कि कोई गरीब आदमी थाने में पैर रखने से पहले सोचता है। बद से बदतर स्थिति है। उग्रवाद प्रभावित इलाके में जो हमारे यहां कार्यक्रम चल रहे थे.....क्रमशः।

टर्न-23/अशोक/27.03.2017

डा. रविन्द्र यादव : क्रमशः महोदय, आज देखिये आपकी बजट की जो स्थिति है, आज जो बजट की स्थिति है गृह विभाग की, वर्ष 2015-16 में पाचं हजार नौ सौ पन्चानवे करोड़, 2016-17 में सात हजार नौ सो संतानवे करोड़, 2017-18 सात हजार चार सौ, टोटल बजट का 1.3 प्रतिशत पुलिस पर खर्च होता है, अभावग्रस्त पुलिस है । होमगार्ड के जवान हड़ताल पर हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जजमेंट मेरे पास है, हम उसको पढ़ कर सुना रहा हूँ । श्रीमान् समय के परिधि में हमलोग बंधे हैं .....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): समय आपका बीतता जा रहा है ।

डा. रविन्द्र यादव : हमारे जिला में चार थाना, पूरे जिले में 15 थानें स्वीकृत हैं और उसके लिए जमीन भी अधिगृहित कर ली गई हैं, सरकार की रिपोर्ट भी आ गई हैं, हमारे क्षेत्र में चार थाना हैं, आश्चर्य की बात है कि सरकार वहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आश्चर्य की बात है कि हमारे यहां भगवान महावीर की जन्मस्थली हैं, अगर आपको आयना दिखाने लगूं, पढ़ने लगूं कागज तो घंटों बीत जायेगा ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप समाप्त करें ।

डा. रविन्द्र यादव : लछुआर गांव का थाना भी सैंक्शन है, लछुआर का थाना स्वीकृत है, 2015 में सैंक्शन हुआ, जमीन अधिगृहित हैं, मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि वे अपने उत्तर में इसके बारे में वक्तव्य देंगे । भगवान महावीर की मूर्त्ति वहां चोरी हुई थी, उग्रवाद प्रभावित जिले की स्थिति इतन बदत्तर है, एक कार्यक्रम हमलोगों के यहां चलता था, वह समाप्त हो गया ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया ।

डा. रविन्द्र यादव : महोदय, जमुई जिला में हमारे यहां, नक्सलाईट प्रभावित क्षेत्रों में, हमारे नक्सलाईट इलाका में.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप भाषण समाप्त करें ।

डा. रविन्द्र यादव : नक्सर्लाइट इलाके में जो भवन बनते हैं थाना के, जो सड़क और दूसरी कार्य हो रहे हैं, वहां जो स्कीम चलते थी वह बंद कर दी गई हैं और अभी 11 करोड़ लायब्लिटीज है जमुई जिला में । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ । मेरे पास जो कागजात है उसको प्रोसिडिंग्स का पार्ट बनवा दने की कृपा करें ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्या सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : सभापति महोदय जी, माननीय सोनिया गांधी जी को और हमारे उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को और राष्ट्रीय हमारे जनता दल के नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी और डिप्टी सी.एम. तेजस्वी जी और हमारे विधान मंडल दल के नेता सदानन्द बाबू को, मैं सभी को इस सदन की ओर से धन्यवाद देती हूँ कि उनलोगों के आशीर्वाद से मुझे बोलने का मौका मिला और यहां तक पहुंचने के लिए महागठबन्धन के सारे सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज 5 लाख 11 करोड़ 21 लाख 16 हजार का जो बजट पेश हो रहा है हम उसके समर्थन में खड़ी भी हूँ और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ी हूँ । आज महागठबन्धन की सरकार बनी और बिहार में जिस तरह से सरकार मजबूती रूप से आज बिहार में अपना एक साल का कार्यकाल पूरा किया उसी में सात निश्चय में शराबबन्दी को लाया, शराबबन्दी सभापति महोदय जी, यह क्राईम का बहुत बड़ा जड़ होता हैं शराब और उस शराब को बिहार में रोकने के लिए प्रशासन के लोगों ने भी शपथ लिया जिस तरह हमारे विधायक विधान सभा विधान परिषद् में लिया उसी तरह उनलोगों ने शपथ लिया कि न हम पीयेंगे न पीने देंगे और पीने वाले लोगों को रोकने का काम करेंगे और बिहार में शराब बन्दी को मजबूती रूप से सरकार के द्वारा माननीय हमारे मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शराब को रोकने के लिए दिन रात हमारे पदाधिकारी, बिहार के प्रशासन के लोगो ने कड़ी महेनत किया और रोकने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार में दंगा की बात हमारे विपक्ष करते हैं, आज बिहार में महिलायें सुरक्षित घूम रही हैं, कहीं न कहीं इस सरकार की देन है जो आज बिहार में महिलायें सुरक्षित घूम रही हैं और महिलाओं को उस जगह का दर्जा दिया, पंचायती राज्यों में पंचायती राज्य के लिये सभापति महोदय 50 प्रतिशत आरक्षण, यह बहुत बड़ी बात है महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए और आज बिहार में खास कर शिक्षा जगत में, नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, यह महिलाओं की बढ़ोत्तरी के लिये, महिलाओं के विकास के लये यह प्रयत्नशील गठबन्धन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी बात

है कि महिलाओं को उस जगह पर पहुंचाने का काम किया कि जहां महिलायें आज घरों में रहती थी और शासन पुरूष के लोग करते थें, हम यह कहना चाहती हूॅ कि आज महिलायें घर से बाहर निकली हैं, चाहे विधान सभा के स्तर पर या पंचायत के स्तर पर हो या पंचायत के स्तर पर हो, महिलायें आज बाहर निकर कर और पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आज बिहार में तरक्की और विकास के लिऐ आगे बढ़ रही है। जहां तक कि आज बलात्कार की बात हो रही है, घटनायें की बात हो रही हैं हम यह कहना चाहते है कि आपके कई एसे राज्य हैं जहां ये घटना घटती हैं, हम उस घटना की बात नहीं करते हैं कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है और आपके राज्य में क्या हो रहा है, हम यह कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में अगर किसी का बलात्कार, किसी महिला की छेड़खानी की घटना होती हैं तो हम सभी को निन्दा करनी चाहिए, निन्दा करने की जरूरत है । हम यह नहीं कहें, पार्टिकुलरली नहीं कहनी चाहिए कि हमारे उस राज्य में कम है और इस राज्य में ज्यादा है, हमें ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए उनकी निन्दा के साथ-साथ उन्हें बतलाने की जरूरत है कि घटना अगर घटी है, क्यों घटी है? उसका हमलोगों को दोनों दल, एक तरह से विधान सभा में हमलोगों यह कहा जाता हैं सभापति महोदय कि विपक्ष के लोग सरकार के अंग होते हैं । इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो दोनों को मिलकर इसका समाधान करने की जरूरत है, टिका-टिप्पणी करने की हम ज्यादा जरूरत नहीं समझते हैं। सही में आप भी जनता के प्रतिर्निधित्व करके आप भी विधान सभा पहुंचे हैं, जनता के आशीर्वाद से हम भी पहुंचे हैं, हम समझते हैं जो आपके मन है, वही हमारे मन में है, वही सरकार की सोच है कि बिहार को आगे ले जायं और बिहार क्राईम मुक्त बनायें और हम यह कहना चाहते हैं कि सभापति महोदय कि अपराध की जो घटना पूरे राज्य में, 29 राज्य है, और बिहार आज 22 वां स्थान प्राप्त किया है, घटनाओं की दृष्टि से आज 22 वां स्थान बिहार का है और यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय जी, बिहार की राजधानी पटना इकोनॉमिकल के नाम पर सुरक्षित हैं, दिल्ली से दूसरा स्थान आज बिहार को दिया गया है, यह हम नहीं कहते हैं, यह एन.एस.एस. की रिपोर्ट कहती है, नेशनल रिपोर्ट कहती है । हम यह कहना चाहते हैं कि कैपिटल जो हमारा ग्रोथ है बिहार में, पूरे राष्ट्र से आज छः माह में छः प्रतिशत, आज बिहार की जो स्थिति हैं आन्तरिक सुरक्षा की वह लाया गया है इसलिए आज ये कहते हैं, आज दलितों की बात करते हैं हम भी दलित समाज से आते हैं और दलित का सभी ने दुरूपयोग किया, उनकी ताकत, उनकी क्षमता को चाहे वह दबाने का मामला हो सभापति महोदय जी चाहे उनके केस दर्ज करने के नाम पर उनका प्रयोग करना ।

... क्रमशः ...

टर्न–24/ज्योति

27–03–2017 क्रमशः

सुश्री पूनम कुमार उर्फ पूनम पासवान : और आज गठबंधन की सरकार ने जो गांव में खासकर महादलितों के इलाके में पंचायतों में जो शिक्षा की बढ़ोत्तरी की, लड़कियों को आगे लाने का काम किया इसमें गिरावट आयी है और आज के दिन में बिहार में आज दलित काफी मजबूत महसूस कर रहे हैं और उसपर हमारी सरकार काम कर रही है । हम यह कहना चाहते हैं कि बिहार के माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी ने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है बिहारियों को कि उन्होंने गरीब गुरबा दलित सभी को मुंह में आवाज दी है ताकि थाना हो, कोर्ट हो कचहरी हो आप अपनी आवाज को बुलन्द कर सकते हैं आज कहीं पर भी हम नहीं समझते हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई जाति धर्म की बात होती है और सभापति महोदय जी, खासकर जिसतरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज कहते हैं कि हमने पॉच राज्यों में सरकार बना दी । आप किसतरह से सरकार बनाये हैं, दो राज्यों में चाहे मणिपुर और गोआ आप देख लीजिये उठा कर, महसूस किए वहॉ के गवर्नर ने कि हमसे गलती हुई है । उन्होंने महसूस किया कि हमसे गलती हुई है और लोकतंत्र की हत्या हुई है, इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं कि अगर आपमें अच्छी बात है जिसतहर हम कहते हैं कि गौ हत्या की बात करते हैं । सभापति महोदय जी, कभी अगर आपने सही में सब का साथ, सब का विकास, अगर हमारे विपक्ष के पार्टी के लोग करते, आज यू0पी में ..

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्या, दो मिनट है आप अपने क्षेत्र की भी समस्या रखें ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : तो आप यह महसूस करते होंगें कि यू0पी0 में चुनाव हुए कितने मुसलमान भाईयों को इन्होंने टिकट दिया । ये सब का साथ, सब का विकास यह दर्शाती है कितना सब के साथ, कितना सब के विकास के साथ इनकी सरकार चल रही है । मैं किसी व्यक्तित्व और विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ । हम एक बात और कहना चाहती हूं कि जिसतरह बिहार में आज हमारा पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि जिसतरह माननीय सभापति महोदय जी, जिसतरह थाना में दारोगा रहते हैं, उनकी सही सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए और जिसतरह केन्द्र के कर्मचारी होते हैं, उनके बच्चों के लिए एक स्कूल की व्यवस्था की गयी है और अगर जिला में खासकर पुलिस के बच्चों के लिए अगर एक स्कूल की व्यवस्था प्रत्येक जिला में हो जाय ताकि उनके बच्चे जो रहते हैं वो अचछी शिक्षा ग्रहण कर सकें और उनको यह लगे कि हम अपने परिवार को आगे ले जायेंगे । जबतक ये लोग मानसिक रुप से सही नहीं होंगे तब तक हम समझते हैं कि जो काम करने में जो इनको मेहनत करना पड़ता

है चाहे दिन हो या रात हो वो नहीं समझते हैं और अपने काम में लगे रहते ताकि मानसिक रुप के दबाव से वह निश्चिंत हो जांय । एक चीज और हम कहना चाहते हैं सभापति महोदय जी, आपसे कि हमारे यहॉ पे जो हमारे कोलासी थाना के अंतर्गत वहॉ गाड़ी की व्यवस्था की जाय । कई ऐसे थाना बन चुके हैं लेकिन वहॉ पर जाने के लिए काम करने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम सरकार के द्वारा उनके गाड़ी की व्यवस्था हो सके ताकि सुचारु रुप से वहॉ की व्यवस्था सुधारा जा सके और हमारे वहॉ फल्का ब्लौक में एक हम चाहते हैं कि सभापति जी आपके माध्यम से कि हमारे प्रभारी मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, हमारे फल्का और मोरसण्डा में एक पुलिस चौकी व्यवस्था की जाय मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिससे क्राईम को कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके, मैं इसके लिए तमाम सदन के लोगों को और सभापति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं । जयहिंद, जयभारत ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य महबूब आलम जी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री महबूब आलम : महोदय, धन्यवाद । महोदय, मैं दीपा कुमारी की बलात्कार हत्या काण्ड की बात से शुरु करता हूँ । दीका कुमारी की हत्या और बलात्कार की जो घटना है वह सरकारी दावों की धज्जियॉ उड़ा रही है । दीका कुमारी की हत्या रात के अंधेरे में, किसी सुनसान सड़क पर नहीं, किसी खेत खलिहान के गलियारे में नहीं, दीका कुमारी की हत्या सरकार संरक्षित वैशाली के अम्बेदकर विद्यालय के अंदर में हुई है । एक दिन पहले उस लड़की से उसकी मॉ मिलने गयी और उसने अपनी मॉ से कहा कि- मॉ, एक शिक्षक मुझसे अनैतिक रिश्ता बनाने का दबाव डाल रहा है और मैं तैयार नहीं हूं । मुझपर दबाव डाल रहा है । महोदय, दीका कुमारी की मॉ ने अपनी बेटी को वहॉ से वापस लाने की कोशिश की, मांग की लेकिन हिंदुस्तान में कौन ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा संस्थान हैं जो उसकी मां को उसकी बेटी को सौंपने के लिए तैयार नहीं है । उसकी मॉ को फाटक से धकेल दिया गया, फाटक बंद कर दिया गया और उस रात में उस लड़की की हत्या हो गयी और आजतक धारा 376, पौक्सो नहीं लगा है महोदय, दलित मुद्दों की तो बात होती है, दलित महिला माननीय सदस्या भी है लेकिन दोनों पक्ष के लोग इस दीका कुमारी की हत्या की बात पर नहीं बोल रहे हैं । मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि दो हत्यारे की गिरफ्तारी हुई है । अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है, 90 दिन होने को है अगर 90 दिन के अंदर चार्ज शीट नहीं हो तो दोनों बलात्कारी हत्यारे की भी रिहाई हो जायेगी । पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है । मुझे बोलने दिया जाय विशेष महत्व का मुद्दा है । रेप के नये कानून के तहत यह व्याख्या है ''If anyone touches the body of a women with an intention of immoral intention that will be supposed to be rape \''

तो महोदय, आजतक 376 की धारा क्यों नहीं लागू हुई, पौक्सो क्यों नहीं लागू हुआ ? दीपा कुमारी की बलात्कार और हत्या की काण्ड चीख चीख कर कह रही है कि यह सरकार की खामोशी जो है यह अपराधिक खामोशी है । माननीय मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं, माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए जबतक ये जवाब नहीं देंगे तबतक यह लड़ाई विधान सभा से लेकर सड़क तक चलेगी, इसको छोड़ा नहीं जायेगा इन बातों के साथ महोदय, मेरे माननीय सदस्य जो सत्यदेव राम जी हैं माननीय महोदय, उनको एक झूठे केस में फंसाया गया है साजिश के तहत । मुख्यमंत्री के बार बार आश्वासन देने के बाद भी हमारे आग्रह करने और निवेदन करने के बाद भी आजतक सी.आई.डी. की जॉच नहीं हो रही है।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायणा यादव) : माननीय सदस्या बेबी कुमारी जी 3 मिनट आपके पास है ।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, गृह विभाग पर सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर लाए गए कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूँ ।

सभापति महोदय, गृह विभाग पर पूरे राज्य में अमन चैन बनाये रखने का दायित्व है लेकिन पिछले दिनों से राज्य में अपराधियों का खुले आम तांडव हो रहा है । बैंक लूटे जा रहे हैं, ए.टी.एम. काटे जा रहे हैं । हत्याएं सरेआम की जा रही है । चोरियॉ लगातार हो रही है लेकिन चारे पकड़े नहीं जाते हैं । छोटी मोटी चोरियों की शिकायत करने तो लोग पुलिस थाने में जाते भी नहीं हैं । थाने का माहौल किसी शरीफ व्यक्ति के जाने लायक नहीं होता । वहॉ कोई एफ.आई.आर. करने जाता है तो सबसे पहले उसे अहसास होता है कि वही अपराधी है ।

सभापति महोदय, निरपराध लोगों को पुलिस द्वारा उकसा कर फंसाया जाता है । कोई आदमी किसी एक व्यक्ति पर एफ.आई.आर. करने जाता है तो उसे अन्य संभ्रांत लोगों का भी नाम देने के लिए कहा जाता है ताकि उसका भयादोहन हो सके । माननीय उच्चत्तम न्यायालय का आदेश है कि बिना इनवेस्टिगेशन के गिरफ्तारी नहीं हो लेकिन सामान्य जनों के लिए कोई इनवेस्टिगेशन नहीं होता । सीधे गिरफ्तारी होती है । बड़े बड़ं लोगों पर कोई कार्रवाई इनवेस्टिगेशन के बाद ही होती है । हर थाने में केस डायरी बात में भरी जाती है जिसके कारण मैनिपुलेशन होता है ।

सभापति महोदय, बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया कि ऑनलाईन एफ.आई.आर. की सुविधा प्रारंभ कर दी गयी है परन्तु आप देखिये कि पटना जिला में ही केवल ऑनलाईन एफ.आई.आर. की सुविधा है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायाण यादव): माननीय सदस्या आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, एक मिनट और दिया जाय । सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाह रही हूँ कि जब राज्य में आम आदमी सुरक्षित नहीं है ।.....

टर्न–25/27.3.2017/बिपिन

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आपका समय समाप्त हो गया । माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी, आप दो मिनट में अपनी बात रखिए ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, यह सरकार दलितों की दावा करती है, न्याय की बात करती है, विकास की बात करती है । जब से यह सरकार, आज नहीं, जब से यह सरकार कांग्रेस और राजद की और माननीय नीतीश कुमार जी की आई है, एक दोहरे डी.जी.पी. हुआ दलित का बेटा, रविदास का बेटा । आजादी के बाद प्रशासन में सरकार ही में नहीं, न्यायपालिका जिस तरह से भेदभाव करती, कार्यपालिका करती, विधायिका करती, उसी तरह पत्रकारजगत भी हमारे साथ भेदभाव करता है । कभी भी दलित का बेटा जो आई. ए.एस.–आई.पी.एस. बन कर आता है, जब सरकार कलम उठाती है तो जातीय समीकरण से, वोट के आधार पर डी.जी.पी. बनाती है, आई.जी. बनाकर भेजती है, क्षेत्रों में भेजती है । 405 डी.एस.पी. है, दर्जनों आई.ए.एस. और आई.पी.एस. हैं लेकिन पोस्टिंग जब होती है तो सरकार चुन–चुन कर जाति के आधार पर, चुन–चुन कर पोस्टिंग करती है । यही सरकार का असली चेहरा है । डीके का हत्या की हम बात करें, सरकार आज तक डी.जी.पी. पर ...

(व्यवधान)

चुप रहिए । सरकार चलती है चिल्लाने से नहीं ।

श्री श्याम रजक : सभापति महोदय.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य बैठ जाएं ।

श्री श्याम रजक: महोदय, सरकारें जाति से नहीं, नीतियों से चलती है और नीतीश कुमार जी की सरकार नीतियों से चलती है और नीतियां आज दलित के, पिछड़े के, दलित के समर्थन से चलती है, कोई जाति के आधार पर नहीं । कोई भी बैठेगा और यही सरकार है जहां महादलितों के लिए अलग से योजना बनाई, यही सरकार है जहां अत्यन्त पिछड़ों के लिए अलग आयोग बनने का काम किया और दलितों के लिए पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील रही है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, अब आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान: महोदय, माननीय श्याम रजक जी सरकार की वकालत कर रहे हैं, इसलिए कि सरकार में बैठे हुए हैं ....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): आप आसन के मुखातिब होकर ललन बाबू बोलें ।

श्री ललन पासवान: सभापति महोदय, हम दो सवाल इनसे पूछना चाहते हैं, सरकार से । 65,000 सिपाही है । आज के तारीख में 4320 सिपाही अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के 1120 है महोदय । सरकार कहती है आरक्षण की बात, पदोन्नति में आरक्षण बिहार में

समाप्त है । दावा कर रहे हैं, पदोन्नति में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आरक्षण प्रमोशन में बंद कर दिया है सरकार और यह दावा करती है सरकार । पदोन्नति में आरक्षण नहीं है...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): आप आसन ग्रहण करें । आपका समय हो गया है ।

श्री ललन पासवान: सभापति महोदय....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): दो ही मिनट आपका है, और माननीय सदस्य हैं बोलने के लिए।

श्री ललन पासवान: सभापति महोदय, सरकार दलितों को पुलिस में बहाल विशेष अभियान करके कब चालू करेगी, कब हमारे लोगों को बहाली करेगी ? बैकलॉग खाली है । सरकार आरक्षण विरोधी काम कर रही है महोदय । मेरे यहां...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आपका समय हो गया है माननीय सदस्य ।

श्री ललन पासवान: महोदय, मेरे यहां चेनारी में...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्या श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम: सभापति महोदय, सरकार के द्वारा प्रस्तुत 2017-18 का गृह विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं और आपका मैं आभार प्रकट करती हूं।

महोदय, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । हमारे नेता माननीय लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस राज्य में अमन-चैन कायम हो गया है । हमारी पुलिस आधुनिक तरीके से अनुसंधान कर रही है । अनुसंधान में कमियों का निराकरण किया जा रहा है ।

महोदय, विपक्ष के लोग खासकर भाजपा के लोग अपराध बढ़ गया, अपराध बढ़ गया का हल्ला मचाते रहते हैं लेकिन भाजपा शासित राज्यों में और केन्द्र शासित दिल्ली में क्या हो रहा है, सबको पता है । अगर अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 के आंकड़ों की तुलना अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 के आंकड़ों से की जाए तो अपराध की विभिन्न शीर्षों, यथा, हत्या में 22 प्रतिशत की कमी, लूट में 18 प्रतिशत की कमी, डकैती में 23 प्रतिशत की कमी, गंभीर दंगा में 33 प्रतिशत की कमी, फिरौती हेतु अपहरण 42 प्रतिशत की कमी, बैंक डकैती में 11 प्रतिशत की कमी, बैंक लूट में 40 प्रतिशत की कमी, अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराध में 10 प्रतिशत की कमी आई है । महोदय..

(व्यवधान)

महोदय, अगर देश के विभिन्न प्रांतों से देश के अपराध के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो एक लाख की आबादी पर जितने अपराध पूरे देश में अलग-अलग प्रांतों में होते रहे हैं उनमें बिहार 22 वें नंबर पर है । एक नंबर पर दिल्ली है जहां विधि-व्यवस्था केंद्र सरकार के जिम्मे है । बिहार में हमारी महागठबंधन की सरकार ने

कानून-व्यवस्था सुधारने में समुचित कार्रवाई की है तथा राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द और साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम करने में पूर्णतः सफल है । महोदय, साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर कमी आई है । वर्ष 2014 में साम्प्रदायिक तनाव की 262 घटनाएं प्रतिवेदित हुई, 2015 में 199 घटनाएं प्रतिवेदित हुई है, 2016 में 181 घटनाएं, वर्ष 2017 में जनवरी तक 12 घटनाएं प्रतिवेदित हुई है ।

महोदय, अब मैं सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करना चाहूंगी । वर्ष 2017-18 में थाना भवन, आवासीय भवन एवं आउटपोस्ट के निर्माण हेतु भू-अर्जन मद में 10 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है । महोदय, पुलिस भवन निर्माण मद के अंतर्गत राज्य के 567 थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए दो-दो अदद शौचालय और स्नानागार का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है । राज्य के सभी जिलों में मादक पदार्थो के रख-रखाव हेतु स्टोरेज फैसिलिटी के निर्माण की स्वीकृति दिए गए हैं । 65वीं अखिल भारतीय कुश्ती कलस्टर प्रतियोगिता के लिए 2016 के लिए बी.एम.पी.-5 पटना परिसर में मल्टीप्लेक्स इंडोर स्टेडियम और जीम भवन तथा खेल उपकरणों के क्रय की स्वीकृति दी गई है ।

महोदय, पुलिस प्रशासन के ढाँचागत सुदृढ़ीकरण अंतर्गत राज्य की सभी चालीस जिलों एवं चार रेल जिलों के 1056 थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा अधिष्ठापित किया जा रहा है । सभी जिलों के साइवर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय की कार्रवाई तथा थाना/ओपी, जिला मुख्यालय एवं पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत बल के लिए वी.एच.एफ. सेट का क्रय किया जा रहा है ।

महोदय, पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जा रही है । महोदय, कब्रिस्तानों की घेराबंदी के अंतर्गत कुल 8084 कब्रिस्तानों में से 5234 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1382 का कार्य प्रगति पर है ..

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष महोदय, देश में पहली बार हमारे माननीय लालूजी, नीतीश जी तथा तेजस्वीजी के नेतृत्व में मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजना के अंतर्गत राज्य के मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण करने की कार्रवाई की जा रही है । शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण का अवसर प्रदान करने हेतु ठोस, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से गुड गवर्नेंस की दिशा में सरकार द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस दिनांक 5 जून, 2016 को पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 को लागू किया गया है ।

महोदय, नियत समय सीमा में सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 14करोड़

से अधिक सेवाएं प्रदान की गई है । जनहित में इस वर्ष इसके अंतर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तीन नई सेवाएं जिसमें नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पण जोड़ी गई है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को, हमारे मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह बात सत्य है कि आर.एस.एस. के पहल पर भारत सरकार के द्वारा बाबा साहेब अम्बेदकर के लिखित संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है एवं दलित आदिवासी के आरक्षण को खतम करने की पहल की जा रही है । मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से चाहती हूं कि पूरे बिहार में दलितों, आदिवासियों एवं अन्य सबों का चिंता का विषय है एवं यह शायद एक जन-आन्दोलन का विशाल रूप ले सकता है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न : 26/कृष्ण/27.03.2017

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी । क्वेश्चवन आवर में मैं इस समस्या को रखी थी । मैं नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि हमारे कटोरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड में चिड़िया मोड़ में एक चेक-पोस्ट की अतिआवश्कता है । इस के लिये मैं आप से अनुरोध करूंगी । आप ने मुझे समय दिया, इस के लिये मैं आप का आभार प्रकट करती हूं । धन्यवाद । जयहिंद ।

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर । आप का 5 मिनट समय है । 6 मिनट में दो-दो मिनट कर के पहले के वक्ताओं ने ले लिया ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं । अपने नेता आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी और आदरणीय श्री अरूण कुमार सिन्हा जी को भी धन्यवाद देता हूं और मधुबन की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिस के आर्शिवाद की वजह से मैं यहां खडा हूं, आप सब के सामने बोलने के लिये खड़ा हूं । अध्यक्ष महोदय,संसार का एक अघोषित नियम है कि जो चीज आगे नहीं बढ़ती, उसे पीछे ढकेल दिया जाता है । जहां प्रगति नहीं होती है, वहां दुर्गति होती है । जहां उन्नति नहीं होती है, वहां अवनत्ति होती है । जहां विकास नहीं होता है, वहां विनाश होता है । जहां चलना नहीं होता है, वहां रूकना होता है । बिहार की सरकार यहां की कानून-व्यवस्था कहीं न कहीं ठहर सी गयी है । इसी बिहार में हुजूर लगातार हमारे कई मित्रों ने और हमारी पार्टी के जिवेश कुमार जी ने आज सरकार में जो घटनायें घट रही है, उस का जिक्र किया है । मैं कुछ सुझाव और समाधान के साथ सरकार के सामने खड़ा हूं । मैं कटौती-प्रस्ताव के पक्ष में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि कई मित्रों ने

समस्याओं का जिक्र किया है । मैं समाधान पर थोड़ा बोलना चाहता हूं । हमारे यहां जो पुलिसिंग है और हर काम में जो पुलिस को याद किया जाता है लेकिन सरकार से मेरा एक प्रस्ताव है, एक मांग है कि जो पुलिस लॉ एण्ड आर्डर में लगी है, उस को इन्वेस्टिगेशन से हटाया जाय, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो अनुसंधान करनेवाली पुलिस हो, उस के लिये एक अलग टीम बनायी जाय । ऐसा इसलिए कहता हूं कि अभी अनुसंधान के दो लाख से ज्यादा मुकदमें अनुसंधान की वजह से पेंडिंग पड़े हुये हैं और इस की वजह से बिहार की जनता को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कहीं न कहीं जनता इससे परेशान होती है । सिर्फ उस से उगाही की जाती है । यह सबों का विषय है । एजेंसी जैसे सी0आई0डी0, सी0बी0आई0 है अपने देश में है और बिहार में भी है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वेस्ट बंगाल की सरकार ने 15 साल पहले अपने सी0आर0पी0सी0 में संशोधन कर के उस में प्रावधान किया था कि कोई भी केस हो, किसी भी तरह के मुकदमें हो, तीन साल से ज्यादा पुलिस उन को अपने पास लंबित न रखे । पुलिस को तीन साल से ज्यादा लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं होता । महोदय, मैं यह आप के माध्यम से कहना चाहता हूं । महोदय, यह विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि

There is a beautiful saying

जौन आर्थर बार्कर साहब की एक saying है कि

Vision without action is merely a dream,
and action without vision is just passes the time
but action with vision can change the world.

मुख्यमंत्री जी आये हैं मैं उन का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । क्योंकि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप ही समस्या है और यह बात हम सबलोग इसको मानते-जानते भी हैं कि

Water percolate from top to bottom.

सीढ़ी की सफाई ऊपर से होती है । हमलोग नये मेम्बर हैं । आज थानों की हालत क्या है ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । हम नये मेम्बर है । हम कुछ सदन में सीखते जानते हैं। लेकिन यह सच्चाई बयान करनी होगी और उस को मानना भी होगा ।

एक मिनट सर । इसी राज्य बिहार में मुख्यमंत्री ने ओथ लिया था और इनका बहुत बढ़िया एक इन्टरव्यू पढ़ा था और इन्होंने अपनी प्राथमिकतायें बतायी थी कि गुड गवर्नेस, गुड गवर्नेस, गुड गवर्नेस । मैं यह समझता हूं, आज इस बात से सहमति रखता हूं कि केवल गवर्नेस रह गया है, गुड पीछे छूट रहा है । महोदय, यह चिन्ता का विषय है । क्योंकि आपके राज्य में थाने बिक रहे हैं । मैं कई लोगों से मिल कर आया हूं, एक अच्छा सुझाव है, मुख्यमंत्री जी बैठे हुये हैं । इसलिये यहां रखना चाहता हूं कि

अगर एक मापदंड बन जाय कि किसी थाने में अगर सेम नेचर का केस 1 से 3 तक हो जाय या 5 तक जाय तो किसी न किसी को रेस्पौंसिबुल बनाया जाये, रेस्पौंसिब्लिटी शब्द है, Ability to Respond. तो SHO को रेस्पौंसिबुल बनाया जाय । इसी प्रकार 25 से 30 मामला होता है तो वहां के अनुमंडल के एस0डी0पी0ओ ,को रेस्पौंसिबुल बनाया जाय, सेम नेचर का केस, और अगर 50 केस होता है तो वहां के एस0 पी0 पर कार्रवाई किया जाय, उनको रेस्पौंसिब्लिटी दी जाय ।

अध्यक्ष : आप समाप्त कीजिये ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक बात कह कर बैठ जाऊंगा । हमारे यहां व्यवसायियों ने दुकान बंद कर के रखा है और वह इसलिए कि रंगदारी वहां से रूक नहीं रही है । मैंने मंत्री जी से भीा आग्रह किया था सदन में आवाज उठाया था । मैं नया सदस्य हूं और सदन की गरिमा को समझते हुये आप सबों से आग्रह करता हूं कि कहीं न कहीं यह आस्था और विश्वास होना चाहिए । आप ने बोलने का अवसर दिया, इस के लिये आप को धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष : श्री राजू तिवारी ।

श्री राजू तिवारी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती-प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी हमारे क्षेत्र में थानों की जो समस्या है उस का मुख्य कारण है थानों में पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है चूंकि हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा दूसरे बोर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है । थानों पर पर्याप्त मात्रा में डिजल की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जाती है, जिस से आम जनता जाती है उनको भी कष्ट होता है, थाने का स्तर पहले की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ा है, 1990 से लेकर 2005 तक के दशक में जो अपराध का ग्राफ था, उस को कंट्रोल माननीय मुख्यमंत्री किये हैं, वह पूरा देश जानता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फिर वही दिन नहीं आये, इसलिए थानों पर स्थिति है कि कोई भी अगर थाने पर कंप्लेन करने जाता है तो थाने का दारोगा और मुंशी तेल के नाम पर रूपया मांगने का काम कर रहा है । मैं इसलिए आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि थानों को पर्याप्त सुविधा दी जाय । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि थाने पर जो गरीब जाता है, उस को मान-सम्मान नहीं मिल रहा है । बड़े अफसर बैठे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, सबों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो जनता है, पूरे बिहार प्रदेश की जो जनता है, उन को थाने पर मान-सम्मान मिले, कम से कम उस को दुत्कार न मिले । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश तिवारी । आप 5 मिनट में समाप्त कर दीजियेगा । पहले के आप के वक्ताओं ने आप का समय ले लिया है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव जो लाया है, मैं उस के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम को तो लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी सुनेंगे लेकिन मुख्यमंत्री जी चले गये ।

अध्यक्ष : तिवारी जी आप सदन में नहीं रहते हैं तो क्या आप सदन की बात नहीं सुनते हैं ? सुनते हैं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : लेकिन महोदय, आज मुख्यमंत्री जी को रहना चाहिए था चूंकि गृह विभाग का मामला है । विपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव जो लाया गया है, मैं उस के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और आज बोलने का जो मुझे अवसर मिला है, उस के लिये मैं आप का अपने विधायक दल के नेता श्री प्रेम कुमार जी का और गोपालगंज के बैकुण्ठपुर की महान जनता का मैं कृतज्ञ हूं, जिस के कारण मैं यहां गृह विभाग के अनुदान मांग के पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूं ।

महोदय, इस बिहार की पहचान पहले ''बुद्धम् शरणम् गच्छामि'' से हुआ करती थी, जो महात्मा बुद्ध का संदेश दुनिया के कोने-कोने तक जाता था । लेकिन उसी धरती से एक नया संदेश आया कि ''साईड मांगोगे बिहार में तो गोली मार देंगे कपार में।'' तब महोदय, लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है
और चुनाव के पहले कहा गया कि झांसे में न आयेंगे, महागठबंधन को जितायेंगे ।

चलिये, बिहार में आप की सरकार बन गयी ।

''तो झांसे में न आयेंगे, महागठबंधन को जितायेंगे
और जब जीत कर सत्ता में आयेंगे तो बिजली बिल 55 परसेंट बढ़ायेंगे,
भले नरेन्द्र मोदी भारत को विश्व में चमकायेंगे
लेकिन हम बिहार को लालटेन युग में पुनः पहुंचोंगे ।''

5 मिनट में महोदय, हम समाप्त कर देंगे । हम कविता ही कह सकते हैं, भाषण तो दे नहीं सकते हैं । महोदय, कहा जाता है कि

'' बिहार में बहार है, मुख्यमंत्री जी लाचार हैं,
यहां तो परमेश्वर, लालकेश्वर और मेवा लाल के साथ मेवा
खा रही चाचा भतीजा और वो की सरकार है ।''
देश के 16 राज्यों में गांव, गरीब और गायों की सेवा में तत्पर
भाजपा की सरकार है ।
कहीं शिवराज, कहीं रमण, कहीं रघुवर और अब यू0पी0 मे
योगी जी की सरकार है । ''
वेंटिलेटर पर पूरा यू0पी0ए0,महागठबंधन और कोमा में बिहार
की सरकार है ।

सर्जिकल स्ट्राईक और देश के दुश्मनों का छक्का छुड़ा के सब का
साथ, सब का विकास के साथ लगातार देश में ही नहीं,
पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही मोदी की सरकार है । ''

क्रमश :

टर्न–27/राजेश/27/3/17

श्री मिथिलेश तिवारी, क्रमशः महोदय, अब मुझे एक बड़ी खुशी होती है, इस महागठबंधन के हमारे साथी इस हाउस में बोलने के लिए खड़े होते हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य को बोलने दीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारीः महोदय, हमारे महागठबंधन के साथी जब बोलने के लिए खड़े होते थे, तो पहले गुजरात चले जाते थे, गुजरात बिहार से दूर भी है, भाड़ा भी अधिक लगता था लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी है कि ये लोग अब गुजरात के बजाय उत्तरप्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं महोदय और हमको जनता दल (यूनाईटेड) के हमारे सम्मानीय, माननीय विधायक हैं, उनको तो हमलोगों को बधाई देना चाहिए, हमारा उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस समय मोदी जी से डरकर, अगर मोदी जी से लालू जी डरे नहीं होते, तो आपके साथ गये नहीं होते और उस समय लालू जी गाना क्या गाते थे, कहते थे कि: ''चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ,

हाथ जोड़ता हूँ तेरे पॉव पड़ता हूं,'' और यह कहकर इन्होंने गठबंधन बनाया, सत्ता में चले आये और नोटबंदी के समय माननीय अध्यक्ष महोदय, नोटबंदी के समय जनता का नब्ज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहचाना, तो मुख्यमंत्री जी, जब नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे, तो लालू प्रसाद जी गाना गा रहे थे, कह रहे थे कि:

''हम थे जिनके सहारे, वे हुए ना हमारे,
डूबी जब मेरी नईया, सामने थे किनारे ।''

महोदय, इस बिहार में क्या होता था, यह राजेन्द्र बाबू का बिहार, शहाबुद्दीन का बिहार हो गया, यह गौतम बुद्द का बिहार नक्सलियों का बिहार हो गया, ये जैन और बुद्द का बिहार राजबल्लभ का बिहार हो गया, लोकतंत्र की वैशाली बच्चा राय का बिहार हो गया, मिथिला की राजधानी आतंकवादियों का पनाहगार हो गया महोदय और इसी बिहार में जो आज की सरकार है, वह कहती है कि ''You show the man I show the law'' यह बिहार में आज चल रहा है महोदय और महोदय बिहार के डी0जी0 निगरानी का बयान आता है, वे कहते हैं कि बिहार में जो 133 ट्रैप कांड हुए हैं, उसमें केवल 32 पुलिस वाले ही पकड़े गये, 2017 में जो ट्रैपिंग हुई, उसमें 5 पुलिस

वाले पकड़े गये, तो सरकार का पोल सरकार का ही आला अधिकारी खोल रहा है महोदय और इसलिए महोदय मैं कहना चाहूंगा कि आज की जो बिहार की सरकार है, तो थाना में जब गरीब लोग जाता है, तो उसको हनुमान जी की चौपाई नजर आ जाती है और वह कहता है कि:

''राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे'',

तो यह सरकार बिहार में चल रही है, एक पासपोर्ट बनाने के लिए जब नवयुवक थाने में आता है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य मिथिलेश जी, अब अंतिम चौपाई ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, मुझे तो समय आपने नहीं दिया, फिर भी महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि गोपालगंज में खजूरवन्नी कांड हुआ, इसी सरकार के शराबबंदी का पोल खुल गया महोदय, दो दिन पहले कंचन प्रसाद की हत्या हुई, वह राजमिस्त्री था और उसकी हत्या कुल्हाड़ियों से काट-काट कर की गयी महोदय, 17 नवंबर 2011 को दो करोड़ की मूर्ति चोरी हो गयी महोदय .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, पहले भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता का, अब उनके जैसा ताड़ीपार नेता लोग आ गये हैं तो मिथिलेश तिवारी बोल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय श्री रत्नेश सादा । आप दो से तीन मिनट के अंदर अपनी बात को कहिये ।

श्री रत्नेश सादा: अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग द्वारा लाये गये बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोल रहा हूँ । महोदय, गृह विभाग वह विभाग है, जिस विभाग से विधि-व्यवस्था, अपराध, समाज में दबंगो पर अंकुश लगाना, न्याय के साथ विकास करना तथा कानून का राज स्थापित करना, समाज में भय का वातावरण को समाप्त करना, गृह विभाग वह विभाग है महोदय, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण और मान-सम्मान सभी वर्गो के लिए किया जा रहा है ।

महोदय, देश में पहली बार केन्द्रीय कारा बेऊर जेल पटना में अधिष्ठापन किया गया और वहाँ सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है और सफलतापूर्वक बिहार राज्य के 55 काराओं में 4 करोड, 87 लाख, 32 हजार, 905 रुपये की लागत पर कार्यों का पूर्ण कम्प्युटरीकृत विकसित करने हेतु सिस्टम विकसित किया गया । महोदय, राज्य के 58 काराओं में नये सिरे से सी0सी0टी0भी0 एवं अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों के अधिष्ठापन

एवं राज्य के सभी काराओं में नये सिरे से काराओं को न्यायालय के बीच बंदियों को उपस्थापन .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: रत्नेश जी, अब क्षेत्र की भी बात हो, तो कह लीजिये, अब समाप्त करना होगा ।

श्री रत्नेश सादा: महोदय, मैं क्षेत्र की बात कहने से पहले एक बात खासकर मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये विपक्ष के लोग बराबर बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, यह बिहार ने वह चीज दिया जो नालंदा के विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम किया, महात्माबुद्द को ज्ञान इसी बिहार के गया में प्राप्त हुआ, भगवान महावीर का बिहार के वैशाली में जन्म हुआ, आज वीर कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, इन सबों को और महोदय इतना ही नहीं डा0 राजेन्द्र प्रसाद को देने का काम किया इसी बिहार ने और जब गरीब-गुरुआ की आवाज और जब गरीब-गुरुआ पर आतंक फैल गया महोदय तो लालू प्रसाद जी को दिया बिहार ने और जब हक, अधिकार की बात आयी महोदय, तो सभी विभागों में चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी में विकास के लिए यहाँ नीतीश कुमार जी को दिया है बिहार महोदय, ये बिहार को बदनाम करने के लिए, ये लोग साजिश रचते हैं महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री रत्नेश सादा: एक मिनट सर । आज भगवा के लोगों को, आर0एस0एस0 के लोगों को, देश को बचाने में, आजादी दिलाने में, कोई हाथ नही था, वे आज देश के प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश पर राज कर रहे हैं, उसीतरह से बिहार में बी0जे0पी0 के लोगों को बिहार को बनाने में कोई हाथ नहीं है और बिहार को बदनाम करने का साजिश इनलोगों के द्वारा चल रहा है महोदय, यह कहाँ का नियम है ? महोदय, मैं बी0जे0पी0 के विधायकों से पूछना चाहता हूँ कि दलित, महादलित की बात ये करते हैं, लेकिन मैं इन विधायकों से पूछना चाहता हूँ कि किसी महादलित को इनलोगों ने चापाकल दिया है आज तक, एक महादलित को सामुदायिक भवन दिया है आज तक, महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग महादलित की बात करते हैं लेकिन ये बताये कि महादलित के कार्यकर्ता से ये लोग बात भी करते हैं महोदय, नहीं करते हैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री रत्नेश सादा: एक मिनट सर । महोदय, हमारे क्षेत्र में एक समस्या है ।

अध्यक्ष: इसीलिए तो पहले कह रहे थे ।

श्री रत्नेश सादा: महोदय, सोनवर्षा प्रखंड में खजुराहा पंचायत में गज बाजार में एक पुलिस कैंप पहले था, वहाँ पर माओवादियों का राज है लेकिन वहाँ से पुलिस कैंप हट गया है, वहाँ

पुलिस कैंप स्थापित करने की कोशिश की जाय और इन झॉसा राम को आने वाले दिनों में बिहार की जनता सबक सिखायेगी .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब आपका समय समाप्त हुआ । अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

टर्न-28/सत्येन्द्र/27-3-17

सरकार का उत्तर

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 16 माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी जानकारी अपनी अपनी मनोकामना और अपनी अपनी भावना के अनुरूप अपने विचार सदन के समक्ष रखने का काम किया । महोदय, ये जिवेश कुमार जी नये मेम्बर हैं दरभंगा से जीतकर आते हैं, ये जब बोल रहे थे तो छठा-सातवां में मैं जब स्टूडेंट था तो उस समय की कुछ बातें याद आती हैं । घर के बगल में एक रामलीला पार्टी सिद्दिकी जी दरभंगा के हैं दरभंगा से रामलीला पार्टी हमलोगों के इलाके में जाया करती थी तो उसमें एक विदुषक आता था मंच पर तो दो घटना मुझे याद है, सदानंद बाबू चूंकि बीच में वे भी खड़े हो गये थे कुछ शब्दों पर एतराज करते हुए तो एक विदुषक आया पीछे में लालटेन जलाकर के और कुछ कह रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि भई इतनी रोशनी है लालटेन लेकर क्यों आये हो तो कहा नया में पंडित हम हुए हैं, पतरा बांटने के लिए हम आये हैं, रोशनी में भी हमको लालटेन चाहिए । दूसरी घटना है कि विदुषक ने एक प्रसंग में कहा कि भगवान बड़ा भई बईमान आदमी है तो दर्शक से लेकर के और रामलीला पार्टी में जो उसके सभी सागिर थे सभी भौंचक रह गये कि ये भगवान के खिलाफ में बोल रहा है लेकिन उसने कहा कि हम बोलेंगे, कहा क्यों ? तो कहा, हाथी इतना बड़ा जानवर है, भगवान ने आंख इसको कितना छोटा दिया, यह बतलाईए बेईमानी नहीं है तो क्या है? तो महोदय भारतीय जनता पार्टी की हालत वही विदुषक की हो गयी है और फरसटेशन में हैं, इनको बड़ी ही आंकाक्षा थी अब एक बार मेरे गांव में एक आदमी बड़ा खुश था तो किसी ने कहा भई क्यों खुश है आपका तो खेत दह गया है, तो उसने कहा नहीं मालूम पड़ोसिया का खेत तीन मन का कट्ठा उपजा, तो महोदय अपनी पीड़ा से वे लोग परेशान है, कहीं हुकहुकी आ गया है कि उत्तर प्रदेश में हमारा हो गया है । इस पीड़ा का बखान वह विभिन्न गणितों के फेरेबी आंकड़ों से किया करते है और उन्हें अच्छाई कुछ सुझता ही नहीं है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने

महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के क्रम में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन सारी आंकड़ों का जिक्र किया था । महोदय, भारत सरकार का एक आर्गेनाईजेशन है जो सम्पूर्ण राज्यों के क्राईम के आंकड़ों को इकट्ठा कर के साल में प्रकाशित करने का काम करता है । वही आधार है और उसी आधार पर क्राईम फिगर किस राज्य का कईवां स्थान है और इसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत रूप से सदन में अपनी बातों को रखने का काम किया था । अपराध क्या है और लॉ एंड आर्डर क्या है, दोनों में फर्क लोग समझ नहीं पा रहे हैं । महोदय, आज मैं सुन रहा था कह रहे थे अरूण बाबू कि सरकार में इतनी कमजोर व्यवस्था है कि एभिडेंश ठीक नहीं होता है तो छूट जाया करते हैं अपराधी । अब महोदय, 200-250 साल पहले मेरी जानकारी के अनुसार अंग्रजों ने सी0आर0पी0सी0 और आई0पी0सी0 का निर्माण किया था और उस समय यह कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता था । आज सारी दुनिया उसी को इम्प्लीमेंट कर रही है और महोदय, आजाद भारत में 70 साल के करीब हो गया है उसमें कोई अमेंडमेंड बहुत नहीं हुआ है, कुछ ऐडीशन हुआ है लेकिन वही हो रहा है । आज मैं देख रहा था बुधवार को Briten के पार्लियामेंट पर हंगामा हुआ आतंकवादी हमला हुआ था, पांच-छः आदमी मारे गये, 12 आदमी की गिरफ्तारी हुई लेकिन आज रिपोर्ट था उसमें से 11 आदमी को छोड़ दिया गया और आज फिर एक की गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस इंभिस्टीगेशन करने के बाद अगर जानती है कि निर्दोष है चूंकि उनको भी कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि अपराधी है कि नहीं है और कोर्ट उनका संज्ञान लेता है और उन सारी चीजों का मोनेटरिंग करता है । सारी चीजों पर उसकी बहस होती है, इसके बाद सजा होता है नहीं तो वह वेल ले लेता है, छूट जाता है, अपराधी निर्दोष साबित होता है लेकिन महोदय बड़ी चर्चाएं होती है Court can't interfere in the investigation. Investigation का प्रभारी थाना प्रभारी होते हैं। अब जब सी0आर0पी0सी0 बना तो हुआ कि साहब थाना प्रभारी किसी को 24 घंटे के लिए बंद कर देगा हाजत में और हर थाने में हाजत होता है । मुझे याद है कि एक दारोगा जी हमारे यहां थे वह कहते थे कि देखते हो यह राष्ट्रपति के यहां भी नहीं है, हमारे यहां ही यह है, थाना प्रभारी इतना ताकतवर होता है। हम ही को नियंत्रित करने के लिए इंस्पेक्टर डी0एस0पी0, एस0पी0, डी0आई0जी0, आई0जी0, डी0जी0पी0 सब होते हैं और सच है कि थाना प्रभारी को बहुत पावर है तो एक बार मीटिंग हुई तो एक एस0पी0 ने खड़ा होकर कहा गवर्नर जनरल को कि हुजूर हमलोग भी जायेंगे थाना में इंस्पेक्शन करने तो हमको भी अगर थाना प्रभारी बंद कर दे हाजत में तब क्या होगा तो ऐड किया कि सिनियर अफसर जब थाना में प्रवेश करेंगे तो अफसर इंचार्ज वह हो जायेंगे, उस पीरियड का वही केस डायरी को दर्ज करेगा तो पुलिस का निर्माण श्री नीतीश कुमार जी की सरकार में सी0आर0पी0सी0 का निर्माण नहीं हुआ है,

आई0पी0सी0 का निर्माण नहीं हुआ है । यह अंग्रेजों के बनाये हुए कानून हैं और मैंने Briten का जिक्र इसलिए किया कि स्कॉटलैंड की पुलिस सबसे बेहतर पुलिस मानी जाती है उसी की ट्रेनिंग को आधार बनाया जाता है, माना जाता है लेकिन Briten में भी हमले हुए तब क्या कहा जाय कि लॉ ऐंड आर्डर बहुत खराब है, अमेरिका में भी तो हुआ है लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ बराबर, यूरोप बहुत ही समृद्ध है, बहुत एजुकेटेड है, अर्थव्यवस्था वहां की बड़ी मजबूत है, शत प्रतिशत साक्षरता है । अमेरिका सबसे रिचेस्ट है और आज दुनिया में अर्थव्यवस्था का नियंत्रण डॉलर के आधार पर होता है इन टर्म्स ऑफ डालर कितना आपका क्वायन है, यही इकोनोमी का मापदंड है, यही जी0डी0पी0/जी0आर0 निर्धारित करता है । अमेरिका में, यूरोप के सारे देश में या कोई एक देश का नाम बतलावें कि जहां जेल नहीं है । एक देश का नाम कोई बतावे विद्वान आदमी कि वहां पुलिस नहीं है, आर्मी हो । यूरोपियन यूनियन तो एक जगह है अभी केवल वोटिंग के आधार पर यूरोपियन यूनियन इकोनोमिक जो ब्रांडिंग है उससे Briten अलग हुआ है तो ठीक है जो बाहरी हमले के लिए देश में आर्मी हो, पुलिस क्यों है, न्यायालय क्यों है, महोदय, कहने का मतलब मेरा यह है कि अपराध मुक्त दुनिया नहीं है बल्कि आंकड़ें ये बतलाते हैं कि सबसे अधिक अपराध अमेरिका में होता है और सबसे अधिक आदमी जेल में है वहां । अपराध तो क्राईम फ्री एक कल्पना है, क्राईम मुक्त हो, अपराध मुक्त दुनिया हो लेकिन हुआ नहीं है । अभी तक मैने अमेरिका और यूरोप का जिक्र किया महोदय, एक अवधारणा और भी है Law never make society. Society makes their own law. कानून समाज का निर्माण नहीं करता है, अब भाई भाई में झगड़े होते हैं, महोदय हर घर में तो पुलिस बैठी नहीं रहेगी, पुलिस को जाने में देर तो लगेगी, हर घर में अगर ये प्रवृत्ति आज क्या अखबार में छप रहा है बाप ने बेटे की हत्या कर दी, बेटे ने बाप की हत्या कर दी, माँ की हत्या हुई, पत्नी की हत्या हो रही है, अब जरा बतलाया जाय, हां हत्या को रोकना हमारा कर्त्तव्य है हमारा ध्येय है, पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है कि नहीं, यही सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि है महोदय तो जैसा श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार शब्दों में हर जगह कहते हैं हम न किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं । अगर रूलिंग पार्टी का आदमी भी अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी उतनी ही कठोर कार्रवाई की जाती है, किसी को बख्शा नहीं जाता है । क्या यह बात सच नहीं है कि जनता दल(यू0) के एक एम0एल0सी0 की गिरफ्तारी हुई, राजद के एक एम0एल0ए0 की गिरफ्तारी हुई, शहाबुद्दीन जेल में गये जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा की जा रही है। महोदय, किसी सरकार का ऐसा उदाहरण है कि अपने रूलिंग पार्टी के लोगों को इतनी कड़ाई से जो एम0एल0ए0 हो जो एम0एल0सी0 हो जो भूतपूर्व लोकसभा का सदस्य हो इतनी तत्परता से कार्रवाई हुई

इसलिए इसकी चर्चा भी होनी चाहिए । महोदय, मैं नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है, दुनिया में ही सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन सरकार तत्परता से कार्रवाई कितना कर रही है ये महत्वपूर्ण चीजें हैं । एक बात का और जिक्र मैं दुनिया के पैमाने पर उदाहरण देकर करना चाहूंगा । आज पूरे दुनिया में धन जो है वह इक्ट्ठा हो गया, एकतरफा हो गया, सत्ता का संतुलन भी रूस में खत्म होने के बाद कई भागों में बंटने के बाद एकध्रुवीय हो गयी है। दुनिया में धन का जमाबड़ा यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा हो गया है जो एशियन मूल्क है, गैर यूरोपियन और गैर अमेरिकी मूल्क है उसमें बेरोजगारी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, गरीबी बेकारी बेरोजगारी भी अपराध के प्रादूर्भाव को बढ़ाता है । आखिर आज क्यों आतंकवाद फैल रहा है, क्या कारण है मैं पूछना चाहता हूँ, माओवादी क्या अपराधी हैं,यह समाजिक असंतुलन असमानता के खिलाफ एक विद्रोह की भावना है और यह किस राज्य में नहीं है । भाजपा शासित राज्य में क्यों नहीं कंट्रोल हुआ, बगल में छतीसगढ़ में क्यों नहीं नियंत्रण में हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। महोदय, आज हमारी पुलिस की तत्परता आज ही न्यूज हमने पढ़ा कि मुम्बई के एक औफिसर का शराब को लेकर के आ रहा था उसकी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ने का काम किया जितना संभव हो पाता है हमारी पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती है, किसी को फर्क नहीं करती, कार्रवाई करती है लेकिन सभी का सहयोग भी चाहिए । हमलोगों का भी कर्त्तव्य बनता है । (क्रमशः)

टर्न-29/मधुप/27.03.2017

...क्रमशः ...

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : हमलोग भी उसमें सहायक हों । लेकिन केवल कह देने से लोकतंत्र में डिसेंसी, डिकोरम, डिस्कशन और डिसीजन, यह महत्वपूर्ण तथ्य है । अपेक्षा यह रहती है सदन में कि जो माननीय सदस्य किसी खामियों को उजागर करेंगे सरकार के सामने में तो उसके निराकरण के लिये कुछ अपने सुझाव भी देंगे, केवल एकतरफा हरिबोल का गीत गाना, यह उचित नहीं है । अंताक्षरी बहुत देर तक लोकतंत्र के शोभा को नहीं बढ़ाता । डिस्कशन होनी चाहिये और डिस्कशन में डेकोरम भी रहनी चाहिये, डिसेंसी भी रहनी चाहिये । इसीलिये मैं बार-बार कहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है । राजतंत्र नहीं है, राजा किसी का सुनते नहीं थे, दरबारी लोगों का सुनते थे, लेकिन लोकतंत्र में कोई दरबार नहीं हुआ करता है, कोई दरबारी नहीं हुआ करता है । पॉच साल के लिये जनता सत्ता देती है और पॉच साल के बाद फिर वह रिनिउअल करती है अगर ठीक-ठाक काम किया किया तो ।

महोदय, इसीलिये मैं जिक्र कर रहा था, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। लेकिन होता क्या है ? अगर एक घटना हो गई, इस राज्य की प्रवृत्ति है, तो अखबार में

मुख्य खबरों में छपता है । अगर कोई उपलब्धि हुई, अगर कोई पकड़ा गया दुर्दांत अपराधी तो वह दो लाईन की खबर में छपती है । अच्छाई कोई हुई तो नीचे में 12वें पृष्ठ पर छपता है और अगर कोई बुराई है तो मुख्य पृष्ट पर । जैसा मैंने कहा कि विदूषक ने कहा कि भगवान बड़ा भारी बेईमान आदमी है कि हाथी को देह दिया इतना बड़ा और ऑख क्यों छोटा दे दिया । इस तरह का छिद्रान्वेषी होना, निगेटिव एप्रोच रखना, यह लोकतंत्र के लिये, समाज के लिये अहितकारी है । करोड़ो-करोड़ नौजवान, लाखों लोग हमारे चरित्र को, हमारे बहस को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को देखा करता है । उसपर भी असर पड़ता है इसीलिये हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिये कि हमारा जीवन जो राजनीति में हमलोग आये हैं, 11 करोड़ लोगों में 243 आप यहॉ आये हैं, 243 मामूली संख्या नहीं है लेकिन 11 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं । इसीलिये बहस बड़ी सार्थक, बड़ी कारगर और बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ पारदर्शी तरीके से सृजनात्मक होनी चाहिये क्योंकि इस दायित्व का निर्वहन अगर हम न करेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जिस खतरे को पैदा कर रही है, उस खतरे से निपटना आसान काम नहीं होगा । ठीक ही कह रहे थे एक माननीय सदस्य कि अगर तीनों पार्टी के यू0पी0 में वोट जोड़ दिये जायें तो कितना प्रतिशत होता है और भारतीय जनता पार्टी का कितना प्रतिशत होता है । हमारे बिखराव का लाभ उनलोगों ने उठाने का काम किया है । ठीक ही कहा, आज तक परम्परा रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर ओथ के लिये बुलाता है लेकिन क्या हुआ मणिपुर में, क्या हुआ गोवा में ?

इसलिये अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कोई काम न करें । लॉ एण्ड ऑर्डर खराब है, लॉ एण्ड ऑर्डर खराब है, बिहार बहुत बर्बाद है तो कौन-सा राज्य है जहॉ स्वर्ग-सितारा उतर गया है नीचे ? किसी भी राज्य में चलकर कोई दिखावे कि वहॉ अपराध नहीं होता है ।

महोदय, मैं एक जिक्र करना चाहूँगा उदाहरण के तौर पर । गुजरात में हमलोग गये थे इनर्जी मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में, टेबल पर खा रहे थे, एक पत्रकार आया मेरे पास, कहा कि बिहार में अपराध बहुत बढ़ गया है । बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, कहा कि गुजरात में आज तीन अपहरण हुआ, तीन रेप हुआ लेकिन देखिये 18वें पन्ने में न्यूज छपा है दो लाईन का और बिहार में अगर एक घटना होती है तो हेडलाईन में छपता है । कितना किसान आपके यहॉ आत्महत्या किया ? गुजरात में अभी एक लाख किसानों ने पिछले तीन साल में आत्महत्या किया है लेकिन कोई खबर नहीं फैली । मैंने पूछा कहॉ घर है भईया, जब वे पत्रकार भाग गये, तो कहा कि मेरा घर मोतिहारी है, हमने कहा कि क्या नाम है तो कोई सिंह बताया । महोदय, ऐसा नहीं है ।

लेकिन हमलोग अपने-आप, हमारे माननीय लोग भी, भईया विपक्ष में हैं तो हमारा क्या दोष है ? यहीं बैठते थे नन्द किशोर जी, विरोधी दल के नेता थे, आपको भी महोदय, कहा था कि आपको छोड़ेंगे नहीं, अगले चुनाव में नहीं आने देंगे, याद होगा, महोदय । लेकिन अब जनता ने नहीं दिया साथ तो हमलोग क्या करें भईया ? गुस्से में हमलोगों को क्यों बोल रहे हो ? हमारा क्या दोष है ? जनता के बीच में जाओ । आज यू0पी0 में, तो पड़ोसिया को लेकर नाचो । ठीक है, खुशी में रहो । खुशी में रहो तो कुछ तो करो भईया । ठीक ही कहा, हमारे माननीय सदस्य ने कि बहुत उत्साह में हैं, तो कुछ तो भारत सरकार से दिलवाइये । महोदय, अनावश्यक आरोप लगाना और काम करना दोनों में अन्तर है ।

महोदय, मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा । पिछले वित्तीय वर्ष में नालंदा जिला में चेरो ओ0पी0 हेतु भूमि अर्जन की कार्रवाई की गई है, मधुबनी पुलिस लाईन हेतु भू-अर्जन के लिये राशि दी गई है, दरभंगा जिला का अलीनगर पुलिस थाना हेतु भू-अर्जन की कार्रवाई की जा रही है । आतंकवाद निरोधक दस्ता हेतु साईबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का निर्माण करने की कार्रवाई हो रही है । प्रत्येक जिला में साईबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट, बिहार पुलिस आनुधिक हेल्प-लाईन, पुलिस हेतु वी0एच0एफ0 सेट का क्रय, अति विशिष्ट/ विशिष्ट महानुभावों हेतु सुरक्षा उपकरण का क्रय, सभी थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा की स्थापना, विधि-विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों का क्रय, सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना हेतु 894 अदद कम्प्यूटर डेस्कटॉप, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के क्रय की कार्रवाई की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त महोदय, बिहार पुलिस आधुनिक हेल्प लाईन हेतु पोर्टा हट का निर्माण, कुल 567 थानों में महिला शौचालय/स्नानागार का निर्माण हो रहा है । प्रकाश पर्व हेतु विभिन्न निर्माण कार्य, बिहार सैन्य पुलिस-5, पटना में इनडोर स्टेडियम का निर्माण, पुलिस थानों के भवन का निर्माण कार्य, नारकोटिक्स स्टोरेज के लिये निर्माण कार्य, सी0आर0पी0एफ0 हेतु कोईलवर(आरा) में भवन निर्माण का कार्य, रेल महिला पुलिस हेतु बैरेक का निर्माण कार्य, एस0एस0बी0 हेतु जमुई में आवास का निर्माण कार्य, माननीय सदस्य उठा रहे थे, 65वाँ अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता हेतु बिहार सैन्य पुलिस-5, पटना में निर्माण का कार्य, विशेष कार्य दल हेतु पटना, गया, जमालपुर में भवन निर्माण का कार्य, पटना पुलिस लाईन में 200 बेड महिला बैरेक का निर्माण कार्य, यह भी विशिष्ट उपलब्धि है पिछले वित्तीय वर्ष का । आगे महोदय, 33 अदद स्कार्पियो की खरीदारी, 5 बुलेट प्रूफ फोर्चुनर क्रय किया जा रहा है, क्रयादेश दिया जा चुका है । पुलिस लाईन, बाँका का निर्माण कार्य किया गया है । नक्सल थाना, मॉडल थाना, ग्रेड-4 थाना, ग्रेड-3 थाना, ग्रेड-2 थाना, सहित कुल 70 थाना भवनों का निर्माण किया गया है । पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के आवास हेतु कुल 390 यूनिट का निर्माण

कार्य पूरा किया गया है । कुल 4077 सिपाहियों के आवासन हेतु सभी सुविधाओं सहित बैरक का निर्माण किया गया है । यह विशिष्ट उपलब्धि है, महोदय । मुख्य भवन कार्य यथा कारा विभाग, स्वान दस्ता, रेल पुलिस संयुक्त भवन, बिहार अग्निशमन, सैनिक कल्याण भवन, पदाधिकारी आवास, पोर्टा हट बैरक, 12 मिनियल्स आवास रक्षित कार्यालय, ए0टी0एस0 भवन, मैगजीन भवन, आदि के कुल 65 भवनों का निर्माण किया जा रहा है । 97 थानों में महिला सिपाहियों के लिए 5 सीटेड शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य पूरा किया गया है । 46 पुलिस लाईन/बी0एम0पी0 में महिला सिपाहियों के लिए 20 सीटेड शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य पूरा किया गया है । 559 स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए 2 सीटेड शौचालय एवं 2 सीटेड स्नानागार निर्माण कार्य पूरा हो गया है । गुरू गोविन्द सिंह जयंती समारोह हेतु ट्रैफिक पोस्ट–20, अस्थायी ट्रैफिक कंट्रोल रूम–5, अस्थायी थाना–8, वाच टावर–7 (रेलवे स्टेशन पर) का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है । बी0एम0पी0टी0सी0 डुमरॉव, पुलिस लाईन, लखीसराय एवं सुपौल, बी0एम0पी0–12 सुपौल, एम0एम0पी0 बटालियन (पटना एवं भागलपुर) का कार्य किया जा रहा है । मॉडल थाना, ग्रेड–4 थाना, ग्रेड–3 थाना, ग्रेड–2 थाना, नक्सल थाना, SC/ST थाना विशेष थाना (पीरबहोर थाना), के कुल 134 थाना भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है । ललन जी बोल रहे थे कि SC/ST की उपेक्षा की जा रही है, महोदय, पहली बार हो रहा है । महोदय, दस जिलों में महिला पुलिस थाना निर्माण कार्य प्रगति में है । महिला पुलिस कर्मियों के लिए कुल 1130 यूनिट बैरक का निर्माण कार्य प्रगति में है । 10 थानों में महिला सिपाहियों के लिए 5 सीटेड शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य प्रगति में है । 5 पुलिस लाईन/बी0एम0पी0 में महिला सिपाहियों के लिए 20 सीटेड शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

...क्रमशः.....

टर्न–30/आजाद/27.03.2017

..... क्रमशः .....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 2017–18 के लिए महोदय मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ,

1. बिहार सैन्य पुलिस–1, पटना के निर्माण हेतु दीघा में भू–अर्जन ।
2. जमुई में बिहार सैन्य पुलिस–11 हेतु भू–अर्जन (13.45 करोड़)

महोदय, इसे प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाया जाय । मैं सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और माननीय सदस्य श्री अरूण बाबू से निवेदन करूँगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस करें और सदन से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे अनुदान की मांग को सदन पारित करे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जो लिखित दस्तावेज सदन पटल पर रखा है, वह उनके भाषण का अंश बनेगा ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''इस शीर्षक की मांग 10रू0 से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च,2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 74,47,94,90,000/- (चौहत्तर अरब सैंतालिस करोड़ चौरानवे लाख नब्बे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न अनुदानों की मांगों का मुख बन्द होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसी पूर्त्ति के लिए :-

''मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 40,07,33,78,000/- (चालीस अरब सात करोड़ तैंतीस लाख अट्हत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 4,14,21,17,000/-(चार अरब चौदह करोड़ एक्कीस लाख सत्रह हजार) रूपये

मांग संख्या-06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 90,87,52,000 (नब्बे करोड़ सतासी लाख बावन हजार) रूपये

मांग संख्या-07 निगरानी विभाग के संबंध में 36,21,40,000/- (नब्बे करोड़ सतासी लाख बावन हजार) रूपये

मांग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 15,36,09,34,000/- (पन्द्रह अरब छत्तीस करोड़ नौ लाख चौंतीस हजार) रूपये

मांग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 2,92,56,63,000/- (दो अरब बानवे करोड़ छप्पन लाख तिरसठ हजार) रूपये

मांग संख्या–15 पेंशन के संबंध में 198,66,78,81,000/– (एक सौ अंठानवे अरब छियासठ करोड़ अट्हत्तर लाख एकासी हजार) रूपये

मांग संख्या–16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 86,94,43,29,000/– (छियासी अरब चौरानवे करोड़ तैंतालिस लाख उनतीस हजार) रूपये

मांग संख्या–17 वाणिज्य–कर विभाग के संबंध में 1,29,12,61,000/– (एक अरब उनतीस करोड़ बारह लाख एकसठ हजार) रूपये

मांग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 16,44,72,88,000/– (सोलह अरब चौवालिस करोड़ बहत्त लाख अठासी हजार) रूपये

मांग संख्या–19 पर्यावरण एवं वन विभाग के संबंध में 3,18,96,74,000/– (तीन अरब अठारह करोड़ छियानवे लाख चौहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 70,01,52,13,000/– (सत्तर अरब एक करोड़ बावन लाख तेरह हजार) रूपये

मांग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में 8,43,26,44,000/– (आठ अरब तैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख चौवालीस हजार) रूपये

मांग संख्या–24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के संबंध में 2,04,55,66,000/– (दो अरब चार करोड़ पचपन लाख छियासठ हजार) रूपये

मांग संख्या–25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 2,48,63,71,000/– (दो अरब अडतालीस करोड़ तिरसठ लाख एकहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 4,68,95,01,000/– (चार अरब अड़सठ करोड़ पंचानवे लाख एक हजार) रूपये

मांग संख्या–27 विधि विभाग के संबंध में 6,96,88,60,000/– (छः अरब छियानवे करोड़ अठासी लाख साठ हजार) रूपये

मांग संख्या–29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 25,85,16,000/– (पचीस करोड़ पचासी लाख सोलह हजार) रूपये

मांग संख्या–30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 5,95,06,76,000/– (पाँच अरब पंचानवे करोड़ छः लाख छिहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या–31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 2,01,47,000/– (दो करोड़ एक लाख सैंतालीस हजार) रूपये

मांग संख्या–32 विधान मंडल के संबंध में 1,70,21,41,000/–(एक अरब सत्तर करोड़ एक्कीस लाख एकतालीस हजार) रूपये

मांग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 5,18,61,16,000(पाँच अरब अठारह करोड़ एकसठ लाख सोलह हजार) रूपये

मांग संख्या–35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 28,41,72,76,000/–(अट्ठाइस अरब एकतालिस करोड़ बहत्तर लाख छिहत्तर हजार)रूपये

मांग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 24,34,41,25,000/– (चौबीस अरब चौंतीस करोड़ एकतालीस लाख पचीस हजार) रूपये

मांग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 95,18,05,05,000/– (पंचानवे अरब अठारह करोड़ पॉच लाख पॉच हजार) रूपये

मांग संख्या–38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संबंध में 1,52,80,37,000/– (एक अरब बावन करोड़ अस्सी लाख सैंतीस हजार) रूपये

मांग संख्या–39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 10,69,40,01,000/– (दस अरब उनहत्तर करोड़ चालीस लाख एक हजार) रूपये

मांग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 8,62,21,68,000 (आठ अरब बासठ करोड़ एक्कीस लाख अड़सठ हजार) रूपये

मांग संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 2,13,45,35,000/– (दो अरब तेरह करोड़ पैंतालिस लाख पैंतीस हजार) रूपये

मांग संख्या–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 13,01,89,97,000/– (तेरह अरब एक करोड़ नवासी लाख संतानवे हजार) रूपये

मांग संख्या–45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 1,18,57,72,000/– (एक अरब अठारह करोड़ संतावन लाख बहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या–46 पर्यटन विभाग के संबंध में 1,09,87,35,000/– (एक अरब नौ करोड़ सतासी लाख पैंतीस हजार) रूपये

मांग संख्या–50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 6,06,82,03,000/– (छः अरब छः करोड़ बेरासी लाख तीन हजार) रूपये

मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 60,06,25,81,000/– (साठ अरब छः करोड़ पच्चीस लाख एकासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 मार्च, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल 47 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 28 मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

*****

परिशिष्ट

बजट सत्र 2017 के अभिभाषण हेतु सामग्री
वित्तीय वर्ष 2016-17

❖ पुलिस हेल्प लाईन

पुलिस मुख्यालय में जनता की शिकायतों एवं सूचनाओं को सुनने एवं उसके आधार पर कार्रवाई कराने एवं सूचनादाताओं को जानकारी देने के लिए नये Police Help Line की स्थापना की गई है । उक्त Help Line का नं0-0612-2209999 हैं, जिसमें 07 हंटिग लाईन भी है । उक्त Help Line का Toll No. 1860-3456-999 है । उक्त Help Line सुचारू रूप से कार्य कर रहा है ।

❖ बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग

राज्य में पुलिस अवर निरीक्षकों एवं अन्य वर्दीधारी विभागों में समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग का गठन किया जा चुका है ।

❖ भू-अर्जन

नालंदा जिला के चेरो ओ.पी. हेतु भूमि अर्जन	76.73 लाख
मधुबनी पुलिस लाईन हेतु भू-अर्जन	84.70 करोड़
दरभंगा जिला का अलीनगर पुलिस थाना हेतु भू-अर्जन	47.60 लाख

❖ ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं पुलिस आधुनिकीकरण

आतंकवाद निरोधक दस्ता हेतु साईबर फॉरेंसिंक प्रयोगशाला	66.19 लाख
प्रत्येक जिला में साईबर काईम एवं सोशल मीडिया यूनिट	2.05 करोड़
बिहार पुलिस आधुनिक हेल्प-लाईन	1.04 करोड़
पुलिस हेतु वी.एच.एफ. सेट का क्रय	9.36 करोड़
अति-विशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों हेतु सुरक्षा उपकरण का क्रय	7.84 करोड़
सभी थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा की स्थापना	105.00 करोड़
विधि-विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों का क्रय	4.12 करोड़
सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना हेतु 894 अद्द कम्प्यूटर डेस्कटॉप, प्रिन्टर एवं यू.पी.एस. का क्रय	9.36 करोड़

❖ **भवन निर्माण**

बिहार पुलिस आधुनिक हेल्प लाईन हेतु पेटा हट का निर्माण	84 लाख
कुल 567 थानों में महिला शौचालय/स्नानागार का निर्माण	11.86 करोड़
प्रकाश पर्व हेतु विभिन्न निर्माण कार्य	6.17 करोड़
बिहार सैन्य पुलिस-5, पटना में इनडोर स्टेडियम का निर्माण	22.53 करोड़
पुलिस थानों के भवन निर्माण का कार्य	6.75 करोड़
नारकोटिक्स स्टोरेज के लिए निर्माण कार्य	5.50 करोड़
सी.आर.पी.एफ. हेतु कोईलवर (आरा) में भवन निर्माण का कार्य	9.00 करोड़
रेल महिला पुलिस हेतु बैरेक का निर्माण कार्य	5.00 करोड़
एस.एस.बी. हेतु जमुई में आवास का निर्माण कार्य	1.00 करोड़
65वां अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता हेतु बिहार सैन्य पुलिस-5, पटना में निर्माण का कार्य	1.73 करोड़
विशेष कार्य दल हेतु पटना, गया, जमालपुर में भवन निर्माण का कार्य	2.4 करोड़
पटना पुलिस लाईन में 200 बेड महिला बैरेक का निर्माण कार्य	4.19 करोड़

❖ **हथियार**

हैंड ग्रेनेड, राईफल ग्रेनेड, राईफल, पिस्टल, कार्बाइन, टीयर गैस गन, टीयर गैस शेल, गोली एवं बारूद का कय किया गया है । विवरण निम्न प्रकार है :-

Sr. No.	Ordnance Factory/ Units	Itmes Name	Qty.	Amount	BD Sent (Yes or No)	Remarks
1	A.F. Khadki, Pune	Cartdg. 7.62 mm Blank	50,000	37,02,300/-	Sent	
2		Cartdg. 9 mm Blank (MK-II)	50,000	19,83,375/-	Sent	
3		Cart. .38mm Revolver ball	66974	31,88,029/-	Sent	
4		Cartdg. .303 mm ball Blank (V)	50,000	25,45,331/-	Sent	
5	O.F Khamaria Jabalpur	Cartdg. .303 mm ball CTN	4,51,788	4,17,18,104/-	Sent	
6	O.F Varangaon (Maharastra)	Cartdg. 7.62 mm CTN	6,72,401	3,49,40,561	Sent	
7		Cartdg. 7.62x39 mm for A.K-47	39,649	18,27,365/-	Sent	
8	H.E. Khadki, Pune	Grenade Hand 36-M MK-1	617	13,17,604/-	Sent	
9	A.F. Khadki, Pune and H.E. Khadki, Pune	For Collection, (by-Dy.S.P.Prem sagar)	-	2,50,000/-	Sent	
10	C.R.P.F. New Delhi	Old but Serviceable Rifle	5,000	50,00,000/-	Sent	

11	CENWOSTO,BSF, Tekanpur ,Gwalior	Explosive Items	-	67,815/-	Sent	
12	R.F.Ishapore Kolkata	Tear Gas Gun	46	9,49,113/-	Sent	
13	GCF.Cossipore Kolkata	Projector Grenade 7.62mm RifleSLR	5760	97,93,872/-	Sent	
14	S A F Kalpi Road,Kanpur	Gun Macine 5.56 fix Butt	74	1,30,47,609/	Sent	
15	R.F.Ishapore Kolkata	Pistol Auto 9mm	3658	14,94,08,959/	Sent	
16	S A F Kalpi Road,Kanpur	Sub Machine Gun 9mm Carbine	1362	7,83,28,333/	Sent	
17	TSU,BSFTekanpur Gwalior	Tear Smoke Munnition	20,000	1,54,60,000/	Sent	
18	O.F Khamaria Jabalpur	Grenade Rifle 36MHE	396	12,62,606/-	Sent	
19	O.F Dum-Dum,Kolkata	20 Round Magazine for INSAS Rifle 5.56mm	5,000	10,95,207/-	Sent	
20	O.F Tiruchirapalli	Rifle 7.62mm SLR	758	5,49,33,576/	Sent	
21	TSU,BSFTekanpur Gwalior	Tear Smoke Munnition	13650	1,19,88,350/		Pending in Home
22	CENWOSTO,BSF, Tekanpur ,Gwalior	Rifle 7.62mm SNIPER	10	10,000/-	Sent	
23	CRPF New Delhi	UBGL Shell	920	16,37,600/-	Sent	
24		Rifle 7.62mm SLR, GM 7.62MM		33,30,000/-	Sent	

❖ **वाहनों का क्रय**

स्कार्पियो-33 अदद (दर 8.91 लाख प्रति अदद)- कुल 2.94 करोड़ ।

5 बुलेट प्रूफ फोर्चुनर क्रय हेतु अग्रिम के रूप में रू 2.8561 करोड़ का क्रयादेश निर्गत है, जिसमें से 75 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में दिया जा चुका है । शेष राशि का भुगतान किया जाना है ।

❖ **<u>गत 01 (एक) वर्ष में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किये गये कार्य</u> :-**

1. पुलिस लाईन (बांका) का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
2. नक्सल थाना, मॉडल थाना, ग्रेड-4 थाना, ग्रेड-3 थाना, ग्रेड-2 थाना, सहित कुल 70 थाना भवनों का निर्माण किया गया है।
3. पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के आवास हेतु कुल 390 यूनिट का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
4. कुल 4077 सिपाहियों के आवासन हेतु सभी सुविधाओ सहित बैरक का निर्माण किया गया है।
5. मुख्य भवन कार्य यथा कारा विभाग, स्वान दस्ता, रेल पुलिस संयुक्त भवन, बिहार अग्निशमन, सैनिक कल्याण भवन, पदाधिकारी आवास, पोर्टा हट बैरक, 12 मिनियल्स आवास रक्षित कार्यालय, ए0. टी0 एस0 भवन, मैगजीन भवन, आदि के कुल 65 भवनों का निर्माण किया गया है।

6. 97 थानों में महिला सिपाहियो के लिए 5 सीटेड शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य पूरा किया गया है ।
7. 46 पुलिस लाईन/बी0 एम0 पी0 में महिला सिपाहियो के लिए 20 सीटेड शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य पूरा किया गया है ।
8. 559 स्थानों पर महिला पुलिस कर्मिया के लिए 2 सीटेड शौचालय एवं 2 सीटेड स्नानागार का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
9. गुरू गोविन्द सिंह जयंती समारोह हेतु ट्रैफिक पोस्ट-20, अस्थायी ट्रैफिक कन्ट्रोल रूम-05 अस्थायी थाना-8, वाच टावर-7 (रेलवे स्टेशन पर) का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

❖ **<u>प्रगतिशील कार्यः-</u>**

1. बी0एम0पी0टी0सी0 डुमरॉव, पुलिस लाईन लक्खीसराय एवं सुपौल, बी0एम0पी0-12 सुपौल, एम0एम0पी0 बटालियन (पटना एवं भागलपुर), का कार्य किया जा रहा है।
2. मॉडल थाना, ग्रेड-4 थाना, ग्रेड-3 थाना, ग्रेड-2 थाना, नक्सल थाना, SC/ST थाना विशेष थाना (पिरबहोर थाना), के कुल 134 थाना भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है।
3. पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के आवासन हेतु कुल 1075 यूनिटों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
4. कुल 5972 सिपाहियों के आवासन हेतु सभी सुविधाओं सहित बैरक का निर्माण कार्य चल रहा है।
5. कारा विभाग, बिहार अग्निशमन, गृह रक्षा वाहिनी एवं अन्य प्रकार के कुल 96 भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
10. एस0टी0एफ0 ट्रेनिंग स्कूल ऑपरेशनल सेन्टर, पुलिस अधीक्षक रेल पटना आवासीय भवन-01, सी0आर0पी0एफ0 भवन, डॉग कैनेल वायरलेस भवन पटना, स्पेशल ब्रान्च ट्रेनिंग सेन्टर पटना, आदि कूल 10 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

❖ **<u>महिला थाना/महिला पुलिस कर्मियो हेतु बैरक एवं शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य :-</u>**

1. 10 जिलों में महिला पुलिस थाना का निर्माण कार्य प्रगति में है।
2. महिला पुलिस कर्मियो के लिए कुल-1130 यूनिट बैरक का निर्माण कार्य प्रगति में है।
3. 10 थानों में महिला सिपाहियो के लिए 5 सीटेड शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य प्रगति में है।
4. 5 पुलिस लाईन/बी0 एम0 पी0 में महिला सिपाहियों के लिए 20 सीटेड शौचालय सह स्नानागार का निर्माण कार्य प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 का कार्य-योजना

❖ **भू-अर्जन**

1. बिहार सैन्य पुलिस-1, पटना के निर्माण हेतु दीघा में भू-अर्जन ।
2. जमुई में बिहार सैन्य पुलिस-11 हेतु भू-अर्जन (13.45 करोड़) ।
3. गोपालगंज पुलिस लाईन (27.29 करोड़), अररिया एवं मधेपुरा पुलिस लाईन हेतु भू-अर्जन ।
4. कुल 171 भूमिहीन पुलिस थानों हेतु भू-अर्जन ।
5. जमुई जिलान्तर्गत मलयपुर, गिद्धौर एवं चन्द्रदीप पुलिस थानों हेतु भू-अर्जन में अतिरिक्त राशि ।

❖ **ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं पुलिस आधुनिकीकरण**

1. सभी थानों में सी.सी.टी.वी. स्थापना हेतु शेष कार्य ।
2. 40 अदद मोबाईल फॉरेंसिंग वाहन का क्रय ।
3. सार्वजनिक स्थलों पर सी.सी.टी.भी. कैमरों का अधिष्ठापन ।
4. अभियान हेतु हेलिकॉप्टर लीज का प्रस्ताव ।
5. ई-चालान एवं स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ।
6. महिला सुरक्षा हेतु मोबाईल ऐप ।
7. नव-निर्मित क्षेत्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर हेतु उपकरणों का क्रय ।
8. प्रत्येक जिला में आधुनिक नियंत्रण कक्ष ।
9. अपराध अनुसंधान विभाग हेतु Automated Finger Print Identification System की स्थापना ।
10. सुरक्षा उपकरण (यथा-Bomb Disposal Items, GPS, NLJD, DFMD, HHMD) , एवं वाहन मिनी/बड़ा बस, ट्रक, कैदी वाहन, छोटा बज्र वाहन का क्रय ।
11. सी.सी.टी.एन.एस. योजना पर अग्रतर कार्रवाई एवं सिस्टम इन्टीग्रेशन ।

❖ भवन निर्माण

1. सी.आर.पी.एफ. हेतु कोईलवर में भवन निर्माण की शेष राशि (10.90 करोड़) ।
2. एस.एस.बी. जवान हेतु जमुई में आवास निर्माण की शेष राशि (3.98 करोड़) ।
3. रेल पुलिस महिला हेतु भवन निर्माण की शेष राशि (7.01 करोड़) ।
4. पटना पुलिस केन्द्र का निर्माण कार्य (242.52 करोड़) ।
5. शेखपुरा एवं किशनगंज पुलिस केन्द्र का निर्माण कार्य ।
6. महिलाओं हेतु प्रशिक्षण संरचना एवं सामर्थ्य विकास हेतु निर्माण कार्य (100.68 करोड़) ।
7. राजगीर पुलिस अकादमी का निर्माण कार्य ।
8. बिहार पुलिस मुख्यालय का निर्माण कार्य ।
9. भूमियुक्त थाना/ओ.पी. के भवन निर्माण का कार्य (49.00 करोड़) ।
10. बिहार सैन्य पुलिस-15 का निर्माण कार्य (बिहार सैन्य पुलिस-12 परिसर में)
11. अन्य जिन थानों/ओ.पी. की भूमि प्राप्त होती है, उनका निर्माण कार्य।

❖ <u>निकट भविष्य में शुरू किये जाने वाले कार्य :-</u>

1. 437 थाना भवनों में सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना के अन्तर्गत साईट तैयार करने का कार्य
2. 30 थाना भवनों का निर्माण
3. पुलिस उप-महानिरीक्षक आवास पश्चिमी चम्पारण
4. आर्थिक अपराध थाना